नई दिल्ली। शनिवार, 08 अगस्त, 2026
श्रावण कृष्ण पक्ष दशमी, सिद्धार्थि संवत्सर विक्रम संवत 2083
वर्ष : 12, अंक : 214 / मूल्य 3.00 रुपए। पृष्ठ 12

दैनिक
विश्व केसरी
सिर्फ पत्रकारिता...
नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ से एक साथ प्रकाशित
vishwakesari.com
@vishwakesariTV
@vishwakesari
vishwa_kesari_official
@VishwaKesari

@ खेल चेस : आर प्रज्ञानानंद ने जीता सेंट लुइस रैपिड...
@ विचार कांवड़ यात्रा : आस्था से आगे, वैज्ञानिक जीवनशैली...
@ व्यापार पश्चिम एशिया में तनाव के चलते लाल हुआ बाजार...

ई20 पेट्रोल वाहनों के लिए पूरी तरह सुरक्षित : सरकार

व्यापक परीक्षणों के बाद हुई पुष्टि

एजेंसी ■ नई दिल्ली

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को संसद को बताया कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों, वाहन निर्माताओं और उद्योग संगठनों द्वारा किए गए व्यापक प्रयोगशाला परीक्षणों और वास्तविक परिस्थितियों में हुए परीक्षणों के बाद यह पुष्टि हुई है कि निर्धारित मानकों के तहत ई20 पेट्रोल वाहनों के लिए पूरी तरह सुरक्षित है।

संसद में एक लिखित उत्तर में भारी उद्योग मंत्रालय ने कहा कि ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई), सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम), इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) तथा विभिन्न वाहन निर्माताओं ने संयुक्त रूप से ई20 ईंधन पर विस्तृत परीक्षण किए।

मंत्रालय ने आगे कहा कि इन परीक्षणों के दौरान इंजन की मजबूती, वाहन की संचालन क्षमता, ठंडे मौसम में इंजन स्टार्ट होने की क्षमता, जंग प्रतिरोध, विभिन्न पुर्जों के साथ ईंधन की अनुकूलता, ईंधन प्रणाली की विश्वसनीयता, उत्सर्जन स्तर और ईंधन दक्षता जैसे सभी महत्वपूर्ण पहलुओं का वैज्ञानिक मूल्यांकन किया गया।

इन सभी अध्ययनों के परिणामों से यह स्पष्ट हुआ कि निर्धारित मानकों के अनुसार ई20 पेट्रोल का उपयोग पूरी तरह सुरक्षित है और इससे वाहनों के प्रदर्शन या टिकाऊपन पर कोई महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता।

भारी उद्योग मंत्रालय ने बताया कि 26 दिसंबर 2020 को नीति आयोग के तहत एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने वाहनों की ई20 ईंधन के साथ अनुकूलता, माइलेज और ईंधन दक्षता से जुड़े सभी पहलुओं की व्यापक समीक्षा की थी। इस मूल्यांकन को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया और सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स द्वारा किए गए शोध का भी पूरा समर्थन मिला।

मंत्रालय ने कहा कि ई20 ईंधन के वैज्ञानिक परीक्षण और चरणबद्ध क्रियान्वयन की पूरी प्रक्रिया में वाहन निर्माता कंपनियां, ऑटोमोबाइल कलपुर्जा निर्माता, एसआईएएम, एआरएआई, परीक्षण एजेंसियां और तेल विपणन कंपनियां सक्रिय रूप से शामिल रहीं।

सरकार के अनुसार, ई20 ईंधन को लागू करने से पहले ईंधन प्रणाली, इंजन की मजबूती, वाहन संचालन क्षमता, विभिन्न पुर्जों के साथ ईंधन की अनुकूलता तथा उत्सर्जन प्रदर्शन का सफलतापूर्वक सत्यापन किया गया था।

मंत्रालय ने संसद को बताया कि परीक्षणों के दौरान निर्धारित परिचालन परिस्थितियों में पुराने वाहनों पर भी ई20 पेट्रोल के उपयोग से प्रदर्शन, इंजन की टिकाऊ क्षमता या वाहन के पुर्जों की अनुकूलता पर कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव सामने नहीं आया।

हूती विद्रोहियों का यमन और सऊदी अरब पर हमला

तेहरान। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने गुरुवार को सऊदी अरब और यमन में एक साथ बड़े हमले किए। पहला हमला यमन सरकार के मिलिट्री ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हुआ, जिसमें 58 सैनिकों की मौत हुई और दर्जनों घायल हो गए। यमन के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि सही समय और सही जगह पर जवाब दिया जाएगा। दूसरा हमला सऊदी के नजरान में हुआ, जिसमें 11 नागरिक घायल हुए। इनमें 7 सऊदी, एक यमनी, दो मिस्री, एक पाकिस्तानी नागरिक है। वहीं, एक 4 साल का एक बच्चा भी घायल हुआ है। हमलों के बाद नजरान के कई हिस्सों में आग लग गई।

ईरान के एक सांसद ने दावा किया है कि होर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच ओमान के जरिए बातचीत चल रही है। उनके मुताबिक, अमेरिका सीधे बातचीत करने के बजाय ओमान को मध्यस्थ बनाकर आगे कर रहा है। सांसद अहमद बख्शायेश अर्देस्तानी ने कहा कि प्रस्ताव के तहत होर्मुज स्ट्रेट का प्रबंधन ईरान के हाथ में होगा। वहां से गुजरने वाले जहाजों से माल की कीमत का 7% टैक्स लिया जाएगा, जिसमें 75% हिस्सा ईरान और 25% हिस्सा ओमान को मिलेगा। यह दावा ऐसे समय आया है जब होर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा और समुद्री व्यापार पूरी दुनिया, खासकर भारत जैसे तेल आयातक देशों के लिए बेहद अहम मुद्दा बना हुआ है।

सरकार और छात्रों के बीच सकारात्मक वार्ता अंतिम समझौते तक सत्याग्रह रहेगा जारी

एजेंसी ■ रांची

झारखंड में जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ 14 दिनों से चल रहे छात्र आंदोलन के बीच शुक्रवार शाम को राज्य सरकार और छात्रों के एक प्रतिनिधिमंडल के बीच पहली औपचारिक वार्ता हुई।

मोरहाबादी स्थित राजकीय अतिथिशाला में हुई बैठक करीब डेढ़ घंटे चली, जो रात 9.25 बजे खत्म हुई। छात्र प्रतिनिधियों ने बातचीत को सकारात्मक बताया। हालांकि, बातचीत अंतिम समझौते पर नहीं पहुंची है। छात्रों ने अंतिम रूप से समझौता होने और अपनी मांगें पूरी होने तक सत्याग्रह जारी रखने का निर्णय लिया है।

सरकार की पांच सदस्यीय टीम और छात्रों के 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के बीच आमने-सामने बातचीत हुई। छात्रों ने अपनी मांगों का एक-एक बिंदु सरकार के सामने रखा। उन्होंने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग दोहराई। छात्रों ने कहा कि वे ठोस कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं।

वार्ता में सरकार की ओर से चार मंत्री शामिल हुए। इनमें चमरा लिंडा, सुदिव्य कुमार सोनू, दीपिका पांडेय सिंह और संजय प्रसाद यादव शामिल थे। विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह भी बैठक में मौजूद रहे।

छात्र प्रतिनिधिमंडल में रवींद्र पासवान, पीयूष कुमार, राजेश प्रसाद, नीतू कुजूर, अंकित राज, कार्तिक सोरेन, शालू कुमारी, रवींद्र कुमार रवि, आनंद कुमार और अंकित कुमार शामिल थे।

मंत्रियों ने छात्रों की मांगों पर कहा कि सरकार छात्रों के एक-एक मुद्दे के समाधान की दिशा में सकारात्मक कदम उठाएगी। माना जा रहा है कि सरकार के चार मंत्रियों की कमेटी मुख्यमंत्री को छात्रों की मांगों से अवगत कराएगी। जल्द ही दूसरे दौर की वार्ता हो सकती है। वार्ता से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा परिसर में कहा कि सरकार छात्रों की समस्याओं को लेकर संवेदनशील है। सरकार छात्रों की हर बात सुनने को तैयार है। बातचीत के जरिए समाधान निकाला जा सकता है। छात्रों के सवाल, सुझाव और जिज्ञासाएं खुलकर सामने आनी चाहिए। उनके सुझावों का सरकार स्वागत करेगी। उन्होंने कहा कि युवाओं की भागीदारी से भर्ती और शिक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार किए जा सकते हैं। संवाद किसी एक स्थान या सीमित समूह तक नहीं रहना चाहिए। राज्य के सभी छात्र अपनी राय रखें। उनके विचारों के आधार पर सरकार सुधार की दिशा में आगे बढ़ना चाहती है।

इससे पहले गुरुवार को सरकार और छात्रों के बीच प्रतिनिधिमंडल को लेकर गतिरोध था। सरकार ने केवल छात्रों से बातचीत की शर्त रखी थी। इसके बाद छात्रों ने अपना प्रतिनिधिमंडल बदलकर नई सूची सरकार को सौंपी।

एफसीआरए हमारा आंतरिक मामला, बाहरी टिप्पणी स्वीकार नहीं : विदेश मंत्रालय

एजेंसी ■ नई दिल्ली

भारत ने 'फॉरेन कॉन्ट्रिब्यूशन (रेगुलेशन) एक्ट अमेंडमेंट बिल (एफसीआरए)' पर शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय समुदाय के कुछ वर्गों की टिप्पणियों को खारिज कर दिया, जिनमें एक अमेरिकी सांसद भी शामिल हैं। भारत ने कहा कि देश से जुड़े विधायी मामले हमारे आंतरिक विषय हैं और इन पर निर्णय भारत की संसद की ओर से लिए जाते हैं।

शुक्रवार को नई दिल्ली में आयोजित विदेश मंत्रालय (एमईए) की नियमित मीडिया ब्रीफिंग के दौरान मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अमेरिका सहित कई देश विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए नियम बनाते हैं। उन्होंने मीडिया के सवाल के जवाब में कहा, 'हमने इन टिप्पणियों को देखा है। भारत से जुड़े विधायी मामले हमारे आंतरिक विषय हैं, जिन पर निर्णय हमारे देश की संसद की ओर से लिए जाते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि अमेरिका सहित कई देश विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं।'

हाल ही में अमेरिकी सांसद राइली मूर ने भारत में विदेशी चंदे और दान से जुड़े कानूनों में प्रस्तावित संशोधनों पर टिप्पणी की थी। केंद्र सरकार संसद के मौजूदा मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में एफसीआरए संशोधन विधेयक पेश कर सकती है। सरकार के 22 जुलाई को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, वैश्विक वित्तीय नेटवर्क, डिजिटल लेनदेन और सीमा-पार फंडिंग व्यवस्थाओं के तेजी से बढ़ने से वित्तीय पारदर्शिता, विदेशी प्रभाव और लोकतांत्रिक संस्थाओं की सुरक्षा से जुड़ी नई चुनौतियां सामने आई हैं। इसी कारण कई लोकतांत्रिक देशों में विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करना सुशासन का एक सामान्य और स्वीकार्य हिस्सा बन गया है। सरकार का कहना है कि एफसीआरए को इसी व्यापक अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में समझा जाना चाहिए। यह कानून वैध और वास्तविक सामाजिक या परोपकारी गतिविधियों को रोकने के लिए नहीं है। बल्कि इसका उद्देश्य ऐसा कानूनी ढांचा उपलब्ध कराना है, जिससे अंतरराष्ट्रीय सहयोग जारी रह सके और विदेशी योगदान भारतीय कानूनों के अनुसार प्राप्त, उपयोग और दर्ज किए जा सकें।

एफसीआरए वह कानून है जो यह तय करता है कि भारत के व्यक्ति, संगठन, गैर-सरकारी संस्थाएं (एनजीओ), ट्रस्ट और कंपनियां विदेशों से मिलने वाले धन, प्रतिभूतियों या अन्य वस्तुओं को किस तरह प्राप्त और उपयोग कर सकती हैं। इसका संचालन गृह मंत्रालय करता है। एफसीआरए तीन मुख्य काम करता है। यह तय करता है कि कौन विदेशी योगदान स्वीकार कर सकता है और किन शर्तों पर। यह निर्धारित करता है कि उस धनराशि को कैसे प्राप्त किया जाए, उसका हिसाब-किताब कैसे रखा जाए और उसकी रिपोर्ट कैसे दी जाए।

हथकरघा क्षेत्र के सतत विकास के लिए नई प्रौद्योगिकियां उचित : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु

एजेंसी ■ नई दिल्ली

भारत की राष्ट्रपति, द्रौपदी मुर्मु राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र, नई दिल्ली में आयोजित 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह में शामिल हुईं और संत कबीर हथकरघा पुरस्कार तथा राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 प्रदान किए। इस अवसर पर भारत की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपराओं के सम्मान में चार स्मारक डाक टिकट भी जारी किए गए।

समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि हथकरघा सदियों से भारत की सभ्यता की विकास यात्रा का अभिन्न अंग रहा है। इसमें हमारे राष्ट्र की असाधारण विविधता दिखाई देती है और इसने हमारी क्षेत्रीय विशिष्टताओं को संरक्षित भी किया है। हथकरघा क्षेत्र से रोजगार, महिला सशक्तीकरण, कला-संस्कृति और प्रकृति-प्रेम को बढ़ावा मिलता है। हथकरघा भारत के स्वतंत्रता संग्राम और आत्मनिर्भरता से भी जुड़ा रहा है।

राष्ट्रपति ने कहा कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 को हुई थी। बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुए इस आंदोलन का उद्देश्य स्वदेशी वस्तुओं, स्वदेशी उद्योगों और विशेष रूप से देश के हथकरघा बुनकरों को प्रोत्साहन देना था। इसी ऐतिहासिक घटना के सम्मान में भारत सरकार वर्ष 2015 से, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाती आ रही है। उन्होंने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर हथकरघा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह आयोजन हमारे देश की विविधता का उत्सव है जो हमारी सांस्कृतिक एकात्मता को परिलक्षित करता है। यह सरकार और बुनकर समाज के उन साझे प्रयासों को याद करने का अवसर है जो भारत के हथकरघा क्षेत्र की एक प्रीमियम क्वालिटी छवि बना रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे हथकरघा क्षेत्र की, भारत की ग्रामीण प्रीमियम अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख, मानव-केंद्रित उदाहरण बनने की संभावनाएं बहुत बलवती हुई हैं। महत्वपूर्ण हथकरघा क्लस्टरों को आधुनिक प्रौद्योगिकी और आधुनिक प्रशिक्षण विधियों से जोड़ा जा रहा है। सरकार बुनकरों की आय बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठा रही है। उन्होंने यह जानकर प्रशंसा व्यक्त की कि सरकार के प्रयासों से भारतीय हथकरघा क्षेत्र की अंतरराष्ट्रीय छवि निखर रही है और यह क्षेत्र एक 'प्रमाणित सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था' में परिवर्तित हो रहा है।

राष्ट्रपति ने कहा कि तकनीक और नवाचारी डिजाइनों के साथ अनेक प्रतिभाशाली युवा उद्यमी इस क्षेत्र में आ रहे हैं। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि सरकारी योजनाओं और संस्थानों द्वारा युवाओं को सक्रिय रूप से सहयोग और मार्गदर्शन दिया जाना चाहिए ताकि उनका उत्साह और कौशल इस क्षेत्र की दीर्घकालिक बहुआयामी सफलता सुनिश्चित कर सके। युवा उद्यमी, डिजाइनर्स और स्टार्टअप्स पारंपरिक शिल्प को आधुनिक ट्रेंड्स, ब्रांड्स और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं से जोड़कर इस क्षेत्र में नए अवसर उत्पन्न कर सकते हैं। उन्हें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान और बुनकर सेवा केंद्रों के तत्वावधान में डिजाइन संसाधन केंद्र युवाओं को इस क्षेत्र से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि इस क्षेत्र के सतत विकास के लिए नई प्रौद्योगिकी का उचित उपयोग आवश्यक है। आधुनिक डिजिटल समाधानों के माध्यम से बाजार तक पहुंच को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।

स्वतंत्रता सेनानियों ने गोलियां खाईं आप अंडों से डरती हैं : सुप्रीम कोर्ट

एजेंसी ■ नई दिल्ली

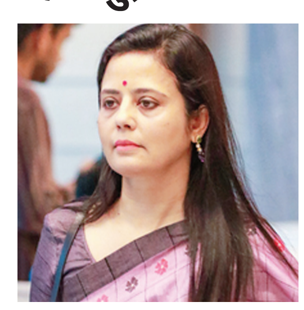

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद महुआ मोइत्रा की उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने कथित रूप से हिंसा भड़काने वाले सार्वजनिक बयानों से जुड़े मामले में जांच अधिकारी (आईओ) के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के बजाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने की अनुमति मांगी थी।

न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ ने मोइत्रा की इस मांग के आधार पर सवाल उठाते हुए संकेत दिया कि उन्हें जांच में व्यक्तिगत रूप से सहयोग करना होगा।

सुनवाई के दौरान महुआ मोइत्रा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि उनकी मुवक्किल को जांच में शामिल होने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जांच में शामिल होना चाहती हैं। इस पर न्यायमूर्ति दत्ता ने पूछा, 'वर्चुअली क्यों? सिर्फ इसलिए कि आप सांसद हैं?'

इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलील दी कि यदि मोइत्रा पुलिस स्टेशन में व्यक्तिगत रूप से पेश होती हैं तो उन्हें भीड़ के हमले की आशंका है। उन्होंने एक पुराने घटनाक्रम का भी हवाला दिया, जिसमें कथित तौर पर उन पर अंडे फेंके गए थे। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट इस दलील से संतुष्ट नहीं हुआ। पीठ ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा, 'आप सांसद हैं? राजनीति में आने के बाद आपको अंडों से डर लगता है? हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने तो सीने पर गोलियां खाई थीं। इस तरह की अर्जियां इस अदालत के सामने नहीं आनी चाहिए।'

सुप्रीम कोर्ट की इन टिप्पणियों के बाद मोइत्रा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी। इसके बाद शीर्ष अदालत ने याचिका को वापस लिया हुआ मानते हुए खारिज कर दिया।

'तिरंगा यात्रा' अभियान राष्ट्र निर्माताओं के योगदान को जानने में सहायक बनेगा : अरुण साव

बस्तर संभाग में 500 से अधिक स्कूलों, प्रमुख चौराहों और सामुदायिक भवनों का नामकरण शहीदों के नाम पर किया जाएगा : विजय शर्मा

संवाददाता ■ रायपुर

छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का 'हर घर तिरंगा' और 'तिरंगा यात्रा' अभियान देशभक्ति की लहर जगाने, सामाजिक समरसता को मजबूत करने और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व राष्ट्र निर्माताओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक भव्य और ऐतिहासिक माध्यम बनेगा। साव ने शुक्रवार को यहाँ एकात्म परिसर स्थित भाजपा कार्यालय में आहूत महती पत्रकार वार्ता को सम्बोधित करते हुए प्रदेशभर में आयोजित होने वाले 'हर घर तिरंगा' अभियान और 'तिरंगा यात्रा' की रूपरेखा साझा की।

प्रदेश के उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि बस्तर के वे नक्सल प्रभावित दुर्गम क्षेत्र, जहाँ अब तक राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया जा सका था, वहाँ इस वर्ष 15 अगस्त को तिरंगा लहराएगा। यह पूरे छत्तीसगढ़ के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। साव ने कहा कि वर्ष 2022 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 'हर घर तिरंगा' अभियान चलाया जा रहा है। इसका मूल उद्देश्य देश की युवा पीढ़ी को राष्ट्रभक्ति से जोड़ना, संवैधानिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना, सामाजिक समरसता तथा 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' की भावना को सुदृढ़ करना है।

इस दौरान प्रदेश की सभी 450 से अधिक भाजपा मण्डल इकाइयों, बड़े गाँवों, ग्राम पंचायतों, नगरीय निकायों और विकासखण्ड मुख्यालयों में जन-जागरण हेतु तिरंगा यात्राएँ निकाली जाएंगीं। साव ने बताया कि अभियान को सफल बनाने के लिए नगरीय निकायों, जिला पंचायतों और पार्टी पदाधिकारियों की वर्चुअल बैठक संपन्न हो चुकी है, साथ ही रायपुर शहर एवं ग्रामीण जिलों की बैठकें भी आयोजित की जा चुकी हैं।

आगामी 10 अगस्त को राजधानी के मरीन ड्राइव से तिरंगा यात्रा का ऐतिहासिक शुभारम्भ सुबह 10 बजे होगा। इस यात्रा में मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, सांसद, विधायक, स्कूल-कॉलेज के विद्यार्थी, एनसीसी कैडेट्स, स्काउट्स, पूर्व सैनिक, खिलाड़ी, स्वयंसेवी संस्थाएँ, धर्माचार्य और विभिन्न समाजों के विशिष्ट जन शामिल होंगे। यात्रा को यादगार बनाने के लिए लोग पारंपरिक वेशभूषा, वाद्य यंत्रों, घोड़ों और सवारियों के साथ शामिल होंगे।

थाईलैंड में नवमीं के छात्र ने 8 लोगों की हत्या की

एजेंसी ■ नई दिल्ली

थाईलैंड के एक स्कूल में एक छात्र ने शुक्रवार को ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस घटना में कम से कम एक शिक्षक की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। थाईलैंड के एक बड़े रेस्क्यू ग्रुप पोह टेक तुंग फाउंडेशन ने कहा कि शुरुआती रिपोर्ट से पता चला है कि दो लोग मारे गए हैं और 15 घायल हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर है। ऑफिसर इलाके से छात्रों को तुरंत निकाल रहे हैं बैंकॉक के उत्तर में नोंथबुरी प्रांत के बंग क्रुई जिले में एक व्यस्त हाईवे पर स्थित देबसिरिन नोंथबुरी स्कूल में फायरिंग हुई, जो लगभग 3,000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, नॉनथाबुरी प्रोविंशियल पुलिस कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल डेचरापी कोंगडी ने कहा कि संदिग्ध बंदूकधारी ने खुद को मार डाला। पुलिस ने अपराधी की पहचान एक स्टूडेंट के तौर पर की है। थाईलैंड के सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने अमेरिकी मीडिया सीएनएन को बताया कि हालात अब नियंत्रण में हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, घायलों में एक टीचर और तीन स्टूडेंट शामिल हैं। अमेरिकी मीडिया सीएनएन ने एक सत्यापित वीडियो के हवाले से बताया कि स्टूडेंट स्कूल से बाहर भागते हुए दिखे, जबकि एक स्टाफ मेंबर उन्हें निकालने में मदद कर रहा है।

सरकार छात्रों की आवाज दबा रही है, गृहमंत्री संसद में जवाब देने से बच रहे: प्रियंका गांधी

विश्व केसरी

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसदों ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार छात्रों की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है और केंद्रीय गृह मंत्री संसद में आकर जवाब देने से बच रहे हैं। साथ ही, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत के जेन जी को लेकर दिए गए बयान को लेकर भी कांग्रेस ने सरकार और संघ पर निशाना साधा है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने प्रयागराज में प्रस्तावित 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम को लेकर कहा कि सरकार इस कार्यक्रम से डर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कार्यक्रमों के साथ हमेशा ऐसा ही व्यवहार किया जाता है।

केंद्रीय गृहमंत्री के संसद में आने के सवाल पर प्रियंका गांधी ने कहा कि ऐसा नहीं लगता कि वे सदन में आएंगे। यदि कोई गलती हुई है तो सरकार को उसकी जिम्मेदारी लेते हुए संसद में जवाब देना चाहिए।

कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने भी गृह मंत्री की अनुपस्थिति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री लोकसभा और संसद से गायब हैं। वेणुगोपाल ने मांग की कि गृह मंत्री सदन में आकर स्पष्ट करें कि छात्रों पर पैलेट गन चलाने और आंसू गैस छोड़ने का आदेश किसने दिया। देश और छात्र दोनों इन सवालों के जवाब चाहते हैं। कांग्रेस ने इस संबंध में लोकसभा अध्यक्ष से संसदीय कार्य मंत्री को निर्देश देने का अनुरोध किया है, लेकिन अब तक गृह मंत्री सदन में उपस्थित नहीं हुए हैं, जबकि संसद सत्र के केवल चार दिन शेष हैं।

वहीं, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के जेन जी को लेकर दिए गए बयान पर कांग्रेस सांसद मणिक्कम टैगोर ने कहा कि आरएसएस इस समय बैकफुट पर है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 12 वर्षों में आरएसएस ने विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में प्रभाव स्थापित किया है तथा उससे जुड़े लोग विभिन्न पदों पर नियुक्त किए गए हैं। टैगोर के अनुसार, इसी कारण अब आरएसएस रक्षात्मक स्थिति में नजर आ रहा है। कांग्रेस सांसद अमर सिंह ने भी शिक्षा व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यदि मोहन भागवत कोई सुझाव देना चाहते हैं तो उन्हें सीधे केंद्र सरकार को देना चाहिए, क्योंकि पिछले 12 वर्षों से वही सत्ता में है। अमर सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार ने शिक्षा को महंगा बना दिया है, जिससे आम परिवारों के लिए बच्चों की पढ़ाई मुश्किल हो गई है। पढ़ाई पूरी करने के बाद युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। पिछले दस वर्षों में देशभर में लगभग एक लाख सरकारी स्कूल बंद हुए हैं, जो शिक्षा व्यवस्था की स्थिति को दर्शाता है। कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी कहा कि मोहन भागवत जो बातें कह रहे हैं, वही कांग्रेस लंबे समय से उठाती रही है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री को संसद में आकर छात्रों से जुड़े घटनाक्रम पर जवाब देना चाहिए।

रंधावा ने कहा कि प्रधानमंत्री की अपनी कार्यशैली हो सकती है, लेकिन कम से कम गृह मंत्री को सदन में उपस्थित होकर विपक्ष और देश के सवालों का सामना करना चाहिए। कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि वह छात्रों से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाबदेही की मांग आगे भी उठाती रहेगी।

असम बाढ़ : राहत और पुनर्वास कार्यों में तेजी के निर्देश 14 अगस्त तक पूरा होगा नुकसान का आकलन

विश्व केसरी

गुवाहाटी। असम में बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए राज्य सरकार ने राहत और पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव रवि कोटा ने शुक्रवार को राज्य के चार सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में चल रहे कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों से कहा कि नुकसान का आकलन, आर्थिक सहायता और आजीविका बहाल करने का काम समय पर पूरा किया जाए।

वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई जिला परामर्श समिति की उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव ने की। इस दौरान उन्होंने जोरहाट, शिवसागर, चराईदेव और गोलाघाट जिलों के अधिकारियों से बात कर राहत उपायों की प्रगति जानी और बाढ़ प्रभावित परिवारों को समय पर मदद पहुंचाने पर जोर दिया।

बैठक में जिला आयुक्त, बैंकों और बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि और विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हुए। चर्चा का मुख्य फोकस नुकसान के आकलन, वित्तीय सहायता और बीमा क्लेम निपटान में समन्वय बेहतर बनाने पर रहा। रवि कोटा ने कहा कि राहत कार्य में देरी न हो, इसके लिए कई एजेंसियों को साथ मिलकर काम करना होगा और रोजाना निगरानी जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों को संस्थागत समन्वय मजबूत करने और पुनर्वास में आ रही अड़चनों को दूर करने का निर्देश दिया।

बैठक में कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, आवास, एमएसएमई और अन्य आजीविका से जुड़े क्षेत्रों में हुए नुकसान की विस्तृत समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि फील्ड लेवल पर वेरिफिकेशन के साथ तकनीक आधारित और प्रमाणित नुकसान का आकलन 14 अगस्त तक पूरा कर लिया जाए। सेक्टर-वार रिपोर्ट 18 अगस्त से पहले संबंधित समितियों के सामने पेश की जाए, ताकि राहत और पुनर्वास की सहायता जल्द दी जा सके। बीमा से जुड़ी मदद आसान बनाने के लिए चारों जिलों में जिला-वार बीमा नोडल अधिकारी पहले ही नियुक्त किए जा चुके हैं। क्लेम प्रोसेसिंग पर नजर रखने और दिक्कतें दूर करने के लिए विशेष समीक्षा व्यवस्था भी बनाई गई है। मुख्य सचिव ने कहा कि जिन बाढ़ पीड़ितों के जरूरी कागजात खो गए हैं, उनके लिए दस्तावेजी प्रक्रिया सरल की जाए। जहां मूल रिकॉर्ड खराब या नष्ट हो गए हैं, वहां वैकल्पिक तरीके से सत्यापन की अनुमति दी जाए।

बैंकों को सलाह दी गई कि वे अगले दो हफ्तों में प्रभावित कर्जदारों से खुद संपर्क करें। उन्हें लोन मोरेटोरियम, मौजूदा लोन का पुनर्गठन, नया कर्ज और उपभोग ऋण जैसी राहत दी जाए ताकि परिवारों की तुरंत आर्थिक जरूरतें पूरी हो सकें।

युवाओं को देश विरोधी क्यों कहा गया अमित शाह सदन में आकर जवाब दें : प्रियंका चतुर्वेदी

विश्व केसरी

नई दिल्ली। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के जेन-जी आंदोलन को लेकर दिए गए बयान पर शिवसेना (यूबीटी) नेता और पूर्व राज्यसभा सदस्य प्रियंका चतुर्वेदी ने शुक्रवार को कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बातें इशारों में नहीं, खुलकर और सीधे कही जानी चाहिए।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक मोहन भागवत ने हालिया छात्र आंदोलनों और जेन जी को लेकर गुरुवार को कहा था कि यदि जेन जी विरोध-प्रदर्शन कर रही है तो उन्हें 'देशविरोधी' नहीं कहा जाना चाहिए। यह देश की पीढ़ी है और उनके मुद्दों को संवाद के जरिए समझकर समाधान निकालने की जरूरत है। प्रियंका चतुर्वेदी ने आईएएनएस से कहा, 'क्यों इशारों में बात कर रहे हैं? खुलकर और साफ-साफ बोलना चाहिए। चूंकि वे खुद भारतीय जनता पार्टी की मुख्य नेता और मार्गदर्शक हैं, इसलिए उन्हें स्पष्ट रूप से कहना चाहिए कि भाजपा के राज्यसभा और लोकसभा सांसदों के साथ-साथ विधायकों ने बार-बार उन्हें देश विरोधी करार देने की कोशिश की।'

जेन जी की आवाज दबाने के बजाय केंद्र सरकार कुछ अच्छा काम करें, अरविंद केजरीवाल ने दी सलाह

विश्व केसरी

नई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार देश के युवाओं से डरी हुई है और इसीलिए उनकी आवाज दबाने के लिए नए-नए तरीके अपना रही है।

आप के राष्ट्रीय संयोजक ने एक वीडियो ब्लॉग में सरकार को सलाह भी दी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि वे देश के युवाओं की आवाज दबाने के बजाय रचनात्मक और उल्लेखनीय कामों पर ध्यान दें।

केजरीवाल ने दावा किया कि केंद्र सरकार एक नया कानून लाई है, जिसके तहत सरकार के कामकाज की आलोचना या असहमति जताने वाली किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट या वीडियो को सरकार के कहने पर हटा दिया जाएगा। उन्होंने वीडियो में दावा किया, 'केंद्र सरकार एक नया कानून लाई है। अगर सरकार किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कोई पोस्ट, लेख या वीडियो हटाने के लिए कहती है, तो उन्हें इसे 3 घंटे के भीतर हटाना होगा। इसका मतलब है कि अगर आप पेपर लीक, इथेनॉल ब्लेंडिंग और सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो आपकी पोस्ट कुछ ही घंटों में हटा दी जाएगी।'

केजरीवाल ने कहा, 'सत्ता में बैठे लोगों को लगता है कि उन्हें युवा छात्रों के साथ बुरा बर्ताव करने, उनका अपमान करने और उन्हें परेशान करने का हक है और इसके लिए उनसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। यह देश के युवाओं की आवाज को दबाने और उन्हें चुप कराने की एक साफ कोशिश है।'

उन्होंने कहा कि जंतर-मंतर पर हुआ विरोध प्रदर्शन लोगों के उस गुस्से का नतीजा है जो पिछले दस साल से जमा हो रहा था।

केजरीवाल ने कहा कि छात्रों के साथ बुरा बर्ताव किया गया, महिलाओं का अपमान किया गया और उन्हें अपना विरोध जताने से रोका गया। यह सही तरीका नहीं है।

प्रधानमंत्री को सीधे सलाह देते हुए केजरीवाल ने कहा, 'लोगों को डराने और उनकी आवाज को दबाने के बजाय आपको अच्छे काम करने चाहिए, लोग आपकी तारीफ करने लगेंगे।' उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने अपना रवैया नहीं बदला तो युवाओं में गुस्सा और बढ़ता जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी, 'आप देश के युवाओं की आवाज को जितना दबाएंगे, उनका गुस्सा उतना ही बढ़ेगा।'

कांग्रेस ने की आरोपी के लिए फास्ट-ट्रैक ट्रायल और कड़ी सजा की मांग

विश्व केसरी

भोपाल/नरसिंहपुर। मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता उमंग सिंघार ने शुक्रवार को नरसिंहपुर जिले में 8 साल की बच्ची के कथित रेप और हत्या मामले में गिरफ्तार आरोपी के लिए फास्ट-ट्रैक ट्रायल और सबसे कड़ी सजा की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में नाकाम रही है।

घटना की निंदा करते हुए उमंग सिंघार ने कहा कि आठ साल की मासूम बच्ची का अपहरण, रेप और बेरहमी से हत्या बेहद दुखद है। इस घटना ने पूरे मध्य प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। कांग्रेस नेता ने मांग की कि इस मामले की सुनवाई फास्ट-ट्रैक कोर्ट में हो और आरोपी को सबसे कड़ी सजा दी जाए। उन्होंने पीड़ित परिवार के लिए न्याय, आर्थिक मदद और हर संभव सहयोग की भी मांग की। सिंघार ने कहा, 'खोखले भाषणों और दावों से बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती। इसके लिए मजबूत कानून-व्यवस्था, त्वरित न्याय और जवाबदेह सरकार की जरूरत है।' वहीं, नरसिंहपुर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) ऋषिकेश मीणा ने कहा कि जांच तेजी से चल रही है।

शास्त्री नगर में दलदली नाले में फंसा व्यक्ति, दमकल टीम ने रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाला

विश्व केसरी

गाजियाबाद। गाजियाबाद में शुक्रवार को अग्निशमन एवं आपात सेवा की तत्परता और सूझबूझ के चलते एक बड़ा हादसा टल गया। शास्त्री नगर स्थित एक गहरे और गंदे नाले के दलदल में फंसे एक व्यक्ति को फायर विभाग की टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाकर सुरक्षित बाहर निकाल लिया। समय पर मिली सूचना और त्वरित कार्रवाई के कारण व्यक्ति की जान बच गई।

जानकारी के अनुसार, कमिश्नरेट गाजियाबाद के फायर स्टेशन कोतवाली को सुबह 10:11 बजे सूचना प्राप्त हुई कि आई ब्लॉक, शास्त्री नगर स्थित एक गहरे नाले में एक व्यक्ति दलदल में फंस गया है और स्वयं बाहर निकलने में असमर्थ है।

सूचना मिलते ही अग्निशमन अधिकारी कोतवाली के नेतृत्व में फायर स्टेशन कोतवाली से एक एफक्यूआरवी (फर्स्ट क्विक रिस्पांस व्हीकल) तथा फायर स्टेशन कविनगर से एक फायर टेंडर तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना किया गया। घटनास्थल पर पहुंची अग्निशमन टीम ने सबसे पहले मौके की स्थिति का बारीकी से निरीक्षण किया। नाले की गहराई, दलदल और गंदगी को देखते हुए रेस्क्यू अभियान चुनौतीपूर्ण था।

सदन के बाहर बैठकर इस तरह से तमाशा करने का कोई मतलब नहीं: हरभजन सिंह

विश्व केसरी

नई दिल्ली। टीम इंडिया के पूर्व गेंदबाज और राज्यसभा सदस्य हरभजन सिंह ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर नाश्ते पर मुलाकात की। हरभजन ने उस मुलाकात को बेहद यादगार और सकारात्मक बताया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी से काफी कुछ सीखने को मिलता है। हरभजन ने सदन की कार्यवाही लगातार स्थगित होने को लेकर भी नाराजगी जाहिर की।

हरभजन ने पत्रकारों के साथ बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मार्गदर्शन बताया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी से काफी कुछ सीखने को मिलता है। प्रधानमंत्री ने उनसे और बाकी सांसदों से मुलाकात और बातचीत की। प्रधानमंत्री के साथ रहने पर सकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है। विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार सदन के स्थगित होने को लेकर भी हरभजन ने बात की। उन्होंने कहा, 'सदन का न चलना मेरे हिसाब से किसी के लिए भी सही नहीं है। सदन में लोग इसलिए आते हैं कि वह अपनी और अपने राज्य की बात को रख सकें और अगर सदन चलेगा ही नहीं, तो किसी की भी बात नहीं रखी जा सकेगी।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने डॉक्टर से मारपीट मामले में रमेश म्हात्रे और अन्य आरोपियों को दी जमानत

विश्व केसरी

मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को डॉक्टरों और अस्पताल के स्टाफ के साथ कथित मारपीट के मामले में शिवसेना के पार्षद रमेश म्हात्रे और अन्य सभी आरोपियों को कड़ी शर्तों के साथ जमानत दे दी। हालांकि, हाईकोर्ट ने इस मामले को फास्ट-ट्रैक कोर्ट भेज दिया है। कल्याण कोर्ट मामले में आगे की सुनवाई करेगा।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवींद्र वी. घुगे और न्यायमूर्ति गौतम अंखाड की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के दौरान एक चुने हुए प्रतिनिधि पर लगे आरोपों के गंभीर नतीजों का जिक्र किया। कोर्ट ने कहा, 'चुना हुआ प्रतिनिधि जनता का प्रतिनिधि होता है। यह एक गंभीर मामला है, जब कोई चुना हुआ प्रतिनिधि जनता की सेवा करने वाले कर्मचारियों पर हमला करता है।'

इसके साथ ही, कोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री को सात दिनों के भीतर फास्ट-ट्रैक कोर्ट के लिए एक जज नियुक्त करने का भी निर्देश दिया। इसने वॉयस सैंपल और राज्य की फोरेंसिक लैब को 15 कामकाजी दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया।

पश्चिम एशिया संकट के बीच भारत आने वाले 62 जहाज होर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित निकले: केंद्रीय मंत्री

विश्व केसरी

नई दिल्ली। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने शुक्रवार को संसद को बताया कि खाड़ी क्षेत्र से 4,052 नाविकों को वापस लाया गया है और 3 अगस्त तक भारत आने वाले 62 जहाज होर्मुज स्ट्रेट से सफलतापूर्वक गुजर चुके हैं। इनमें से 23 भारतीय ध्वज वाले और 39 विदेशी ध्वज वाले जहाज थे।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति को देखते हुए, समुद्री प्रशासन महानिदेशालय (डीजीएमए) मध्य पूर्व संघर्ष के बीच भारतीय नाविकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए लगातार अपनी एडवायजरी अपडेट करता रहता है। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में मंत्री ने कहा कि व्यापारिक जहाजों पर नए सिरे से हो रहे हमलों के मद्देनजर, नौवहन महानिदेशालय ने पूर्ण अंतरराष्ट्रीय पोत और बंदरगाह सुविधा सुरक्षा (आईएसपीएस) कोड सुरक्षा उपायों को लागू करना अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही खाड़ी क्षेत्र से गुजरने वाली यात्राओं पर भारतीय नाविकों को तैनात न करने की सलाह दी है।

काला सागर में काम करने वाले भारतीय नाविकों को ले जाने वाले भारतीय और विदेशी ध्वज वाले जहाजों के लिए भी एक डीजीएमए एडवायजरी जारी की गई है, जिसमें अत्यधिक सावधानी बरतने, यात्रा-विशिष्ट सुरक्षा आकलन करने, सुरक्षा एडवायजरी का कड़ाई से पालन करने और घटनाओं की तत्काल रिपोर्ट करने को कहा गया है। इसके अलावा, बाब-अल-मंडेब स्ट्रेट, दक्षिणी लाल सागर और उससे सटे यमन के पानी में काम करने वाले जहाजों के लिए एक एडवायजरी जारी की गई है, जिसमें जहाज मालिकों और कप्तानों को अत्यधिक सावधानी बरतने, सुरक्षा घटनाक्रमों की निरंतर निगरानी करने और अतिरिक्त जोखिम न्यूनीकरण उपायों को लागू करने का निर्देश दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने होर्मुज स्ट्रेट में भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इनमें एक समर्पित 24×7 नियंत्रण कक्ष की स्थापना, जहाजों और चालक दल के लाइव डेटाबेस का रखरखाव और जहाजों की आवाजाही, भारतीय नाविकों, घटनाओं और हताहतों की निगरानी के लिए हर 24 घंटे में एक स्थिति रिपोर्ट जारी करना शामिल है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि डीजीएमए ने त्वरित रिपोर्टिंग और प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए समर्पित 24×7 समुद्री दुर्घटना रिपोर्टिंग, संकट प्रबंधन और नाविक शिकायत निवारण मॉड्यूल के साथ एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म भी विकसित किया है।

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर
(जोन क्रं - 2)
-:: शहीद स्मारक स्कूल भवन, फाफाडीह, रायपुर : : -
Email ID - rmczone2@gmail.com
पत्र क्र. /34033..../ न. पा. नि. जोन क्र. 2/2026
रायपुर, दिनांक 06-08-2026
इश्तिहार
नामांतरण प्र.क्र. 34033
वार्ड का नाम 13 - राजीव गांधी वार्ड
एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्ड 13 स्थित भवन / भूमि जिसका प्रॉपर्टी आई डी. RPR222H00029 जो की निगम अभिलेख श्री /श्रीमती **MR. AKHILESH JAIN** पिता/पति श्री श्रीमती **REKHCHAND JAIN** के नाम से दर्ज है जिसको श्री श्रीमती 01. श्री कपील कुमार खेतानी, 02. श्री विशाल कुमार खेतानी पिता/पति श्री श्रीमती पिता खुशाल भाई खेतानी ने मृत्यु प्रमाण पत्र, सह पत्र शपथ पत्र दान पत्र, हिब्बानामा, रजिस्ट्री विलेख के अनुसार / पंजीकृत विक्रय विलेख / वंशानुक्रम / अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत द्वारा आवेदन किया है। यदि कोई व्यक्ति / संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते है, प्रकाशन के 15 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा / प्रस्तुत करे। निर्धारित समयावधि पश्चात प्राप्त दावा। आपत्ति पर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की जाएगी। जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।
सूचना जारी करे ...
श्री संतोष पाण्डेय
(जोन कमिश्नर) जोन (2)
नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर
(जोन क्रं - 2)
-:: शहीद स्मारक स्कूल भवन, फाफाडीह, रायपुर : : -
Email ID - rmczone2@gmail.com
पत्र क्र. /34132..../ न. पा. नि. जोन क्र.2/2026
रायपुर, दिनांक 06-08-2026
इश्तिहार
नामांतरण प्र.क्र. 34132
वार्ड का नाम - 35 - हवलदार अब्दुल हमीद वार्ड
एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्ड 35 स्थित भवन / भूमि जिसका प्रॉपर्टी आई डी. RPR235J00074 जो की निगम अभिलेख श्री /श्रीमती DWARIKA PRASHAD पिता / पति श्री/ श्रीमती ... के नाम से दर्ज है जिसको श्री श्रीमती SMT. SHARDA DEVI पिता / पति श्री/श्रीमती **W/O LT. DWARIKA PRASAD PANDEY** ने मृत्यु प्रमाण पत्र, सह पत्र, शपथ पत्र, दान पत्र, हिब्बानामा, रजिस्ट्री विलेख के अनुसार। Shapath patr, sahmati patr, adhar card, mrityu praman patr, old ragistri / वंशानुक्रम / अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत द्वारा आवेदन किया है। यदि कोई व्यक्ति / संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते है, प्रकाशन के 15 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा प्रस्तुत करे। निर्धारित समयावधि पश्चात प्राप्त दावा। आपत्ति पर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की जाएगी। जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।
सूचना जारी करे ...
श्री संतोष पाण्डेय
(जोन कमिश्नर) जोन (2)
नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर
(जोन क्रं - 3)
-:: शंकर नगर पानी टंकी के नीचे, रायपुरः : -
Email ID - rmczone3@gmail.com
पत्र क्र. /34129..../ न. पा. नि. जोन क्र.3/2026
रायपुर, दिनांक 06-08-2026
इश्तिहार
नामांतरण प्र.क्र. 34129
वार्ड का नाम 30- शंकर नगर वार्ड
एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्ड 30 स्थित भवन / भूमि जिसका प्रॉपर्टी आई डी. **RPR**331**B**00110 जो की निगम अभिलेख श्री / श्रीमती **BHUVAN LAL SAHU, HARISH KUMAR SAHU** पिता पति श्री /श्रीमती **LT. PREM LAL SAHU** के नाम से दर्ज है जिसको श्री / श्रीमती **SRI BHUVAN LAL SAHU** पिता / पति /श्री श्रीमती **S/O LT. PREM LAL SAHU** ने मृत्यु प्रमाण पत्र, सह पत्र, शपथ पत्र, दान पत्र, हिब्बानामा, रजिस्ट्री विलेख के अनुसार / पंजीकृत बंटवारानामा / वंशानुक्रम । अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत द्वारा आवेदन किया है। यदि कोई व्यक्ति / संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते है, प्रकाशन के 15 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा / प्रस्तुत करे। निर्धारित समयावधि पश्चात प्राप्त दावा। आपत्ति पर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की जाएगी। जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।
सूचना जारी करे ...
श्रीमती प्रीति सिंह
(जोन कमिश्नर) जोन (3)
नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर
(जोन क्रं - 9)
-:: पुलिस थाना के पास, दुबे कॉलोनी, मोवा, रायपुरः : -
Email ID - rmczone9@gmail.com
पत्र क्र. /34043..../ न. पा. नि. जोन क्र. 9/2026
रायपुर, दिनांक 06-08-2026
इश्तिहार
नामंतरण प्र.क्र. 34043
वार्ड का नाम - 32 - महर्षि वाल्मीकि वार्ड
एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्ड 32 स्थित भवन / भूमि जिसका प्रॉपर्टी आई. डी. **RP R328T00248** जो की निगम अभिलेख श्री श्रीमती **SARITA JAISWAL** पिता/पति श्री श्रीमती **GIRDHARI LAL JAISWAL** के नाम से दर्ज है जिसको श्री/श्रीमती शिवानी रॉबिन पिता/पति श्री श्रीमती रॉबिन शाहू ने मृत्यु प्रमाण पत्र, सह पत्र शपथ पत्र दान पत्र, हिब्बानामा, रजिस्ट्री विलेख के अनुसार / पंजीकृत विक्रय विलेख वंशानुक्रम / अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत द्वारा आवेदन किया है। यदि कोई व्यक्ति / संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते है, प्रकाशन के 15 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा / प्रस्तुत करे । निर्धारित समयावधि पश्चात प्राप्त दावा / आपत्ति पर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की जाएगी। जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।
सूचना जारी करे
श्री राकेश शर्मा
(जोन कमिश्नर)जोन (9)
नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर
(जोन क्रं - 9)
-:: पुलिस थाना के पास, दुबे कॉलोनी, मोवा, रायपुरः : -
Email ID - rmczone9@gmail.com
पत्र क्र. /34044..../ न. पा. नि. जोन क्र. 9/2026
रायपुर, दिनांक 06-08-2026
इश्तिहार
नामंतरण प्र.क्र. 34044
वार्ड का नाम - 32 - महर्षि वाल्मीकि वार्ड
एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्ड 32 स्थित भवन / भूमि जिसका प्रॉपर्टी आई डी. **RP R328P00065** जो की निगम अभिलेख श्री श्रीमती **YUSUF SHARIF** पिता/पति श्री श्रीमती **DAWUD SHARIF** के नाम से दर्ज है जिसको श्री **गगन चोपड़ा** पिता / पति श्री **सुदर्शन चोपड़ा** ने मृत्यु प्रमाण पत्र सह पत्र, शपथ पत्र दान पत्र, हिब्बानामा, रजिस्ट्री विलेख के अनुसार / पंजीकृत विक्रय विलेख वंशानुक्रम / अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत द्वारा आवेदन किया है। यदि कोई व्यक्ति / संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते है, प्रकाशन के 15 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा प्रस्तुत करे । निर्धारित समयावधि पश्चात प्राप्त दावा / आपत्ति पर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की जाएगी। जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।
सूचना जारी करे
श्री राकेश शर्मा
(जोन कमिश्नर) जोन (9)
नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

सीएम की सख्त मॉनिटरिंग, अब अधिकारियों की जवाबदेही तय

विश्व केसरी

रायपुर। छत्तीसगढ़ में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की अब हर महीने मुख्यमंत्री स्तर पर समीक्षा होगी। राज्य सरकार ने परियोजनाओं की निगरानी के लिए Project Assessment, Review and Analysis System (पारस) को प्रभावी निगरानी प्रणाली के रूप में लागू किया है।

इसके जरिए जिलों की परफॉर्मेंस की रैंकिंग तैयार की जाएगी और जिन योजनाओं का लाभ समय पर लोगों तक नहीं पहुंचेगा या जिनके क्रियान्वयन में लापरवाही मिलेगी, उनके लिए संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी।

हर महीने होगी राज्यस्तरीय समीक्षा

मुख्यमंत्री ने गुरुवार को मंत्रालय महानदी भवन में पारख पोर्टल के जरिए राज्यस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, सुबोध सिंह, देवेंद्र यादव, राकेश चतुर्वेदी, राहुल शर्मा, कमलेश सिंह,

अंकित आनंद, श्याम आंबेडकर सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि जिन विभागों की लापरवाही के कारण योजनाएं प्रभावित होंगी, उनके जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने समय–सीमा के भीतर लंबित मामलों के निराकरण पर विशेष जोर दिया।

समीक्षा के दौरान बताया गया कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 के संचालन के बाद अब तक 1.10 लाख से अधिक शिकायतें दर्ज की गई हैं। इनमें से 65 हजार से अधिक शिकायतों का निराकरण किया जा चुका है, जबकि करीब 55.29 प्रतिशत शिकायतकर्ताओं ने समाधान पर संतुष्टि जताई है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिन 27 विभागों में 721 अधिसूचित सेवाएं लोक सेवा गारंटी अधिनियम (पब्लिक सर्विस गारंटी) के तहत संचालित हैं, वहां लंबित मामलों का जल्द से जल्द निपटारा सुनिश्चित किया जाए।

हर पात्र किसान का होगा पंजीयन

मुख्यमंत्री ने एस्ट्रेक्ट पोर्टल के माध्यम से जन–निर्बंधित पोषण किसान योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि यह केवल धान खरीदी तक सीमित व्यवस्था नहीं है। इसका उद्देश्य किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना भी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिलों में विशेष अभियान चलाकर हर पात्र किसान का पंजीयन सुनिश्चित किया जाए, ताकि कोई भी पात्र किसान सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित होंगे।

मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए कि वे लंबित प्रकरणों की नियमित समीक्षा करें और तय समय–सीमा के भीतर उनका निराकरण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों को सरकारी सेवाओं के लिए अनावश्यक परेशानी न हो, इसके लिए जिला प्रशासन को जवाबदेही के साथ काम करना होगा।

नोकझोंक 'मानसिक क्रूरता' नहीं

तलाक के मामले में हाईकोर्ट की दो टूक

विश्व केसरी

बिलासपुर। तलाक के एक मामले में फैमिली कोर्ट द्वारा पति के पक्ष में दी गई तलाक की डिक्री को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने निरस्त कर दिया है। पति का दावा था कि पत्नी उसे सांवले रंग और प्राइवेट नौकरी को लेकर ताने दिया करती थी। फैमिली कोर्ट ने इसे क्रूरता मानते हुए तलाक मंजूर की थी। जिसे पत्नी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। मामले में जस्टिस प्रार्थ प्रतीम साहू और जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की डिवीजन बेंच ने कहा कि पत्नी लगातार वैवाहिक संबंध बनाए रखने का प्रयास करती रही, जबकि पति ने साथ रहने की दिशा में प्रयास नहीं किए।

बिलासपुर निवासी व्यक्ति की शादी दुर्ग की महिला से हुई थी। आपसी विवाद के बाद पति ने फैमिली कोर्ट में तलाक का केस लगाया, जिसमें पति ने अपनी पत्नी पर उसके सांवले रंग और प्राइवेट नौकरी को लेकर ताने देने का आरोप लगाया था। फैमिली कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद तलाक की डिक्री दी थी। फैमिली कोर्ट के आदेश को पत्नी ने हाई कोर्ट में यह कहते हुए चुनौती दी, कि उसने कभी वैवाहिक दायित्व निभाने से इनकार नहीं किया। वह सरकारी नौकरी में होने के कारण पदस्थापना वाली जगह पर रहने को मजबूर थी। पति और उसके परिवार ने दहेज की मांग करते हुए उसे प्रताड़ित किया। कोर्ट ने दांपत्य संबंधों की पुनर्स्थापना के आदेश दिए। मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि पति का यह आरोप भरोसे के लायक नहीं है कि पत्नी उसके सांवले रंग या निजी नौकरी के कारण उसे पसंद नहीं करती थी। दोनों पहले से एक–दूसरे को जानते थे और यदि ऐसा होता तो विवाह ही नहीं होता। सामाजिक बैठक में दोनों को एक–दूसरे के साथ रहने का अवसर देने की कोशिश की गई थी।

हाई कोर्ट ने कहा कि मानसिक क्रूरता का आधार केवल छोटे–मोटे वैवाहिक मतभेद या सामान्य नोकझोंक नहीं हो सकते।

नांदघाट-मुंगेली रोड होगा फोरलेन, राज्य शासन ने मंजूर किए 21.81 करोड़

विश्व केसरी

रायपुर। राज्य शासन ने बेमेतरा जिले के नांदघाट से मुंगेली जिला मुख्यालय तक टू–लेन सड़क के फोरलेन में उन्नयन के लिए 21 करोड़ 81 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। इस राशि से 36.40 किमी फोरलेन सड़क का निर्माण किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद राज्य शासन ने मंत्रालय से राशि स्वीकृति के संबंध में प्रमुख अभियंता को परिपत्र जारी कर दिया है।

उप मुख्यमंत्री साव ने कार्य में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्रियों एवं संपूर्ण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए हैं। किसी भी स्तर पर कार्य की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर उत्तरदायित्व का निर्धारण करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

लोक निर्माण विभाग ने प्रमुख अभियंता को कार्य की निविदा समय–सीमा में करने, निर्माण कार्य प्राक्कलन व कार्य संपादित करने में मितव्ययिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने निर्माण एजेंसी से अनुबंधित समय–सीमा में काम पूर्ण किया जाना सुनिश्चित कराने को कहा है। कार्य पूर्ण किये जाने के लिए अनावश्यक समय–सीमा वृद्धि नहीं किए जाने के भी निर्देश विभाग ने दिए हैं। अपरिहार्य एवं नियंत्रण से बाहर मान्य कारणों के आधार पर ही सक्षम अधिकारी द्वारा समय–सीमा में वृद्धि की जा सकेगी। निर्माण कार्य की समयावधि में वृद्धि नियमानुसार अर्थदंड सहित अधिरोपित करने के निर्देश दिए गए हैं।

सेवानिवृत्त प्राध्यापकों एवं वैज्ञानिकों के पेंशन प्रकरणों के निराकरण हेतु हर संभव प्रयास : कृषि विश्वविद्यालय प्रशासन

विश्व केसरी

रायपुर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा है कि विश्वविद्यालय द्वारा सेवानिवृत्त प्राध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों के पेंशन, ग्रेच्यूटी एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ दिलवाने के संबंध में सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने सेवानिवृत्त प्रध्यापकों द्वारा उनके लंबित पेंशन एवं ग्रेच्यूटी प्रकरणों तथा महंगाई भत्ते में वृद्धि एवं एरियर्स राशि की मांग को लेकर की जा रही हड़ताल के संबंध में स्पष्ट किया है कि विगत अवधि में सेवानिवृत्त 42 प्राध्यापकों/वैज्ञानिकों में से 15 प्राध्यापकों/वैज्ञानिकों को विश्वविद्यालय द्वारा 90 प्रतिशत पेंशन स्वीकृत कर इसका भुगतान किया जा रहा है। इसी प्रकार 15

अन्य लंबित पेंशन प्रकरणों को स्थानीय निधि संपरीक्षा, संचालनालय को सत्यापन हेतु भेजा गया है जिन पर स्वीकृति प्राप्त होते ही पेंशन का भुगतान शुरू किया जाएगा। 12 अन्य पेंशन प्रकरण स्वीकृति हेतु विचाराधीन हैं जिन पर त्वरीत कार्यवाही की जा रही है।

विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिन सेवानिवृत्त प्रध्यापकों/वैज्ञानिकों को 90 प्रतिशत पेंशन राशि प्रदान की जा रही है उनके नियुक्ति आदेश में उल्लेखित सेवा शर्तों एवं उनके परिपालन में व्याप्त विसंगतियों को दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालय के लेखानियंत्रक एवं स्थानीय निधि संपरीक्षा, संचालनालय द्वारा आपत्ति दर्ज की गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा उक्त प्रकरणों को मार्गदर्शन हेतु राज्य शासन को भेजा गया है और मानवीय आधार पर तात्कालिक कार्यवाही करते हुए अंतरिम राहत के रूप में 90 प्रतिशत पेंशन राशि का भुगतान किया जा रहा है। इसी प्रकार अन्य विसंगतिपूर्ण लंबित पेंशन प्रकरणों का भी तेजी से निराकरण किया जा रहा है तथा इनका निराकरण होने पर संबंधित प्रध्यापकों/वैज्ञानिकों को पेंशन का तत्काल भुगतान किया जाएगा।

विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा है कि विश्वविद्यालय में कार्यरत वैज्ञानिकों द्वारा उनकी सेवानिवृत्ति आयु प्रध्यापक संवर्ग की तरह ही 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष निर्धारित करने की मांग के संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा प्रबंध मंडल से इसे पारित कराकर राज्य शासन से मार्गदर्शन मांगा गया है जो कि अब तक अपेक्षित है। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा सेवानिवृत्त प्रध्यापकों/वैज्ञानिकों को देय पेंशन राशि में महंगाई भत्ते की दर 55 प्रतिशत से बढाकर 58 प्रतिशत किये जाने का आदेश प्रसारित कर दिया गया है।

खेती की लागत अध्ययन योजना के अतर्गत दो दिवसीय कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न

विश्व केसरी

रायपुर। आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय (डीईएस), कृषि, सहकारिता एवं कृषि कल्याण विभाग, कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ''भारत में प्रमुख फसलों की खेती के लागत अध्ययन की समग्र योजना (सी.एस.स्कीम)'' के अतंर्गत संचालनालय अनुसंधान सेवाएं, इं.गाँ.कृ.वि., रायपुर केंद्र में दिनांक 6 एवं 7 अगस्त, 2026 को दो दिवसीय कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ।

कार्यशाला का उद्घाटन संचालक अनुसंधान सेवाएं डॉ विवके कुमार त्रिपाठी की अध्यक्षता में योजना के मानद निर्देशक डॉ. प्रवीण कुमार वर्मा एवं प्रक्षेत्र अधिकारी डॉ. मुकेश कुमार सेठ की उपस्थिति में योजना में कार्यरत 24 कर्मचारियो को खेती की लागत संबंधी आँकड़े एकत्रण की कार्यशाला संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम खेती की लागत योजना में कार्यरत 15 क्षेत्रीय अमलों के अन्वेषकों हेतु उनके कौशल विकास एवं सुचारू जानकारी एकत्रण हेतु आयोजित किया गया। प्रशिक्षण का समापन आज दिनाँक 07.08.2026 को डॉ. धनंजय शर्मा, सह–संचालक अनुसंधान, डॉ. हेमंत पाणीग्राही सह–प्राध्यापक एवं डॉ. दीप्ती पटेल सह–प्राध्यापक, फल विज्ञान की उपस्थिती में प्रमाण पत्र वितरण कर सम्पन्न हुआ।

सैनिकों के सम्मान में बीएसपी विद्यार्थियों ने तैयार कीं 2500 राखियां

विश्व केसरी

रायपुर। देश की सीमाओं पर तैनात वीर सैनिकों के प्रति सम्मान, कृतज्ञता और राष्ट्रभक्ति की भावना को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से संचालित राष्ट्रव्यापी 'ऑपरेशन सिपाही रक्षा सूत्र–2026' अभियान के अंतर्गत भिलाई इस्पात संयंत्र के विद्यालयों के विद्यार्थियों ने लगभग 2500 राखियां तैयार कर सैनिकों को समर्पित कीं।

विद्यार्थियों ने श्रद्धा और स्नेह के साथ तैयार किए गए रक्षा सूत्रों के साथ सैनिकों के तिलक के लिए चुटकी भर पवित्र मिट्टी तथा उनके नाम सम्मान और शुभकामनाओं से युक्त संदेश–पत्र भी तैयार किए। इन रक्षा सूत्रों एवं अन्य सामग्री को देश की सीमाओं पर तैनात सैनिकों तक पहुंचाने के उद्देश्य से 5 अगस्त 2026 को अपराह्न 3 बजे स्काउट्स

एवं गाइड्स जिला संघ, भिलाई के तत्वावधान में घड़ी चौक, सुपेला में आयोजित कार्यक्रम के दौरान संग्रहण समूह को ससम्मान सौंपा गया। स्काउट्स एवं गाइड्स जिला संघ, भिलाई पिछले चार वर्षों से इस अभियान के माध्यम से रक्षा सूत्र देश की सीमाओं पर तैनात सैनिकों तक पहुंचा रहा है। अभियान का उद्देश्य विद्यार्थियों में राष्ट्रप्रेम, सामाजिक उत्तरदायित्व और सैनिकों के प्रति सम्मान की भावना को मजबूत करना है। विद्यार्थियों की इस पहल के माध्यम से देश की रक्षा में समर्पित जवानों के प्रति समाज की कृतज्ञता और भावनात्मक जुड़ाव का संदेश भी पहुंचाया जा रहा है। कार्यक्रम का आयोजन स्काउट्स एवं गाइड्स जिला संघ, भिलाई की जिला मुख्य आयुक्त एवं भिलाई इस्पात संयंत्र की महाप्रबंधक (शिक्षा–टीएसडी) शिखा दुबे के मार्गदर्शन में किया गया। इस अवसर पर स्काउट्स एवं गाइड्स जिला संघ के पदाधिकारी, विभिन्न विद्यालयों के प्राचार्य एवं शिक्षक, स्काउट्स, गाइड्स तथा बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित थे।

विधायक प्रतिनिधि नियुक्त हुए विजय साहू

विश्व केसरी

कसडोल। कसडोल के वरिष्ठ पत्रकार विजय साहू को विकास खण्ड शिक्षा विभाग का विधायक प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। नियुक्ति के उपरांत क्षेत्र में खुशी का माहौल है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं शुभचिंतकों ने उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएँ दीं।

विधायक संदीप साहू ने विजय साहू को नियुक्ति प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया तथा उनके उज्ज्वल कार्यकाल की शुभकामनाएँ दीं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग से जुड़े कार्यों में जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए बेहतर समन्वय स्थापित किया जाएगा।

विजय साहू वर्तमान में कसडोल के सक्रिय पत्रकार हैं और लंबे समय से सामाजिक एवं जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाते रहे हैं। उनकी नियुक्ति पर कसडोल विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए विश्वास जताया कि वे अपनी नई जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करेंगे।

बारनवापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अब भी व्यवस्थाओं की भारी कमी, पर्यटन चुनौतीपूर्ण

विश्व केसरी

कसडोल । छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध बारनवापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के सघन वनों के बीच बसा ग्राम पाढ़ादाह आज भी आधुनिक विकास की रोशनी से महरूम है। बिजली के खंभों और तारों का सपना देखकर अंधेरे से मुक्ति पाने की उम्मीद संजोए ग्रामीणों के साथ एक ऐसा छल हुआ है, जिसने पूरी प्रशासनिक व्यवस्था और स्थानीय राजनीति की नीयत पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

बिजली विस्तार के नाम पर एक स्थानीय राजनीतिक दल के पदाधिकारी द्वारा ग्रामीणों से कथित तौर पर 6 से 7 लाख रुपये ऐंठने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। भारी–भरकम राशि की वसूली के एक साल बीत जाने के बाद भी गांव की स्थिति जस की तस है— पाढ़ादाह आज भी पूरी तरह से अंधेरे के साए में डूबा हुआ है।

सपने बेचे, जमीन दांव पर लगवाई

सेंचुरी क्षेत्र के कड़े नियमों और पेचीदा प्रक्रियाओं के कारण पाढ़ादाह में बिजली पहुंचना एक बड़ी चुनौती रहा है। इसी लाचारी का फायदा उठाकर एक चतुर नेता ने ग्रामीणों को गांव–गांव, घर–घर जाकर बिजली सप्लाई और खंभे लगवाने का सपना दिखाया।

उजाले की आस में आर्थिक तंगी झेल रहे ग्रामीणों ने जैसे-तैसे पैसा जुटाना शुरू किया: प्रति परिवार योगदान: हर घर से 7,000 से 8,000 रुपये तक जुटाए गए।

सार्वजनिक संपत्ति की बलि: रकम पूरी करने के लिए गांव के फंड का पैसा तो इस्तेमाल हुआ ही, साथ ही 'बरदीहा डोली' नामक एक बहुमूल्य सार्वजनिक जमीन को भी दांव पर लगा दिया गया।

सालों से अंधेरे का दंश झेल रहे सीधे–सादे ग्रामीणों ने अपने भविष्य की खातिर अपनी मेहनत की कमाई और गांव की साझी विरासत उस नेता के हाथों में सौंप दी।

कौन सच्चा, कौन झूठा? दावों और आरोपों की जंग

सालों के लंबे इंतजार और नेताजी की गोलमोल बातों के बाद जब धरातल पर बिजली का एक तार तक नहीं बिछा, तब ग्रामीणों का सब्र टूट गया। अब यह मामला दावों और प्रति–दावों के बीच उलझकर रह गया है।

कानूनी कार्रवाई की तैयारी में आक्रोशित ग्रामीण

अंधेरे और ठगी के दोहरे दंश से पीड़ित पाढ़ादाह के ग्रामीण अब चुप बैठने के मूड में नहीं हैं। हालांकि, अब तक इस मामले में आधिकारिक तौर पर कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, लेकिन गांव में आक्रोश की लहर दौड़ रही है। एकजुट होकर ग्रामीण अब अपने पास मौजूद साक्ष्यों और बैंक लेन–देन/चंदे के विवरणों को एकत्रित कर रहे हैं। जल्द ही प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस स्टेशन में इस कथित वित्तीय अनियमितता के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराने की रणनीति बनाई जा रही है।

सुलगते सवाल: क्या लौटेगी रोशनी या डूबेगी गाढ़ी कमाई?

इस पूरे प्रकरण ने सेंचुरी क्षेत्र के विकास और राजनीतिक शुचिता की पोल खोलकर रख दी है।

सेंचुरी नियमों का पेच: जब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्षेत्र में विद्युत विस्तार के नियम बेहद कड़े हैं, तो किसी राजनीतिक व्यक्ति को इतनी बड़ी राशि एकत्र करने का अधिकार किसने दिया?

प्रशासन की चुप्पी: लाखों रुपये का लेन–देन हो गया और गांव की सार्वजनिक जमीन दांव पर लग गई, क्या स्थानीय प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी?

गाढ़ी कमाई का क्या होगा: क्या ग्रामीणों को उनका पैसा वापस मिलेगा या फिर विभाग नियम शिथिल करके गांव में सचमुच बिजली पहुंचाएगा?

वीआईपी रोड पर मलबा फेंकने पर कारोबारी पर 25 हजार का जुर्माना

विश्व केसरी

रायपुर। राजधानी रायपुर में सार्वजनिक स्थान पर निर्माण मलबा फेंकने के मामले में नगर निगम ने सख्त कार्रवाई की है। वीआईपी रोड स्थित बेबीलान टावर के पास मुख्य सड़क किनारे मलबा फेंके जाने की शिकायत सही पाए जाने पर नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने कारोबारी जसवीर सिंह खनूजा पर 25 हजार रुपये का ई–चालान जारी किया। निगम ने भविष्य में दोबारा ऐसी लापरवाही नहीं करने की चेतावनी भी दी है।

नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, मुख्य सड़क किनारे स्थित एक व्यावसायिक परिसर की ओर से बड़ी मात्रा में निर्माण मलबा फेंके जाने की शिकायत मिली थी। शिकायत के बाद नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा ने तत्काल जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए।

जोन–9 की टीम ने किया औचक निरीक्षण

आयुक्त के निर्देश पर जोन–9 के जोन कमिश्नर राकेश शर्मा के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची। अलसुबह किए गए औचक निरीक्षण में स्वास्थ्य अधिकारी बैरोन बंजारे, उमेश नामदेव और स्वच्छता निरीक्षक भोला तिवारी ने स्थल का निरीक्षण किया। जांच में पाया गया कि व्यावसायिक परिसर की ओर से बड़ी मात्रा में निर्माण मलबा सड़क किनारे डाला गया था। इससे राहगीरों की आवाजाही प्रभावित हो रही थी और क्षेत्र की स्वच्छता व्यवस्था भी बिगड़ रही थी।

25 हजार रुपये का ई–चालान जारी

निरीक्षण के बाद नगर निगम ने स्वच्छता नियमों के उल्लंघन पर संबंधित व्यावसायिक परिसर के संचालक जसवीर सिंह खनूजा के खिलाफ 25 हजार रुपये का ई–चालान जारी किया। नगर निगम ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थानों पर मलबा या कचरा फेंकने की पुनरावृत्ति होने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ इससे भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

संपादकीय

सावधान जैन जी समाधान बनो, औजार नहीं

वोटों के लालच में चतुर राजनीति बंदूक रख रही युवा कंधों पर

युवा जब सड़क पर उतरता है तो सत्ता को सिर्फ भीड़ दिखाई देती है, जबकि वह व्यवस्था की विफलता का चलता-फिरता दस्तावेज होता है। झारखंड में इन दिनों 'जैन जी' आंदोलन इसी दस्तावेज की तरह सामने आया है। प्रश्नपत्रों का लीक होना, परीक्षाओं में गड़बड़ी, चयन प्रक्रिया में धांधली, भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोप तथा शिक्षा और रोजगार की लगातार गिरती गुणवत्ता ने युवाओं के भीतर जो बेचैनी जमा की थी, वह अब आंदोलन के चरम पर पहुंचती दिखाई दे रही है। दिल्ली में भी कुछ समय पहले इसी तरह की बेचैनी ने आंदोलन का रूप लिया था। मुद्दा अलग-अलग राज्यों का हो सकता है, लेकिन दर्द एक है । पढ़ो, परीक्षा दो, मेहनत करो और फिर भी चयन की गारंटी नहीं।

युवा पूछ रहा है,अगर नौकरी योग्यता से नहीं, जुगाड़ से मिलेगी तो वह पढ़े क्यों? अगर परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र बाजार में पहुंच जाएगा तो वह रात-दिन तैयारी क्यों करे? अगर चयन सूची पर सवाल उठेंगे और शिकायतों के बाद भी कार्रवाई नहीं होगी तो उसे व्यवस्था पर भरोसा किस आधार पर करना चाहिए?

मुद्दा सिर्फ प्रश्नपत्र का नहीं

किसी प्रतियोगी परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक होना केवल परीक्षा की एक घटना नहीं है। यह उस बच्चे के सपने की चोरी है जो महीनों या वर्षों तक तैयारी करता है। उसके माता-पिता की बचत, उसकी नींद, उसकी उम्र और उसका भविष्य—सब उस एक परीक्षा से जुड़ा होता है।

जब कोई प्रश्नपत्र पहले ही बिक जाए तो परीक्षा भवन में बैठे हजारों अभ्यर्थी बराबर नहीं रह जाते। एक के पास किताब होती है, दूसरे के पास पैसा और तीसरे के पास पहुंच। फिर योग्यता कहां बची?

यही कारण है कि परीक्षा संबंधी अनियमितताएं युवाओं के लिए महज प्रशासनिक चूक नहीं, न्याय और भविष्य का प्रश्न बन जाती हैं।

और मामला केवल पेपर लीक तक सीमित नहीं है। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव, परिणामों पर उठते सवाल, चयन में कथित पक्षपात, दलालों और बिचौलियों की भूमिका तथा रिश्वतखोरी की शिकायतें उस अविश्वास को और गहरा करती हैं।

सरकार कहती है कि हर आरोप सच नहीं होता। लेकिन लोकतंत्र में सरकार का काम केवल आरोपों को नकारना नहीं, बल्कि ऐसी पारदर्शी व्यवस्था बनाना है जिसमें आरोप लगाने की गुंजाइश ही न्यूनतम रह जाए।

शिक्षा रोजगार से या निराशा ?

शिक्षा को रोजगार की सीढ़ी है और रोजगार को प्रतियोगी परीक्षाओं की भूलभुलैया भी। लाखों युवा वर्षों तक एक परीक्षा से दूसरी परीक्षा तक दौड़ते रहते हैं। उम्र निकलती जाती है, आवेदन शुल्क बढ़ता जाता है और परिणाम का इंतजार लंबा होता जाता है। एक परीक्षा हुई तो पेपर पर सवाल। दूसरी हुई तो परिणाम पर सवाल। तीसरी में सीटें कम। चौथी में भर्ती प्रक्रिया लंबी। पांचवीं में अदालत। युवा आखिर करे तो करे क्या? यहां असली संकट रोजगार से भी बड़ा है, विश्वास का संकट।

सरकार झुके तो भी सवाल उठेंगे

आंदोलन के दबाव में सरकार अगर बातचीत के लिए तैयार होती है, मांगों पर विचार करती है या सुधार के कदम उठाती है तो यह लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। सत्ता का झुकना हार नहीं, जनता की आवाज सुनने की लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है लेकिन यहां एक दूसरा सवाल भी खड़ा होता है। क्या सरकार को यह बात आंदोलन के चरम पर पहुंचने के बाद ही समझ में आती है?अगर शिकायतें पहले से थीं तो उनका समाधान पहले क्यों नहीं हुआ?

युवाओं को सड़क पर उतरने की नौबत क्यों आई? व्यवस्था इतनी संवेदनशील क्यों नहीं रही कि परीक्षा संबंधी शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई हो सके? लोकतंत्र में आंदोलन अंतिम उपाय होना चाहिए, पहला नहीं।

राजनीति का खेल

युवाओं का आंदोलन जैसे ही बड़ा होता है, राजनीति की निगाह उस पर पड़ना स्वाभाविक है। सत्ता पक्ष कहता है कि पिछली सरकारों की देन है। विपक्ष कहता है कि वर्तमान सरकार ने युवाओं को धोखा दिया। कोई आंदोलनकारियों के साथ खड़ा होने का दावा करता है, कोई उनके बीच जाकर तस्वीर खिंचाता है, कोई मंच साझा करता है और कोई उनके नारों को अपने राजनीतिक भाषण में बदल देता है। यहीं युवा को सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है।

क्योंकि राजनीति को युवा का दर्द चाहिए, समाधान नहीं

युवाओं की भीड़ राजनीतिक दलों को दिखाई देती है। उसमें वोट दिखाई देता है। भविष्य का राजनीतिक समीकरण दिखाई देता है। सत्ता के खिलाफ माहौल बनाने का अवसर दिखाई देता है।युवा को दिखाई देता है, नौकरी।दोनों की जरूरतें अलग हैं।यही अंतर अगर युवा नहीं समझा तो आंदोलन किसी और की पटकथा का हिस्सा बन सकता है।

कंधा युवा का, बंदूक और की

राजनीति का सबसे पुराना हथियार यही है,जनता के असंतोष को अपनी लड़ाई बना लेना। आंदोलन आपका हो सकता है, नारा आपका हो सकता है, लाठी आप खाते हैं, मुकदमा आपके ऊपर होता है; लेकिन उसका राजनीतिक लाभ कोई और उठा सकता है। इसलिए जैन जी और उनके साथ खड़े युवाओं को यह समझना होगा कि हर नेता मित्र नहीं और हर राजनीतिक समर्थन आंदोलन की जीत नहीं होता। युवा खुलकर सवाल पूछे ˙ सवाल पूछे। सिर्फ तालियां न बजाएं।सबसे बड़ी गलती होगी कि आंदोलन किसी एक चेहरे, दल या नेता का पर्याय बन जाए। आज अगर आंदोलन जैन जी के नाम से पहचाना जा रहा है तो उन्हें भी समझना होगा कि आंदोलन की ताकत व्यक्ति में नहीं, मुद्दे की नैतिकता में होती है। हिंसा से बचना होगा। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से बचना होगा। जाति, धर्म और क्षेत्र के नाम पर आंदोलन को बांटने से बचना होगा। राजनीतिक दलों को मंच देने से पहले उनकी भूमिका स्पष्ट करनी होगी। आंदोलन की आर्थिक मदद, निर्णय प्रक्रिया और नेतृत्व,सब पारदर्शी होना नौकरी का अधिकार केवल विज्ञापन जारी करने से पूरा नहीं होता; निष्पक्ष अवसर उपलब्ध कराना भी सरकार की जिम्मेदारी है।

डॉ. घनश्याम बादल

कांवड़ यात्राः आस्था से आगे, वैज्ञानिक जीवनशैली का संदेश

प्रो. (डॉ.) मनमोहन

भारत की सनातन परंपरा में कांवड़ यात्रा केवल भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और भक्ति की अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि यह अनुशासन, संयम, सेवा, सामूहिकता और प्रकृति के प्रति सम्मान का भी सशक्त संदेश देती है। यदि इस यात्रा को आधुनिक विज्ञान और समाजशास्त्र की दृष्टि से देखा जाए, तो यह स्वस्थ जीवनशैली, मानसिक संतुलन, सामाजिक समरसता और पर्यावरणीय उत्तरदायित्व का एक जीवंत उदाहरण प्रतीत होती है। आवश्यकता इस बात की है कि यात्रा के इन सकारात्मक मूल्यों को केवल सावन के कुछ दिनों तक सीमित न रखकर दैनिक जीवन का हिस्सा बनाया जाए।

कांवड़ यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष शारीरिक सक्रियता है। सैकड़ों किलोमीटर तक पैदल चलना हृदय, फेफड़ों, मांसपेशियों तथा चयापचय प्रणाली को सक्रिय करता है। चिकित्सा विज्ञान भी स्वीकार करता है कि नियमित पैदल चलना मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापा तथा हृदय रोगों के जोखिम को कम करने में सहायक हो सकता है। यही कारण है कि कांवड़ यात्रा का संदेश केवल यात्रा तक सीमित न रहकर पूरे वर्ष नियमित शारीरिक गतिविधि अपनाने की प्रेरणा देता है।

यह यात्रा मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी महत्त्वपूर्ण संकेत देती है। सामूहिक प्रार्थना, भजन, 'बोल बम' के उद्घोष तथा साझा उद्देश्य के साथ आगे बढ़ने का अनुभव व्यक्ति में सकारात्मक भावनाओं और

सामाजिक जुड़ाव की भावना को सुदृढ़ करता है। मनोविज्ञान के अनुसार सामाजिक सहभागिता, ध्यान, प्रार्थना और योग जैसी गतिविधियाँ तनाव प्रबंधन तथा मानसिक संतुलन में सहायक हो सकती हैं। आज जब तनाव, अवसाद और अकेलेपन की समस्या बढ़ रही है, तब इन सकारात्मक अभ्यासों को दैनिक जीवन में स्थान देना समय की आवश्यकता है।

कांवड़ यात्रा अनुशासित जीवन का भी उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है। यात्री समयबद्ध दिनचर्या अपनाते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, संयम का पालन करते हैं तथा अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हैं। यदि यही अनुशासन, संतुलित आहार, नियमित दिनचर्या और आत्मनियंत्रण जीवन का स्थायी हिस्सा बन जाए, तो व्यक्तिगत स्वास्थ्य और कार्यक्षमता दोनों में सुधार संभव है।

इस यात्रा का एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक पक्ष भी है। विभिन्न जातियों, भाषाओं, आयु वर्गों और आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग समान उद्देश्य से साथ चलते हैं। मार्ग में स्थापित सेवा शिविरों में भोजन, पेयजल और प्राथमिक चिकित्सा जैसी सुविधाएँ बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध कराई जाती हैं। यह परंपरा भारतीय समाज की सेवा-भावना और सामाजिक समरसता का परिचायक है। यदि यही सहयोग और सेवा की भावना वर्ष भर अस्पतालों, विद्यालयों, वृद्धाश्रमों, पर्यावरण अभियानों तथा अन्य सामाजिक कार्यों में दिखाई दे, तो समाज अधिक संवेदनशील और सशक्त बन सकता है।

कांवड़ में गंगाजल लाने की परंपरा जल के प्रति श्रद्धा और संरक्षण का सांस्कृतिक संदेश भी देती है। ऐसे समय में जब जल संकट वैश्विक चुनौती बन चुका है, यह परंपरा जल के विवेकपूर्ण उपयोग, वर्षा जल संचयन तथा नदियों और अन्य जल स्रोतों की स्वच्छता के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने की प्रेरणा प्रदान करती है। आस्था और पर्यावरण संरक्षण का यह समन्वय आज के समय में विशेष रूप से प्रासंगिक है।

यात्रा के दौरान सीमित संसाधनों में रहना, प्रकृति के निकट समय बिताना तथा कई यात्रियों द्वारा डिजिटल उपकरणों के सीमित उपयोग का अनुभव आधुनिक जीवनशैली के संदर्भ में भी महत्त्वपूर्ण है। आज 'डिजिटल डिटॉक्स' की अवधारणा पर विश्वभर में चर्चा हो रही है। यदि परिवार सप्ताह में कुछ समय मोबाइल और सोशल मीडिया से दूर रहकर संवाद, अध्ययन, प्रकृति और पारिवारिक गतिविधियों को दें, तो मानसिक स्वास्थ्य और पारिवारिक संबंधों को सुदृढ़ करने में सहायता मिल सकती है।

कांवड़ को दोनों कंधों पर संतुलित रखकर चलना केवल शारीरिक संतुलन का नहीं, बल्कि जीवन के संतुलन का भी प्रतीक है। यह संदेश देता है कि जैसे कांवड़ का भार दोनों ओर समान होना चाहिए, वैसे ही जीवन में कार्य और विश्राम, अधिकार और कर्तव्य, भौतिक प्रगति और आध्यात्मिक मूल्यों के बीच भी संतुलन आवश्यक है।

वास्तव में कांवड़ यात्रा को केवल धार्मिक आयोजन के रूप में नहीं, बल्कि जीवन-प्रबंधन के वार्षिक प्रशिक्षण के रूप में भी देखा जा सकता है। यदि इस अवसर पर अपनाई गई स्वस्थ आदतें—नियमित पैदल चलना, योग एवं ध्यान, संयमित जीवनशैली, सेवा-भाव, पर्यावरण संरक्षण तथा सामाजिक उत्तरदायित्व आदि दैनिक जीवन का हिस्सा बन जाएँ, तो इस यात्रा का प्रभाव कहीं अधिक व्यापक , स्थायी और प्रशंसनीय होगा।

कांवड़ यात्रा का वास्तविक संदेश यही है कि धर्म केवल पूजा-पद्धति तक सीमित नहीं है; वह व्यक्ति, समाज और प्रकृति के प्रति उत्तरदायी जीवन जीने की प्रेरणा भी देता है। जब अनुशासन हमारी दिनचर्या, सेवा हमारा स्वभाव, पर्यावरण संरक्षण हमारा कर्तव्य और स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता बन जाएँ, तभी कांवड़ यात्रा का उद्देश्य पूर्ण रूप से सार्थक होगा। तब यह केवल सावन की एक धार्मिक यात्रा नहीं रहेगी, बल्कि स्वस्थ, संतुलित, संवेदनशील और उत्तरदायी भारत के निर्माण की सतत प्रेरणा बन जाएगी।

सरकारी स्कूल बचेंगे तो शिक्षा, संस्कार और संस्कृति भी बचेगी

— डॉ. सत्यवान सौरभ

किसी भी राष्ट्र की वास्तविक ताकत उसके विशाल भवनों, चौड़ी सड़कों, ऊँची इमारतों या आर्थिक विकास दर से नहीं मापी जाती। किसी देश की सबसे बड़ी शक्ति उसकी शिक्षा व्यवस्था होती है। शिक्षा ही वह आधार है जिस पर सभ्यता, संस्कृति, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और आर्थिक प्रगति का पूरा ढाँचा खड़ा होता है। यदि शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी तो समाज मजबूत होगा; यदि शिक्षा कमजोर होगी तो उसका प्रभाव आने वाली कई पीढ़ियों तक दिखाई देगा।

भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में सरकारी विद्यालय केवल पढ़ाई के केंद्र नहीं हैं, बल्कि सामाजिक समानता के सबसे बड़े संस्थान भी हैं। यहाँ किसान का बेटा, मजदूर की बेटी, दुकानदार का बच्चा और सरकारी कर्मचारी का पुत्र एक ही कक्षा में बैठकर शिक्षा प्राप्त कर सकता है। यही वह व्यवस्था है जो समाज में समान अवसर की भावना को जन्म देती है। यदि यह व्यवस्था कमजोर पड़ती है, तो शिक्षा धीरे-धीरे आर्थिक क्षमता पर निर्भर हो जाती है और समाज दो हिस्सों में बँटने लगता है—एक वह जो महँगी शिक्षा खरीद सकता है और दूसरा वह जिसे सीमित अवसरों से ही संतोष करना पड़ता है।

आज दुर्भाग्य से यह धारणा तेजी से फैल रही है कि अच्छी शिक्षा केवल निजी विद्यालयों में ही मिल सकती है। अंग्रेज़ी माध्यम को गुणवत्ता का पर्याय मान लिया गया है। अभिभावक अपनी आय का बड़ा हिस्सा निजी विद्यालयों की फीस, परिवहन, पुस्तकों और अन्य खर्चों पर लगाने को मजबूर हैं। दूसरी ओर, सरकारी विद्यालयों के प्रति उदासीनता बढ़ी है। यह प्रवृत्ति केवल शिक्षा का प्रश्न नहीं, बल्कि सामाजिक संतुलन का भी प्रश्न है।

यह सच है कि कुछ सरकारी विद्यालय संसाधनों, शिक्षकों की कमी या प्रशासनिक चुनौतियों से जूझ रहे हैं। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि देश के हजारों सरकारी विद्यालय उत्कृष्ट परिणाम दे रहे हैं। अनेक सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थी प्रशासनिक सेवाओं, सेना, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, खेल और शोध जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल कर रहे हैं। समस्या पूरे सरकारी तंत्र की नहीं, बल्कि उसकी असमान गुणवत्ता, सार्वजनिक धारणा और निरंतर सहयोग की कमी की भी है।

शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी प्राप्त करना नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को अच्छा नागरिक बनाना, सही और गलत में अंतर करना सिखाना, संविधान के प्रति सम्मान विकसित करना और समाज के प्रति उत्तरदायित्व का भाव जगाना भी है। यदि शिक्षा केवल परीक्षा और अंकों तक सीमित हो जाए तो वह अधूरी शिक्षा है। संस्कार, सहिष्णुता, अनुशासन, सहयोग और संवेदनशीलता जैसे मूल्य भी शिक्षा का अभिन्न हिस्सा हैं।

सरकारी विद्यालयों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलते हैं। विविध सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चों का एक साथ पढ़ना लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करता है। बच्चे एक-दूसरे की परिस्थितियों को समझते हैं, विविधता का सम्मान करना सीखते हैं और सामाजिक समरसता विकसित होती है। इसके विपरीत यदि शिक्षा पूरी तरह आर्थिक वर्गों में बँट जाएगी तो सामाजिक दूरी भी बढ़ेगी। आज अपराध, नशाखोरी, हिंसा, साइबर अपराध और सामाजिक असहिष्णुता जैसी समस्याओं पर गंभीर चर्चा होती है। इन समस्याओं के अनेक कारण हैं—बेरोज़गारी, सामाजिक असमानता, पारिवारिक विघटन, अवसरों की कमी और मूल्य-आधारित शिक्षा का अभाव। यह कहना उचित नहीं होगा कि इन सभी समस्याओं का कारण केवल शिक्षा व्यवस्था है, लेकिन यह अवश्य कहा जा सकता है कि एक मजबूत, समावेशी और मूल्य-आधारित शिक्षा व्यवस्था इन चुनौतियों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसीलिए सरकारी विद्यालयों को केवल भवन, कमरे और फर्नीचर के रूप में नहीं देखना चाहिए।

बोध कथा

अनमोल सांसें (चंदन का बगीचा)

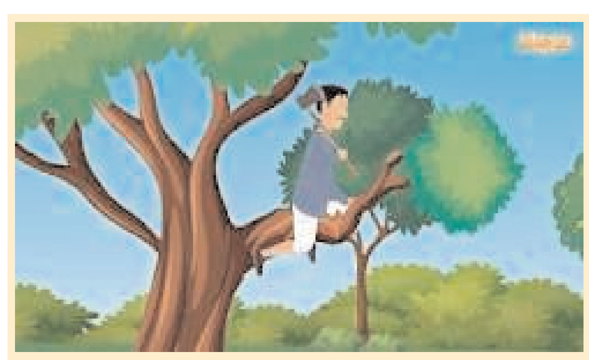

एक राजा ने एक गरीब लकड़हारे की मदद से पानी पिया। राजा उस से खुश हुआ। राजा ने उसे अपनी राजधानी बुलाया।राजधानी आने पर राजा ने खुश होकर उसे एक बड़ा चंदन का बगीचा दे दिया। लकड़हारा बहुत खुश हुआ। लेकिन लकड़हारा नासमझ था। उसने चंदन के कीमती पेड़ों को काटा और उनका कोयला बनाकर बाजार में बेचने लगा। धीरे-धीरे सारा बगीचा खत्म होने लगा। कुछ ही पेड़ बचे।एक दिन राजा बगीचा देखने आया। उसने देखा कि कीमती चंदन जलाकर कोयला बनाया जा रहा है। राजा ने दुखी होकर लकड़हारे से कहा, 'अरे मूर्ख! तू इन पेड़ों को जलाकर कोयला बेच रहा है। अगर तू सीधे चंदन की लकड़ी बेचता, तो तुझे इससे कई गुना ज्यादा पैसे मिलते।' लकड़हारा अपना माथा पीटकर रोने लगा। वह समझ गया कि उसने अपनी बेवकूफी से अनमोल चीज खो दी।

यह शरीर एक चंदन के बगीचे जैसा है। हमारी हर एक सांस चंदन के पेड़ जैसी अनमोल है। हम अपनी अज्ञानता, गुस्से, लालच और बुरी आदतों में अपनी जिंदगी की अनमोल सांसों को व्यर्थ गंवा देते हैं। हमें अपने जीवन को व्यर्थ नहीं खोना चाहिए, बल्कि अच्छे कामों में लगाना चाहिए।

चुटकुले

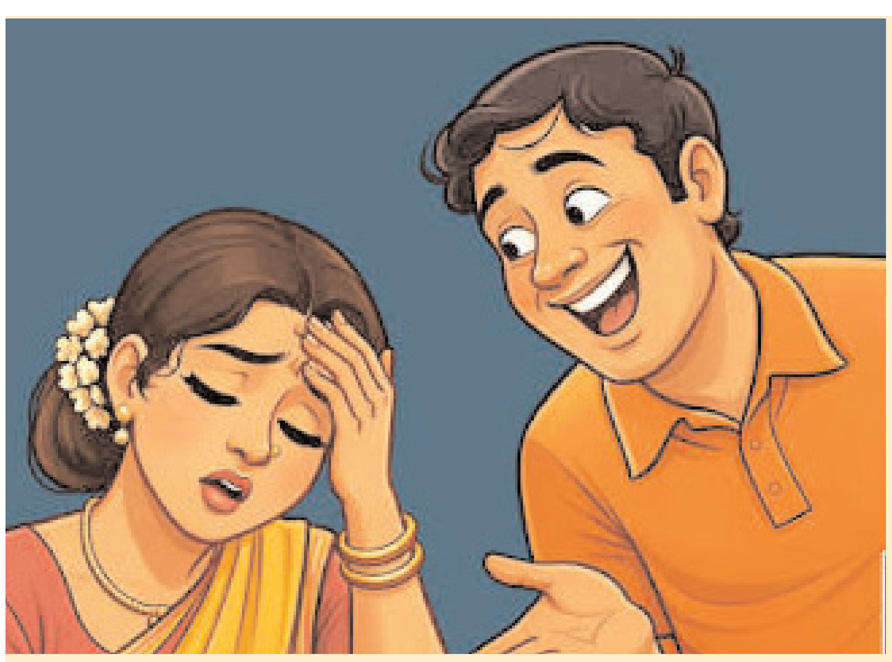

पति पत्नी से- आज पहली बार अलार्म से सुबह-सुबह मेरी नींद खुल गई।

पत्नी- वह कैसे जी? क्या आपको अलार्म सुनाई नहीं देता था?

पति- नहीं आज सुबह मुझे जगाने के लिए तुम्हारी मां ने अलार्म घड़ी फेंक कर सिर पर मारी थी।

एक गांव का लड़का जो दिल्ली नौकरी करने गया,

अपने गांव वापस आया और अपने दोस्तों से बोला:

पता है जितनी भीड़ दिल्ली वालों की शादी में होती है,

उससे ज्यादा भीड़ तो अपने यहां गांव में तब होती है जब खराब ट्रांसफॉर्मर ठीक होता है।

व्यंग्य केसरी

फेसबुकिया मित्र ::अनफ्रेंडली शत्रु!

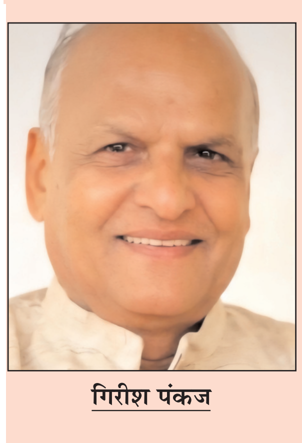

गिरीश पंकज

मित्र के वेश में बैठे शत्रुओं को पहचानना हो, तो फेसबुक आज के दौर का सबसे कमाल का माध्यम है। वह ज़माना गया जब आस्तीन के साँपों को ढूँढने के लिए जासूस लगाने पड़ते थे या उनके मुंह से सच उगलवाने के लिए कोई तंत्र-मंत्र साधना पड़ता था। अब तो बस फेसबुक पर एक स्टेटस डालिए और तमाशा देखिए! आप किसी दिन सुबह-सुबह बड़े ही सात्विक मन से, समाज सुधार या अपने किसी सुखद अनुभव पर कोई अच्छी बात लिखें। आप सोच रहे होंगे कि लोग आकर 'लाइक्स' और 'हार्ट' वाले इमोजी की बारिश करेंगे, पर ज़रा ठहरिए! कमेंट सेक्शन में सबसे पहला वार आपका वही तथाकथित 'फेसबुकिया मित्र' करेगा। वह आपकी बात में कोई ऐसा बाल की खाल निकालता हुआ खोट ढूँढ निकालेगा और फिर बार-बार लगभग गरियाने वाली शैली में ज्ञान पेलेगा। उसकी टिप्पणी पढ़कर आपको लगेगा कि शायद आपने दुनिया का सबसे बड़ा अपराध कर दिया है। बस, वहीं समझ जाना चाहिए कि यह व्यक्ति मित्र के चोले में छुपा हुआ विशुद्ध शत्रु है।

ऐसे लोगों का एकमात्र जीवन-उद्देश्य आपकी पोस्ट की धज्जियां उड़ाकर अपने कुंठाग्रस्त मन को शांति देना होता है। अब सवाल यह उठता है कि ऐसे 'महापुरुषों' का किया क्या जाए? ?अगर आपके भीतर सहिष्णुता की मूरत बनने की क्षमता बची हुई है, या आपका ब्लड प्रेशर अमूमन लो रहता है, तो आप उसे झेलते रहें। डॉक्टर भी तो कहते हैं कि कभी-कभी थोड़ा गुस्सा सेहत के लिए अच्छा होता है! लेकिन अगर आपके पास जीवन में करने के लिए और भी काम हैं और दिमागी सुकून प्यारा है, तो समझदारी तो यही कहती है कि उसे तुरंत 'अमित्र' यानी अनफ्रेंड करें, या सीधे 'ब्लॉक' का ब्रह्मास्त्र चलाकर गंगा नहाएँ। यकीन मानिए, लाल बटन दबाते ही जो परम शांति मिलेगी, वह किसी हिमालय की गुफा में भी नहीं मिल सकती।

वैसे, शास्त्र कहते हैं कि सच्चा मित्र वह है जो आपकी गलती पर आपका हाथ थामे। सच्चा और विवेकशील मित्र तो आपकी बात से असहमत होने पर सार्वजनिक रूप से आपकी फजीहत करने के बजाय मैसेंजर के इनबॉक्स में चुपके से आएगा। वह बड़े प्यार से आपको समझाएगा, 'भाई, तेरी बात में यह कमी थी, इसे थोड़ा ठीक कर ले।

पर अफ़सोस! ऐसी महान आत्माएं अब कहाँ पाई जाती हैं? वे शायद दुर्लभ प्रजाति की सूची में दर्ज हो चुकी हैं या फिर उन्होंने सोशल मीडिया की इस नौटंकी से तंग आकर अपना अकाउंट ही 'डिलीट' कर लिया है।

अब तो फेसबुक के इस डिजिटल कुरुक्षेत्र में केवल 'नोटिफिकेशन' के भूखे योद्धा बचे हैं। यहाँ तारीफें भी दिखावटी हैं और दुश्मनी भी मुफ्त की। इसलिए, अगली बार जब कोई आपकी पोस्ट पर बिना बात के टिप्पणी का भाला चलाए, तो दुखी होने के बजाय मुस्कुराइए। समझ लीजिए कि फेसबुक ने आपको बिना किसी फीस के एक छिपे हुए शत्रु का चेहरा दिखा दिया है। अब फैसला आपके हाथ में है: झेलते रहिए, या ब्लॉक करके शांति की डुबकी लगाइए ! या फिर सूची बनाते बैठे रहिए कि अब कितने शत्रु हो गए, एक दिन सबका निबटारा करें!

इतिहास

8 अगस्त का दिन भारतीय और विश्व इतिहास में अपनी एक खास और महत्वपूर्ण जगह रखता है। इस दिन की मुख्य ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण निम्नलिखित है:

1942: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए बम्बई (अब मुंबई) के ऐतिहासिक गोवालिया टैंक मैदान में 'भारत छोड़ो आंदोलन' (Quit India Movement) की शुरुआत की थी। इसी दिन गांधी जी ने भारतीयों को 'करो या मरो' का शक्तिशाली नारा दिया था। इस दिन को 'अगस्त क्रांति दिवस' के रूप में भी याद किया जाता है।

1864: जिनेवा में 'रेड क्रॉस' (Red Cross) की स्थापना की गई।1900: बॉस्टन में पहली बार 'डेविस कप' (Davis Cup) श्रृंखला की शुरुआत हुई। 1988: 8 साल के लंबे संघर्ष के बाद ईरान और इराक के बीच युद्ध विराम की घोषणा की गई।

पूर्व मुख्यमंत्री बघेल की चुनाव याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

विश्व केसरी

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सर्वोच्च न्यायालय ने भूपेश बघेल की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने 2023 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में अपनी जीत को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका को प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज करने की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बघेल चुनाव याचिका के ट्रायल के दौरान अपने सभी कानूनी और तथ्यात्मक आपत्तियां उठाने के लिए स्वतंत्र होंगे।

मामले में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने बघेल की ओर से दायर चुनौती पर सुनवाई की। चुनाव याचिका भाजपा नेता एवं बघेल के चुनावी प्रतिद्वंद्वी विजय बघेल ने लगाया है।

चुनाव याचिका में आरोप लगाया गया है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में मतदान से 48 घंटे पहले लागू साइलेंस पीरियड के दौरान भूपेश बघेल ने रोड शो किया, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 का उल्लंघन है। बघेल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि आरोप सही मान भी लिया जाए तो यह केवल धारा 126 के तहत चुनाव संबंधी अपराध हो सकता है, लेकिन इसे धारा 123 के तहत 'भ्रष्ट आचरण' नहीं माना जा सकता।

सिब्बल ने कहा, 'धारा 126 एक चुनावी अपराध है। यह भ्रष्ट आचरण नहीं है। भ्रष्ट आचरण धारा 123 के तहत आता है।' उन्होंने यह भी तर्क दिया कि कथित घटना का चुनाव परिणाम पर कोई वास्तविक प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि भूपेश बघेल ने लगभग 20 हजार मतों के अंतर से चुनाव जीता था। उन्होंने कहा कि कथित रोड शो में करीब 200 लोग थे और बघेल उस समय मुख्यमंत्री थे तथा उन्हें '+ सुरक्षा प्राप्त थी।

हालांकि, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची ने कहा कि कथित उल्लंघन से चुनाव परिणाम वास्तव में प्रभावित हुआ या नहीं, यह तथ्य का प्रश्न है, जिसका निर्धारण साक्ष्यों के आधार पर किया जाना आवश्यक है। सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि जब आरोप भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में ही नहीं आता तो बघेल को पूरी चुनावी सुनवाई से गुजरने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। इस पर न्यायमूर्ति बागची ने टिप्पणी की कि 'आपके पास बचाव के लिए एक तर्कसंगत मामला है।'

सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप से इनकार करते हुए बघेल की याचिका खारिज कर दी। हालांकि, कोर्ट ने उन्हें यह स्वतंत्रता दी कि वे चुनाव याचिका की सुनवाई के दौरान अपने सभी कानूनी और तथ्यात्मक तर्क हाईकोर्ट के समक्ष उठा सकते हैं। मामला 2023 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में पाटन विधानसभा सीट से भूपेश बघेल के निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका से जुड़ा है। भाजपा नेता विजय बघेल ने आरोप लगाया है कि मतदान से एक दिन पहले, 16 नवंबर 2023 को भूपेश बघेल ने रोड शो किया, जो धारा 126 के तहत लागू 48 घंटे के मौन काल का उल्लंघन है।

बिलासा एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का रास्ता साफ, टेंडर जारी

विश्व केसरी

बिलासपुर। बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट के विस्तार की मांग आखिरकार रंग लाई। लोक निर्माण विभाग ने टर्मिनल विस्तार के लिए 6.50 करोड़ रुपये की लागत का टेंडर जारी कर दिया है। 'हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति' के अनुसार यह बिलासपुर की जनता के लंबे संघर्ष का नतीजा है।

प्रस्तावित परियोजना के तहत करीब 22 हजार वर्गफुट में टर्मिनल का विस्तार होगा। इसमें लगभग 16 हजार वर्गफुट एरिया पूरी तरह सेंट्रल AC होगा। नए भवन में आधुनिक डिपार्चर हॉल बनेगा। निर्माण के बाद मौजूदा टर्मिनल का इस्तेमाल सिर्फ आगमन हॉल के लिए होगा।

पुराना टर्मिनल 1980 का, सुविधाएं नाकाफी

समिति ने बताया कि मौजूदा टर्मिनल 1980 के दशक की पुरानी बिल्डिंग है। इसमें समय-समय पर सिर्फ मामूली मरम्मत हुई है। आज 72 सीटों वाले विमान चल रहे हैं, लेकिन डिपार्चर हॉल में 72 यात्रियों के बैठने की जगह भी नहीं है।

अराइवल हॉल की स्थिति और खराब है। वहां सिर्फ 30-35 कुर्सियां हैं। यात्रियों की संख्या बढ़ते ही भीड़ लग जाती है। चाय-कॉफी और शौचालय की सुविधा भी कम है। इसी बिल्डिंग में VIP लाउंज और एयरपोर्ट ऑफिस भी चल रहा है, जिससे जगह और कम हो गई है।

जन संघर्ष समिति का कहना है कि टर्मिनल की कम क्षमता और सुविधाओं की कमी के कारण बड़ी एयरलाइनें यहां फ्लाइट शुरू नहीं कर रही थीं। इंडिगो जैसी कंपनी के लिए भी यही बाधा थी।

कहां बनेगा नया टर्मिनल और कब तक काम शुरू

नया निर्माण मौजूदा टर्मिनल के सामने, जहां अभी एयरपोर्ट का मुख्य गेट और बाउंड्री वॉल है, वहां होगा। काम पूरा होने के बाद पूरा डिपार्चर सेक्शन नए भवन में शिफ्ट हो जाएगा। पुरानी बिल्डिंग सिर्फ अराइवल के लिए बचेगी।

टेंडर जमा करने की आखिरी तारीख 21 अगस्त 2026 है। निविदाएं 27 अगस्त को खोली जाएंगी। समिति ने मांग की है कि प्रक्रिया पूरी होते ही निर्माण तुरंत शुरू किया जाए।

नि:शुल्क सरस्वती साइकिल योजना के तहत छात्राओं को वितरित की गई साइकिलें

विश्व केसरी

कोंडागांव। शासन की महत्वाकांक्षी नि:शुल्क सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत शुक्रवार, शुक्रवार को कोंडागांव जिले के शासकीय हाई स्कूल कुएं में कक्षा 9वीं में नवप्रवेशी छात्राओं को नि:शुल्क साइकिलों का वितरण किया गया।

कार्यक्रम में मुख्य रूप से सरपंच गणेश कुमेटी, प्राचार्य घनश्याम पटेल, व्याख्याता संदीपा गायकवाड़, धर्मेंद्र दास वैष्णव, पटवारी मंजुल घोड़ेसवर सहित पालकगण, एसएमसी के सभी सदस्य तथा विद्यालय के छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

इस अवसर पर छात्राओं को साइकिल प्रदान करते हुए अतिथियों ने शासन की इस योजना को बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया। साइकिल मिलने से छात्राओं को विद्यालय आने-जाने में सुविधा मिलेगी और उनकी शिक्षा के प्रति निरंतरता बनी रहेगी। कार्यक्रम का आयोजन विद्यालय परिवार द्वारा उपस्थित जनप्रतिनिधियों, पालकों, एसएमसी सदस्यों एवं छात्र-छात्राओं की उपस्थिति में किया गया।

स्काउट-गाइड के छात्रों ने जवानों के लिए भेजीं हस्तनिर्मित राखियां

विश्व केसरी

महासमुंद। भारत स्काउट एवं गाइड के राज्य मुख्यालय द्वारा संचालित ऑपरेशन सिपाही रक्षा सूत्र-2026 (संस्करण 0.4) के तहत जिले के विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं, स्काउट-गाइड सदस्यों और शिक्षकों ने भारतीय सेना के जवानों के लिए बड़ी संख्या में हस्तनिर्मित राखियां तैयार कीं। यह अभियान राज्य अध्यक्ष एवं शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, राज्य मुख्य आयुक्त इंद्रजीत सिंह खालसा, जिला मुख्य आयुक्त चंद्रहास चंद्राकर तथा जिला अध्यक्ष येतराम साहू के मार्गदर्शन में संचालित किया गया। विकासखंड पिथौरा, सरायपाली, बसना तथा शासकीय श्रीराम उच्च प्राथमिक शाला महासमुंद सहित जिले के विभिन्न विद्यालयों से प्राप्त राखियों का संग्रह कर उन्हें भारत स्काउट एवं गाइड, छत्तीसगढ़ राज्य मुख्यालय भेजा गया। राज्य स्तर पर निर्धारित रूट चार्ट के अनुसार इन राखियों को रायपुर में आयोजित ऑपरेशन सिपाही रक्षा सूत्र-2026 के माध्यम से भारतीय जवानों तक पहुंचाया गया। जिला संगठन आयुक्त स्काउट शत्रुघ्न साहू, जिला संगठन आयुक्त गाइड लीनू चंद्राकर तथा विकासखंड सह सचिव हिरेन्द्र साहू ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जिला शिक्षा अधिकारी बी.एल. देवांगन, सहायक संचालक नंदकिशोर सिन्हा और जिला क्रीड़ा अधिकारी अंजली बरमाल को विधिवत हस्तनिर्मित राखियां सौंपीं।

इस अवसर पर जिला सचिव प्रमोद कुमार कन्नौजे, मुख्यालय आयुक्त रामकुमार साहू, जिला प्रशिक्षण आयुक्त संतोष कुमार साहू, सीनियर गाइडर मधु शर्मा तथा शासकीय हाई स्कूल गढ़शिवनी के प्राचार्य तुलेंद्र सागर भी मौजूद रहे।

अधिकारियों और पदाधिकारियों ने अभियान की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार की गतिविधियां विद्यार्थियों में देशभक्ति, सेवा, समर्पण और सैनिकों के प्रति सम्मान की भावना को मजबूत करती हैं। उन्होंने छात्र-छात्राओं, स्काउट-गाइड सदस्यों एवं शिक्षकों के योगदान की प्रशंसा करते हुए इसे प्रेरणादायी पहल बताया।

कलेक्टर ने धनोरा क्षेत्र के गांवों का किया दौरा, सड़क निर्माण कार्यों का लिया जायजा

विश्व केसरी

कोण्डागांव। कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना ने शुक्रवार को धनोरा क्षेत्र में जिले के सीमावर्ती गांवों का दौरा कर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत चल रहे सड़क निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी लेते हुए कार्यों में तेजी लाने तथा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत ग्राम तोड़ासी से गददाड़, ग्राम बिंझे से चिखलाडीह तथा ग्राम कलेपाल से पराली तक निर्माणाधीन सड़क मार्गों का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से निर्माण कार्य की प्रगति, गुणवत्ता एवं निर्धारित समय-सीमा के संबंध में जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। जिले के इन दूरस्थ एवं सीमावर्ती गांवों में पक्की सड़कों के निर्माण से ग्रामीणों को बारहमासी आवागमन की सुविधा मिलेगी तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एवं अन्य शासकीय सेवाओं तक उनकी पहुंच आसान होगी। साथ ही क्षेत्र में विकास कार्यों को भी गति मिलेगी।

शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अडेंगा में एसएमडीसी की हुई बैठक

विश्व केसरी

कोंडागांव । शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोंडागांव जिले के अडेंगा में विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति की बैठक SMDC अध्यक्ष एस. आर. समरथ की अध्यक्षता एवं प्राचार्य श्री टी. एस. ठाकुर के मार्गदर्शन में संपन्न हुई। बैठक में जनपद उपाध्यक्ष ओम प्रकाश मरकाम, ग्राम पंचायत अडेंगा के सरपंच भूपेंद्र ध्रुव, उप सरपंच कौशल निषाद, शिक्षक प्रतिनिधि चरण पटेल, ग्राम गरावंडी के पूर्व उप सरपंच मिलनाथ कोर्राम तथा पंच प्रतिनिधि चिंताराम सहित समिति के सदस्य उपस्थित रहे।

बैठक में विद्यालय के विकास से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हुए दो अतिरिक्त कक्षों के निर्माण, नवीन फर्नीचर की व्यवस्था, हिंदी, रसायन एवं भौतिक विषय के रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति, विज्ञान प्रयोगशाला के सुदृढ़ीकरण, पुस्तकालय विकास, सड़क एवं पहुंच मार्ग के निर्माण, खेल सामग्री उपलब्ध कराने तथा कृषि संकाय के प्रायोगिक कार्य हेतु वर्मी कम्पोस्ट टैंक एवं कम्पोस्ट टैंक के निर्माण की मांग सर्वसम्मति से पारित की गई। बैठक में विद्यालय के समस्त शिक्षकगण, कर्मचारीगण एवं छात्र-छात्राओं की गरिमामयी उपस्थिति रही। अंत में प्राचार्य टी. एस. ठाकुर ने सभी अतिथियों एवं समिति के सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए विद्यालय के सर्वांगीण विकास हेतु सभी के सहयोग की अपेक्षा व्यक्त की।

पिथौरा-बागबाहरा के होटल-ढाबों में खाद्य विभाग की छापेमारी, पनीर का नमूना लिया गया

विश्व केसरी

महासमुंद। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए लगातार निरीक्षण अभियान चला रहा है। इसी कड़ी में अभिहित अधिकारी के मार्गदर्शन में पिथौरा और बागबाहरा विकासखंड के विभिन्न होटल, ढाबों और खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मेसर्स कोस्तुभ रेस्टोरेंट, विश्वा फैमिली ढाबा, छत्तीसगढ़ फैमिली ढाबा, तिवारी स्वीट्स, प्रतीक रेस्टोरेंट, पराग स्वीट्स, जन-2 रेस्टोरेंट तथा यश फैमिली ढाबा का निरीक्षण किया। जांच के दौरान यश फैमिली ढाबा में स्वच्छता संबंधी कमियां मिलने पर सुधार के लिए इंप्रूवमेंट नोटिस जारी करने की अनुशंसा की गई। वहीं, गुणवत्ता परीक्षण के लिए पनीर का एक प्रवर्तन नमूना भी संग्रहित किया गया। निरीक्षण के दौरान विभागीय अधिकारियों ने सभी संचालकों को वर्षा ऋतु में खाद्य सामग्री की गुणवत्ता और साफ-सफाई बनाए रखने के निर्देश दिए। साथ ही एनालॉग पनीर के उपयोग पर लगे प्रतिबंध का सख्ती से पालन करने, पनीर की खरीदी और उपयोग से जुड़े आवश्यक दस्तावेजों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की समझाइश दी गई।

इसके अलावा ईसी एक्टिविटी के तहत खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता से संबंधित पाम्पलेट और पोस्टर वितरित कर प्रतिष्ठान संचालकों को सुरक्षित खाद्य व्यवहार, स्वच्छता और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री के प्रति जागरूक किया गया।

कतार से क्लिक तक: भारतीय रेलवे में यात्री आरक्षण के चार दशक

विश्व केसरी

बिलासपुर। कतार से क्लिक तक, भारतीय रेलवे ने यात्री आरक्षण व्यवस्था को परिवर्तित कर दिया है। प्रौद्योगिकी दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक आरक्षण प्रणालियों में से एक को आज संचालित कर रही है। निरंतर आधुनिकीकरण ने बुकिंग को तेज और अधिक विश्वसनीय बना दिया है। आधुनिक यात्री आरक्षण प्रणाली एक स्मार्ट और अधिक सहज यात्रा अनुभव महसूस करा रही है।

रेलवे आरक्षण की रीढ़

भारतीय रेलवे (आईआर) दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क से हर दिन लाखों यात्रियों को जोड़ता है। यात्रा चाहे काम के सिलसिले में हो या शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, व्यवसाय या परिवार के लिए हो, यात्रीगण अपनी यात्रा की योजना बनाने के लिए विश्वसनीय आरक्षण इकोसिस्टम पर निर्भर होते हैं। प्रत्येक आरक्षित टिकट के पीछे यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) है, जो लगभग चार दशकों से रेलवे बुकिंग की प्रौद्योगिकी-आधारित रीढ़ है। पीआरएस को 1986 में पेश किया गया था और इसने मैन्युअल आरक्षण काउंटरों की जगह लेने से लेकर ऑनलाइन और मोबाइल टिकट बुकिंग को कामयाब बनाने तक का सफर तय किया है।

जैसे-जैसे उपयोगकर्ताओं की संख्या बढ़ी और ऑनलाइन संस्कृति ने जोर पकड़ा, वैसे-वैसे तेज और अधिक विश्वसनीय और बिना बाधा वाली बुकिंग सुविधाओं की आकांक्षा भी बढ़ी। पीक बुकिंग अवधि, विशेष रूप से तत्काल आरक्षण के दौरान, मांग अचानक बढ़ जाती है, जिससे मूल रूप से एक अलग समय के लिए डिज़ाइन किए गए बुनियादी ढांचे पर दबाव बढ़ जाता है। इन बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए, भारतीय रेलवे पीआरएस का व्यापक आधुनिकीकरण कर रहा है। नया पीआरएस बुकिंग क्षमता को बढ़ाएगा, यात्री-केंद्रित सुविधाओं को पेश करेगा और एक व्यापक ऑनलाइन बुनियादी ढांचा तैयार करेगा।

यात्री आरक्षण प्रणाली के चार दशक

पीआरएस एक कम्प्यूटरीकृत प्लेटफॉर्म है जो भारतीय रेलवे नेटवर्क पर आरक्षित टिकट व्यवस्था का प्रबंधन करता है। यह यात्रियों को आरक्षित टिकट बुक करने, संशोधित करने और रद्द करने की सुविधा उपलब्ध कराता है। यह सीट आवंटन, प्रतीक्षा सूची, टिकट रद्द करने के एवज में आरक्षण (आरएसी) की व्यवस्था संभालने के साथ-साथ आरक्षण चार्ट और यात्री पूछताछ का भी प्रबंधन करता है। आरक्षण केंद्रों और ऑनलाइन बुकिंग प्रणालियों को जोड़कर, पीआरएस ने रेलवे आरक्षण को अधिक कुशल, पारदर्शी और सुलभ बना दिया है।

पीआरएस ने मैन्युअल आरक्षण रजिस्टर और काउंटर-आधारित बुकिंग को इलेक्ट्रॉनिक सेटअप के जरिये बदल दिया। जैसे-जैसे रेलवे नेटवर्क का विस्तार हुआ, पीआरएस एक राष्ट्रव्यापी आरक्षण प्लेटफार्म के रूप में विकसित हो गया।

दर्री तालाब के सौंदर्यीकरण को परिषद की मंजूरी विकास और जनकल्याण से जुड़े कई अहम फैसले

विश्व केसरी

महासमुंद। नगर पालिका परिषद की सामान्य बैठक गुरुवार को पालिकाध्यक्ष निखिलकांत साहू की अध्यक्षता में नगर पालिका सभाकक्ष में आयोजित हुई।

बैठक को संबोधित करते हुए पालिकाध्यक्ष निखिलकांत साहू ने कहा कि नगर पालिका का लक्ष्य केवल प्रशासनिक कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना और उनका जीवन आसान बनाना है। उन्होंने कहा कि महासमुंद को स्वच्छ, सुंदर और विकसित शहर बनाने में जनप्रतिनिधियों और नागरिकों की समान भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, यही परिषद की प्राथमिकता है। बैठक में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत वृद्धावस्था, विधवा एवं अन्य पात्र हितग्राहियों के लंबित आवेदनों का शीघ्र निराकरण करने का निर्णय लिया गया। साथ ही राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के मामलों का भी त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने पर सहमति बनी, ताकि जरूरतमंद परिवारों को समय पर आर्थिक सहायता मिल सके। शहर की पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के उद्देश्य से बेलसोंडा फिल्टर प्लांट एवं मुढ़ेना इंटेकवेल में स्थापित जलप्रदाय योजना के उपकरणों, ट्रांसफार्मर और मोटर पंपों की मरम्मत एवं नियमित रखरखाव को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया।

पश्चिम एशिया में तनाव के चलते लाल हुआ बाजार, सेंसेक्स 456 अंक गिरा

विश्व केसरी ■

मुंबई। बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच वित्तीय सेवाओं और बैंक शेयरों में गिरावट के चलते हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार गिरावट के साथ लाल निशान में बंद हुआ। होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर नए सिरे से बनी अनिश्चितता के बीच कच्चे तेल की कीमतों में उछाल ने मध्य पूर्व में संभावित शांति समझौते पर संदेह पैदा कर दिया, जिसके चलते घरेलू बाजार के प्रमुख बेंचमार्क दबाव में रहे।

बाजार बंद होने के समय 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 455.59 अंकों यानी 0.58 प्रतिशत की गिरावट के साथ 78,499.17 पर पहुंच गया, तो वहीं एनएसई निफ्टी 50 65.35 अंक यानी 0.27 प्रतिशत की मामूली गिरावट के साथ 24,570.65 पर पहुंच गया।

व्यापक बाजार में निफ्टी मिडकैप में 0.22 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप में 0.05 प्रतिशत की गिरावट आई।सेक्टरवार देखें तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी प्राइवेट बैंक और निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई, तो वहीं निफ्टी ऑटो और निफ्टी आईटी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली। इसके अलावा, निफ्टी मेटल और निफ्टी पीएसयू बैंक में भी तेजी देखने को मिली।

निफ्टी50 इंडेक्स में ग्रासिम इंडस्ट्रीज, टीसीएस, हिंडाल्को, एमएंडएम, एचसीएल टेक और एसबीआई के शेयरों में सबसे ज्यादा बढ़त दर्ज की गई। इसके विपरीत, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ट्रेंट, आईसीआईसीआई बैंक, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और श्रीराम फाइनेंस के शेयर सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले शेयरों में शामिल रहे।

इस बीच, मार्केट एक्सपर्ट सुनील शाह ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि शुक्रवार के सेशन में प्रमुख बेंचमार्कों में गिरावट देखने को मिली, जो कि पश्चिम एशिया में नए सिरे से बढ़े तनावों से प्रेरित हैं। हालांकि इसके अलावा, मार्केट में कोई खास हलचल नहीं है।

एक्सपर्ट ने आगे कहा, 'अभी कंपनियों के नतीजे आने का दौर चल रहा है और मार्केट हर कंपनी के नतीजों पर प्रतिक्रिया दे रहा है। साथ ही, रात भर के संकेत भी नेगेटिव थे। आज ग्लोबल संकेत भी नेगेटिव हैं। लेकिन मुझे लगता है कि धीरे-धीरे मार्केट का रुख तेजी (बुलिश) की ओर बढ़ रहा है।'

उन्होंने आगे कहा, 'ऐसा मुझे इसलिए लगता है क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें 80 डॉलर के आसपास हैं, और अगर पश्चिम एशिया में शांति समझौता होता है तो ये कीमतें कम हो सकती हैं। इसलिए मुझे लगता है कि मार्केट अब गिरावट (बेयरिश) के बजाय थोड़ी ज्यादा सहज और तेजी की स्थिति में है।

भारत का घरेलू आर्थिक आधार मजबूत, एफपीआई निवेश में आएगी तेजी : जेफरीज

विश्व केसरी ■

नई दिल्ली। जेफरीज के इक्विटी स्ट्रेटजी के ग्लोबल हेड क्रिस्टोफर वुड ने भारत को लेकर सराकात्मक रुख दोहराते हुए, देश की मजबूत होती आर्थिक बुनियाद, कर्ज वृद्धि में सुधार और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की वापसी का हवाला देते हुए भारत-केंद्रित अपने इक्विटी पोर्टफोलियो में भी बदलाव किए हैं। अपने ताजा ग्रीड एंड फियर नोट में वुड ने कहा कि जुलाई में विदेशी निवेशक भारतीय शेयरों के शुद्ध खरीदार बन गए और उन्होंने 2.45 अरब डॉलर का निवेश किया। यह ऐसे समय हुआ जब वैश्विक निवेशकों ने टेक्नोलॉजी आधारित मेमोरी ट्रेड से जुड़े अपने निवेश को कम किया।

उन्होंने कहा कि बेहतर होते व्यापक आर्थिक संकेतकों के कारण भारत उभरते बाजारों में अब भी अलग नजर आ रहा है। 2026 के दौरान बैंक लोन वृद्धि सालाना आधार पर 17-18 प्रतिशत तक तेज हुई है, जो एक दशक से अधिक समय में सबसे तेज रफ्तार है। नोट के अनुसार, कॉरपोरेट लोन बैंक कर्ज विस्तार का सबसे मजबूत चालक बनकर उभरा है और इसमें सालाना आधार पर करीब 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वहीं, कृषि और खुदरा क्षेत्रों को दिए गए कर्ज में क्रमशः 17 प्रतिशत और 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

ऑटोमोबाइल और आवासीय संपत्तियों की मांग भी मजबूत बनी हुई है। भारतीय बाजार को लेकर अपने सकारात्मक रुख को दर्शाते हुए वुड ने इंडिया लॉन्ग-ओनली पोर्टफोलियो में बदलाव किया और कई घरेलू कंपनियों के शेयरों को बदला। रिपोर्ट में वुड ने आने वाले महीनों में रुपए को समर्थन देने वाले उपायों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक की गैर-निवासी भारतीयों के लिए विदेशी मुद्रा जमा योजना, जिसे जून में शुरू किया गया था, अब तक करीब 41 अरब डॉलर का निवेश आकर्षित कर चुकी है। यह उम्मीद से अधिक है और अगले दो महीनों में यह राशि बढ़कर 80-100 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय सरकारी बॉन्ड में निवेश से मिलने वाले ब्याज पर विदेशी निवेशकों को कर से छूट देने के सरकार के फैसले ने पहले ही सरकारी लोन बाजार को समर्थन दिया है।

भारत में जुलाई में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री रिकॉर्ड 3.28 लाख यूनिट्स पर रही : फाडा

विश्व केसरी ■

नई दिल्ली। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशंस (फाडा) द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, जुलाई में इलेक्ट्रिक वाहनों की खुदरा बिक्री अब तक के उच्चतम स्तर 3,27,901 इकाई पर पहुंच गई, जो सालाना आधार पर 66 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि है।

इस उछाल का मतलब है कि महीने के दौरान देश में खुदरा में बिकने वाले हर आठ वाहनों में से करीब एक वाहन इलेक्ट्रिक था। यह इस क्षेत्र में उपभोक्ताओं की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है।

हालांकि, इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों ने सबसे आगे रहते हुए पहली बार 2 लाख इकाइयों का आंकड़ा पार किया। जुलाई में इनकी खुदरा बिक्री सालाना आधार पर 88.3 प्रतिशत बढ़कर 2,04,362 इकाई हो गई, जबकि बाजार हिस्सेदारी एक साल पहले के 7.7 प्रतिशत से बढ़कर 11.2 प्रतिशत हो गई।

टीवीएस मोटर 55,499 इकाइयों की बिक्री के साथ इस क्षेत्र में शीर्ष स्थान पर बनी रही। इसके बाद बजाज ऑटो 45,613 इकाइयों और एथर एनर्जी 30,357 इकाइयों की बिक्री के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर रही। वहीं, ओला इलेक्ट्रिक ने महीने के दौरान 14,106 इकाइयां बेचीं।

इस बीच, इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों ने भी अपनी मजबूत स्थिति को और मजबूत किया। इनकी बिक्री सालाना आधार पर 25.3 प्रतिशत बढ़कर 87,055 इकाई हो गई। इस क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी बढ़कर 65.1 प्रतिशत हो गई, जो दर्शाता है कि इस श्रेणी में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पसंदीदा विकल्प बन गई है। महिंद्रा समूह 14,191 इकाइयों की बिक्री के साथ इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों के बाजार में शीर्ष पर बना रहा। इसके बाद बजाज ऑटो 13,442 इकाइयों की बिक्री के साथ दूसरे स्थान पर रहा। यात्री वाहन क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों की खुदरा बिक्री सालाना आधार पर 83.1 प्रतिशत बढ़कर 32,928 इकाई हो गई। इनकी बाजार हिस्सेदारी पिछले साल जुलाई के 5 प्रतिशत से बढ़कर करीब 8 प्रतिशत हो गई। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स इलेक्ट्रिक यात्री वाहन बाजार में 13,678 इकाइयों की बिक्री के साथ शीर्ष पर बनी रही।

इसके बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा 7,742 इकाइयों और जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया 5,689 इकाइयों की बिक्री के साथ रहे। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक वाहनों ने भी सबसे मजबूत वृद्धि दरों में से एक दर्ज की। इनकी खुदरा बिक्री सालाना आधार पर करीब 181 प्रतिशत बढ़कर 3,556 इकाई हो गई। इनकी बाजार हिस्सेदारी एक साल पहले के 1.65 प्रतिशत से दोगुनी से अधिक बढ़कर 3.57 प्रतिशत हो गई।

सोने और चांदी में उछाल, करीब 1.1 प्रतिशत तक बढ़े दाम

विश्व केसरी ■

मुंबई। सोने और चांदी की कीमतों में शुक्रवार को उछाल देखने को मिला है और इससे दोनों कीमती धातुओं का दाम करीब 1.1 प्रतिशत तक बढ़ गया है।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने का 5 अक्टूबर, 2026 का कॉन्ट्रैक्ट पिछली क्लोजिंग 1,48,858 रुपए प्रति 10 ग्राम के मुकाबले 1,49,355 रुपए प्रति 10 ग्राम पर खुला। सुबह 10 बजे यह 793 रुपए या 0.53 प्रतिशत की तेजी के साथ 1,49,651 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। अब तक के कारोबार में सोने ने 1,49,164 रुपए प्रति 10 ग्राम का न्यूनतम स्तर और 1,49,648 रुपए प्रति 10 ग्राम का उच्चतम स्तर छुआ है। चांदी का 4 सितंबर, 2026 का कॉन्ट्रैक्ट पिछली क्लोजिंग 2,25,836 रुपए प्रति किलो के मुकाबले 2,27,993 रुपए प्रति किलो पर खुला।

फिलहाल यह 2,549 रुपए या 1.13 प्रतिशत की मजबूती के साथ 2,28,385 रुपए प्रति किलो पर था।

अब तक के कारोबार में चांदी ने 2,27,481 रुपए प्रति किलो का न्यूनतम स्तर और 2,28,401 रुपए प्रति किलो का उच्चतम स्तर छुआ।

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। सोना 0.56 प्रतिशत की तेजी के साथ 4,323 डॉलर प्रति औंस और चांदी 1.43 प्रतिशत की बढ़त के साथ 62.49 डॉलर प्रति औंस पर था। जानकारों ने कहा कि हाल की तेजी को कमजोर अमेरिकी डॉलर और संभावित अमेरिका-ईरान परमाणु समझौते को लेकर बढ़ती उम्मीदों का समर्थन मिला है, जिससे भू-राजनीतिक अनिश्चितता के बावजूद बाजार का मूड सकारात्मक बना हुआ है।

उन्होंने आगे कहा कि बाजार में उतार-चढ़ाव बने रहने की उम्मीद है क्योंकि निवेशक बातचीत के बारे में और साफ जानकारी का इंतजार कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने संकेत दिया है कि अगले 48 घंटों में कोई अहम नतीजा सामने आ सकता है। निवेशक शुक्रवार को आने वाले अमेरिकी नॉन-फार्म पेरोल्स (एनएफपी) और बेरोजगारी के आंकड़ों पर भी नजर रखेंगे, क्योंकि ये आंकड़े फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों के नजरिए को लेकर उम्मीदें तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे।

गोबरधन योजना से 40 हजार करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की होगी बचत, सृजित होंगे 1.5 लाख रोजगार : सरकार

विश्व केसरी ■

नई दिल्ली। एक आधिकारिक बयान में शुक्रवार को कहा गया कि केंद्र सरकार की हाल ही में घोषित 'गोबरधन' (राष्ट्रीय सर्कुलर बायो-एनर्जी योजना) के माध्यम से भारत की आयात पर निर्भरता कम होगी और 40,000 करोड़ रुपए से अधिक की विदेशी मुद्रा की बचत की जा सकेगी। साथ ही यह क्षेत्र राष्ट्रीय जीडीपी में 75,000 करोड़ रुपए से अधिक का योगदान देगा और लगभग 1.5 लाख नए रोजगार पैदा करेगा।

सरकारी बयान के अनुसार, यह योजना अगले दस वर्षों में कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) के उत्पादन को लगभग दस गुना बढ़ाने में मदद करेगी। इसके साथ ही यह निजी निवेश को आकर्षित करेगी, सर्कुलर बायोइकोनॉमी को बढ़ावा देगी और उत्पादकों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए विशेष सीबीजी ऑफटेक एश्योरेंस फ्रेमवर्क स्थापित करेगी। इस योजना के तहत उत्पादित स्वदेशी और स्वच्छ गैस जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने में मदद करेगी। अनुमान है कि इससे करीब एक करोड़ मीट्रिक टन (10 मिलियन टन) जीवाश्म ईंधन के उपयोग को प्रतिस्थापित किया जा सकेगा।

सरकारी बयान के अनुसार, जैविक कचरे को लैंडफिल में जाने से रोकने से 40 मिलियन टन से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड (सीओ2) उत्सर्जन में कमी आएगी। साथ ही लगभग 250 मिलियन मीट्रिक टन जैविक उर्वरक का उत्पादन होगा, जो कृषि क्षेत्र के लिए भी बड़ा लाभ साबित हो सकता है। गोबरधन योजना के तहत सीबीजी उत्पादकों को बाजार की निश्चितता देने के लिए गैस खरीद की गारंटी दी जाएगी। सरकार ने 2,110 रुपए प्रति एमएमबीटीयू की प्रशासित कीमत निर्धारित की है। इसके अलावा परियोजनाओं को प्रति टन प्रतिदिन क्षमता पर 2 करोड़ रुपए तक की पूंजीगत सहायता मिलेगी और एमएसएमई इकाइयों को 85 प्रतिशत तक क्रेडिट गारंटी का लाभ भी दिया जाएगा।

सरकार ने कहा कि परिवहन, घरेलू उपयोग, उद्योग और वाणिज्यिक क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में घरेलू स्तर पर उत्पादित कंप्रेस्ड बायोगैस इस मांग का बड़ा हिस्सा पूरा कर सकती है। सीबीजी रासायनिक रूप से प्राकृतिक गैस के समान होती है और इसे मौजूदा गैस वितरण नेटवर्क में बिना किसी बड़े बदलाव के शामिल किया जा सकता है। इससे नवीकरणीय ऊर्जा के लाभों को देश के बढ़ते गैस बुनियादी ढांचे के साथ जोड़ा जा सकेगा।

हर सीबीजी संयंत्र स्थानीय स्तर पर कृषि अवशेष, गोबर और अन्य जैविक अपशिष्टों के उपयोग पर आधारित एक सर्कुलर अर्थव्यवस्था विकसित करेगा, जिससे कच्चे माल की आपूर्ति, परिवहन, संयंत्र संचालन और जैविक खाद उत्पादन जैसे क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

एसबीआई का मुनाफा पहली तिमाही में करीब 10 प्रतिशत बढ़कर 21,121.22 करोड़ रुपए रहा

विश्व केसरी ■

मुंबई। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने शुक्रवार को वित्त वर्ष 27 की पहली तिमाही के नतीजे जारी किए। बैंक का शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 10.23 प्रतिशत बढ़कर 21,121.22 करोड़ रुपए हो गया है, जो कि वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में 19,160.44 करोड़ रुपए था।

वित्त वर्ष 27 की पहली तिमाही में बैंक की ब्याज से आय सालाना आधार पर 8.5 प्रतिशत बढ़कर 1,27,896.46 करोड़ रुपए हो गई है, जो कि वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में 1,17,830.28 करोड़ रुपए थी।

अन्य आय को मिलाकर वित्त वर्ष 27 की पहली तिमाही में एसबीआई की कुल आय सालाना आधार पर 6.2 प्रतिशत बढ़कर 1,43,819.15 करोड़ रुपए हो गई है, जो कि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 1,35,341.56 करोड़ रुपए थी।

इस दौरान बैंक के कुल खर्च में भी बढ़ोतरी देखी गई है। वित्त वर्ष 27 की पहली तिमाही में एसबीआई का कुल खर्च सालाना आधार पर 5.2 प्रतिशत बढ़कर 1,10,289.97 करोड़ रुपए हो गया है, जो कि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 1,04,797.09 करोड़ रुपए था।

वित्त वर्ष 27 की पहली तिमाही में एसबीआई की नेटवर्थ 87,135.98 करोड़ रुपए बढ़कर 4,95,244.32 करोड़ रुपए हो गई है, जो कि पिछली तिमाही में 4,08,108.34 करोड़ रुपए थी।

परिचालन के मोर्चे पर बैंक का प्रदर्शन शानदार रहा है। एसबीआई का वित्त वर्ष 27 की पहली तिमाही में ग्रॉस एनपीए, वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही के 1.83 प्रतिशत से घटकर 1.47 प्रतिशत पर आ गया है।

वहीं, इस दौरान नेट एनपीएस 0.47 प्रतिशत से घटकर 0.38 प्रतिशत पर आ गया है।

इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 27 की पहली तिमाही में बैंक का डेट-टू-इक्विटी रेश्यो 0.54 रहा है, जो कि वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में 0.65 पर था।

नतीजों के बाद एसबीआई के शेयर में तेजी देखने को मिली है। दोपहर 2:30 बजे यह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर यह 3.15 प्रतिशत की तेजी के साथ 1,119 रुपए पर था।

भारतीय शेयर बाजार के मजबूत स्तंभ के रूप में उभर रहे घरेलू निवेशक, एफपीआई की बिकवाली का कम किया दबाव : सेबी

विश्व केसरी ■

नई दिल्ली। भारतीय शेयर बाजार के लिए घरेलू संस्थागत निवेशक (डीआईआई) वित्त वर्ष 26 में एक मजबूत स्तंभ के रूप में उभरे हैं और इस दौरान उन्होंने 8.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है। इससे पिछले वित्त वर्ष के दौरान विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) की 1.8 लाख करोड़ रुपए की बिकवाली के शेयर बाजार पर प्रभाव को कम करने में मदद मिली है। यह जानकारी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की वार्षिक रिपोर्ट में दी गई।

घरेलू निवेशकों की मजबूत भागीदारी से डीआईआई की हिस्सेदारी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर लिस्टेड सिक्योरिटीज में बढ़कर 17 प्रतिशत पर पहुंच गई है। वहीं, एफपीआई की हिस्सेदारी घटकर 15 महीने के निचले स्तर 15.8 प्रतिशत पर आ गई है। इसके अलावा, घरेलू निवेश में म्यूचुअल फंड का बड़ा हिस्सा रहा। इन्होंने लगभग 6.4 लाख करोड़ रुपए का योगदान दिया, जिसमें लगातार सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (एसआईपी) निवेश और रिटेल निवेशकों की बढ़ती भागीदारी का अहम रोल रहा। यह ट्रेंड निवेशकों की संख्या में लगातार हो रही बढ़ोतरी के बीच देखने को मिला है। साल के दौरान डीमैट खातों की संख्या बढ़कर 22.5 करोड़ हो गई, जो डिजिटल ऑनबोर्डिंग और मार्केट तक आसान पहुंच की वजह से व्यापक भागीदारी को दर्शाता है। सेबी की रिपोर्ट में भारत के कैपिटल मार्केट के बढ़ते विस्तार पर भी जोर दिया गया। कॉरपोरेट इंडिया ने पब्लिक इक्विटी ऑफरिंग के जरिए रिकॉर्ड 2.35 लाख करोड़ रुपए जुटाए। इसमें इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ), फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर (एफपीओ) और राइट्स इश्यू शामिल हैं। यह पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 11.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 26 में रिकॉर्ड 257 कंपनियों ने एसएमई प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके 11,587 करोड़ रुपए जुटाए, जबकि राइट्स इश्यू के ज़रिए जुटाई गई पूंजी 134.2 प्रतिशत बढ़कर 46,168 करोड़ रुपए हो गई।

शरीर में सूजन जैसी महसूस होती है, हो सकता है वाटर रिटेंशन, जानिए इसके कारण और इसे कैसे दूर करें

जब हमारे शरीर के अंगों में वॉटर रिटेंशन होता है तो हमारे शरीर के कुछ हिस्सों जैसे हाथ, पैर, चेहरे और पेट की मांसपेशियों में सूजन हो जाती है। आयुर्वेदिक डॉक्टर चंचल शर्मा कहती हैं कि जब हमारा शरीर मिनिरल्स के लेवल को बैलेंस नहीं कर पाता है तो इसकी वजह से शरीर के टिशूज़ में पानी जमा होने लगता है और शरीर के अंग फूलने लगते हैं। ये स्थिति आपके पैरों, एड़ियों और टखनों में भी भयंकर दर्द का कारण बन सकती है।

वाटर रिटेंशन क्या है?

वॉटर रिटेंशन का मतलब है शरीर के अंदरूनी हिस्सों में तरल पदार्थ का जमा होना। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर के ऊतकों यानि टिशूज में जरूरत से ज़्यादा पानी जमा हो जाता है। इससे शरीर के कुछ खास हिस्सों, जैसे पैरों, टखनों, हाथों या चेहरे पर सूजन आ जाती है। यह समस्या महिलाओं में ज्यादा आम है, खासकर हार्मोनल बदलावों के कारण जैसे कि पीरियड्स से पहले या प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा अधिक होता है। इसके अलावा, ज़्यादा नमक खाना, कम पानी पीना, लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठे रहना और दिल, किडनी या लिवर से जुड़ी बीमारियां भी इस समस्या का कारण बन सकती हैं।

वॉटर रिटेंशन शरीर में क्या होता है?

शरीर में भारीपन महसूस होना जोड़ों में अकड़न होना

तेज़ी से वज़न का बढ़ना

अगर इसका इलाज न किया जाए, तो इससे हाई ब्लड प्रेशर, किडनी की समस्या या दिल की बीमारी जैसी गंभीर स्थितियां पैदा हो सकती हैं।

वॉटर रिटेंशन से बचने के उपाय?

इससे बचने के लिए नमक का सेवन कम करें, खूब पानी पिएं, रोज़ाना हल्की-फुल्की कसरत करें और लंबे समय तक एक ही जगह पर एक ही स्थिति में बैठने से बचें। अगर सूजन बनी रहती है, तो डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें, क्योंकि यह किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है। स्वस्थ दिनचर्या और खान-पान अपनाकर शरीर में पानी जमा होने की समस्या से बचा जा सकता है।

सूजन कम करने के घरेलू उपाए

डॉक्टर चंचल शर्मा (आशा आयुर्वेदा विशेषज्ञ) ने सुझाव देते हुए इसके लिए कुछ घरेलू उपाय बताए हैं जिन्हें आप अपना सकते हैं।

नमक और प्रोसेस्ड फूड कम करें- सोडियम का सेवन कम करें और जंक फूड या डिब्बाबंद चीज़ों से बचें।

पोटैशियम और मैग्नीशियम लें- केले, एवोकाडो, हरी सब्ज़ियां, दही और नट्स जैसी चीज़ें खाएं, जो शरीर में तरल पदार्थों का संतुलन बनाए रखने में मदद करती हैं।

खूब पानी पिएं- शरीर में पानी की सही मात्रा बनाए रखने से टॉक्सिन्स और अतिरिक्त नमक पेशाब के ज़रिए बाहर निकल जाते हैं। शारीरिक गतिविधि बढ़ाएं- नियमित व्यायाम और टहलने से ब्लड सर्कुलेशन और लिम्फैटिक सिस्टम का काम बेहतर होता है, जिससे सूजन कम होती है।

घरेलू उपाय- कुलथी का पानी पीना और पार्सले का सेवन करना नैचुरल डाइयूरेटिक का काम करते हैं। ठंडे पानी से नहाना और हल्के हाथों से मालिश करने से भी सर्कुलेशन बेहतर हो सकता है और सूजन कम हो सकती है।

अगर सूजन कम है तो ठंडी सिंकाई करें, कोल्ड थेरेपी का मुख्य मकसद सूजन और तेज़ दर्द को कम करना है। इसके विपरीत, हीट थेरेपी रक्त संचार को बढ़ाती है, जिससे ताज़ा सूजन वाली जगह पर सूजन और बढ़ सकती है और दर्द भी तेज़ हो सकता है। सूजन है तो घबराएं नहीं, आयुर्वेद के अनुसार बताये गए उपचार अपनाएं।

मिडिल एज में तीन चीजों पर नियंत्रण से 13 साल तक टल सकता है डिमेंशिया : अध्ययन

नई दिल्ली। मिडिल एज में उच्च रक्तचाप, टाइप-2 मधुमेह और धूम्रपान को अगर नियंत्रित रखा तो तय है कि डिमेंशिया की शुरुआत को औसतन 13 वर्ष तक टाला जा सकता है। यह दावा एक नए अंतरराष्ट्रीय अध्ययन में किया गया है।

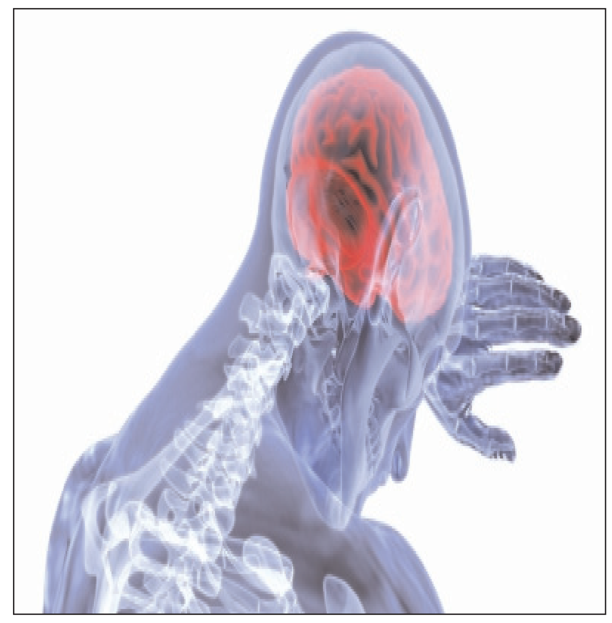

अमेरिकी मेडिकल जर्नल 'न्यूरोलॉजी' में प्रकाशित इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने 12,400 से अधिक लोगों के स्वास्थ्य आंकड़ों का लगभग 26 वर्षों तक विश्लेषण किया। अध्ययन की शुरुआत में प्रतिभागियों की औसत आयु 56 वर्ष थी। फॉलो अप पीरियड के दौरान 3,000 से अधिक प्रतिभागियों में डिमेंशिया बढ़ा।

शोधकर्ताओं ने पाया कि जिन लोगों में मिडिल एज के दौरान उच्च रक्तचाप, टाइप-2 मधुमेह और धूम्रपान जैसे तीनों जोखिम कारक मौजूद नहीं थे, वे औसतन 30.1 वर्ष तक डिमेंशिया से मुक्त रहे। वहीं, जो इन्हें नियंत्रित नहीं कर पाए, उनमें डिमेंशिया-मुक्त अवधि केवल लगभग 17 वर्ष रही। इस प्रकार दोनों समूहों के बीच करीब 13 वर्षों का अंतर दर्ज किया गया। अध्ययन के वरिष्ठ लेखक और अमेरिका के एनवाईयू लैंगोन हेल्थ से जुड़े डॉ. जोसेफ कोरेश ने कहा कि डिमेंशिया की प्रक्रिया लक्षण सामने आने से कई वर्ष पहले ही शुरू हो जाती है। ऐसे में मिडिल एज में हृदय और रक्त वाहिकाओं से जुड़े जोखिमों को नियंत्रित करना मस्तिष्क के दीर्घकालिक स्वास्थ्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञों के अनुसार, उच्च रक्तचाप और मधुमेह मस्तिष्क की रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जबकि धूम्रपान ऑक्सीडेटिव तनाव और सूजन को बढ़ाकर मस्तिष्क कोशिकाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इन जोखिमों को कम करने से संज्ञानात्मक क्षमता लंबे समय तक सुरक्षित रखी जा सकती है।

हालांकि शोधकर्ताओं ने स्पष्ट किया कि डिमेंशिया को पूरी तरह रोका नहीं जा सकता, क्योंकि उम्र और आनुवंशिक कारक इसके प्रमुख जोखिम बने रहते हैं। फिर भी स्वस्थ जीवनशैली अपनाकर, रक्तचाप और रक्त शर्करा को नियंत्रित रखकर तथा धूम्रपान से दूरी बनाकर डिमेंशिया के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इससे पहले लैंसेट आयोग की रिपोर्ट में भी कहा गया था कि डिमेंशिया के लगभग 45 प्रतिशत मामलों को जीवनशैली और अन्य संशोधित किए जा सकने वाले जोखिम कारकों पर समय रहते नियंत्रण कर रोका या कई वर्षों तक टाला जा सकता है।

स्मृति शेष : महंत अवैद्यनाथ ने धर्म को समाजसेवा और राष्ट्रीय चेतना से जोड़ा

नई दिल्ली। भारत के संतों में कुछ नाम ऐसे होते हैं, जो केवल मठ और मंदिर तक ही सीमित नहीं रहे बल्कि वे समय की धारा में एक वैचारिक आंदोलन बने। गोरक्षपीठ के ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ जी महाराज ऐसे ही एक व्यक्तित्व थे। वे गोरखनाथ मठ के पीठाधीश्वर होने के साथ-साथ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, हिंदू समाज की एकता और लोककल्याण की उस चेतना के वाहक थे, जिसने पूर्वांचल से लेकर पूरे देश के लोगों पर गहरी छाप छोड़ी। 28 मई 1921 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के कांड़ी गांव में जन्मे कृपाल सिंह विष्ट ने जिस यात्रा की शुरुआत हिमालय की गोद से की, वह आगे चलकर हिंदुत्व, सामाजिक समरसता और राष्ट्रचेतना के विराट अभियान में बदल गई। महंत अवैद्यनाथ उसी गौरवशाली परंपरा के तेजस्वी नक्षत्र थे, जिसकी वैचारिक नींव उनके गुरुदेव महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने रखी थी। दिग्विजयनाथ जी स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में कांग्रेस से जुड़े रहते हुए भी हिंदू हितों की रक्षा के लिए मुखर रहे। जब कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप तेज हुए, तब उन्होंने कांग्रेस छोड़कर हिंदू महासभा का दामन थामा और फिर हिंदू समाज के संगठन में जुट गए। सन 1939 में उन्होंने अखिल भारतवर्षीय अवधूत भेष बारह पंथ योगी महासभा की स्थापना कर साधु-संतों को केवल आध्यात्मिक साधना तक सीमित रहने के बजाय समाज सापेक्ष कार्यों के लिए प्रेरित किया। यही विरासत आगे चलकर महंत अवैद्यनाथ के व्यक्तित्व में और अधिक व्यापक रूप में दिखाई दी। बचपन में ही माता-पिता का साया सिर से उठ जाने के बाद कृपाल सिंह बिष्ट का झुकाव अध्यात्म की ओर बढ़ा। युवावस्था में उन्होंने हिमालय, कैलाश मानसरोवर, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री जैसे तीर्थों की यात्राएं कीं। 1940 में बंगाल यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात गोरखनाथ मठ के तत्कालीन पीठाधीश्वर महंत दिग्विजयनाथ से हुई। यहीं से उनके जीवन की दिशा बदल गई। 8 फरवरी 1942 को महज 23 वर्ष की आयु में उन्हें दिग्विजयनाथ ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और उनका नाम 'अवैद्यनाथ' रखा। 1969 में जब गुरुदेव दिग्विजयनाथ ब्रह्मलीन हुए तो वह गोरक्षपीठ के पूर्ण पीठाधीश्वर बने। अवैद्यनाथ का व्यक्तित्व केवल धार्मिक नेतृत्व तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने आध्यात्मिकता को समाज सुधार और राष्ट्रहित से जोड़ा। उनका मानना था कि धर्म केवल पूजा-पाठ का विषय नहीं बल्कि समाज को संगठित और जागृत करने का माध्यम है। हिंदू समाज में व्याप्त छुआछूत और जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए उन्होंने अभियान चलाया। 1980 के दशक में तमिलनाडु के मीनाक्षीपुरम में हरिजनों के सामूहिक धर्मांतरण की घटना ने उन्हें गहराई से झकझोर दिया। इसके बाद उन्होंने सामाजिक समरसता और हिंदू एकता को अपना प्रमुख लक्ष्य बना लिया।

विश्वकवि टैगोर : उपलब्धियों से परे एक जीवंत विचार, जिनकी प्रासंगिकता आज भी बरकरार

नई दिल्ली। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिनका जीवन केवल उपलब्धियों का इतिहास नहीं होता, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक जीवंत विचार बन जाता है। रवींद्रनाथ टैगोर ऐसे ही महापुरुष थे, जिन्होंने साहित्य, शिक्षा, समाज सुधार और मानवीय मूल्यों को एक साथ जोड़कर एक ऐसी दृष्टि दी, जिसकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है।

1941 में 7 अगस्त को उनके निधन के साथ ही एक युग का अंत हुआ, लेकिन उनके विचार, उनकी संस्थाएं और उनका शिक्षा दर्शन आज भी समाज को दिशा दिखाती है।

रवींद्रनाथ टैगोर का व्यक्तित्व बहुआयामी था। वे महान साहित्यकार, समाज सुधारक, अध्यापक, कलाकार और संस्थाओं के निर्माता थे। उन्होंने न केवल सपने देखे, बल्कि उन्हें साकार करने के लिए कर्मयोगी की तरह कार्य किया। उनकी कालजयी सफलताओं ने भारतीयों में आत्मसम्मान का भाव जगाया। राष्ट्र की सीमाएं भी उनके विराट व्यक्तित्व को बांध नहीं सकीं। वे स्वयं को विश्व नागरिक मानते थे और उनका शिक्षा दर्शन सम्पूर्ण वसुधा के संरक्षण, विकास, सौंदर्य, सत्य और समस्त जीवों के कल्याण पर आधारित था।

6 मई 1861 को बंगाल के एक समृद्ध परिवार में जन्मे रवीन्द्रनाथ टैगोर को धर्मपरायणता, साहित्य और कला का संस्कार विरासत में मिला। वे महर्षि देवेन्द्रनाथ टैगोर के सबसे छोटे पुत्र थे। देवेन्द्रनाथ टैगोर ने 1863 में बोलपुर के पास एक आश्रम की स्थापना की थी, जो आगे चलकर रवीन्द्रनाथ टैगोर की कर्मस्थली बना। यहीं से शांति निकेतन, विश्वभारती और श्रीनिकेतन जैसी विश्व प्रसिद्ध संस्थाओं की नींव रखी गई।

समृद्ध परिवार में जन्म लेने के बावजूद उनका विद्यालयी जीवन सुखद नहीं रहा। कलकत्ता के ओरिएंटल सेमेनरी और बाद में नार्मल स्कूल का वातावरण उन्हें रास नहीं आया। उन्होंने बाद में लिखा कि विद्यालय में प्रवेश करते ही उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी अपनी दुनिया उनसे छीन ली गई हो और उसकी जगह लकड़ी की बेंच और सीधी दीवारें उन्हें घूर रही हों। यही अनुभव आगे चलकर उनके शिक्षा दर्शन की आधारशिला बना। उन्होंने जीवनभर ऐसी शिक्षा व्यवस्था के लिए कार्य किया, जो बच्चों की प्रकृति, रुचि और आवश्यकताओं के अनुरूप हो।

शिक्षा सीमित रहने के बावजूद उन्होंने घर पर संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी, संगीत और चित्रकला का अध्ययन निजी शिक्षकों से किया। 1878 में उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए, लेकिन वहां भी अधिक समय तक नहीं रुके। 1881 में लॉ की पढ़ाई के उद्देश्य से फिर विलायत गए, लेकिन वकालत का विचार छोड़कर स्वदेश लौट आए। औपचारिक शिक्षा अधूरी रही, लेकिन पूर्व और पश्चिम की संस्कृतियों का प्रत्यक्ष अनुभव उनके व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। 1901 में उन्होंने बोलपुर के निकट ब्रह्मचर्य आश्रम के नाम से विद्यालय की स्थापना की, जिसे बाद में शांति निकेतन कहा गया। इसके बाद उन्होंने स्वयं को शिक्षा, साहित्य और समाज सेवा के लिए पूरी तरह समर्पित कर दिया।

सक्रिय राजनीति में टैगोर को विशेष रुचि नहीं थी, लेकिन जब अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया तो उन्होंने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया। वे कलकत्ता की गलियों में एकता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का संदेश लेकर निकले। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उन्होंने अंग्रेजी सरकार द्वारा दी गई 'नाइटहुड' की उपाधि लौटा दी और पीड़ित भारतीयों के साथ खड़े हुए।

साहित्यकार के रूप में उनकी ख्याति निरंतर बढ़ती गई। 1913 में उनकी काव्य कृति 'गीतांजली' के लिए उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला और वे एशिया के पहले व्यक्ति बने जिन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ। इसके बाद पूरा विश्व उन्हें विश्वकवि के रूप में पहचानने लगा। गुरुदेव केवल साहित्यकार नहीं थे, बल्कि एक ऐसे शिक्षाशास्त्री भी थे, जिन्होंने शिक्षा के सिद्धांतों को व्यवहार में उतारा। उनकी शिक्षा संबंधी प्रमुख पुस्तकों में 'शिक्षा', 'शान्तिनिकेतन ब्रह्मचर्य आश्रम', 'आश्रम के रूप व विकास' और 'विश्वभारती' शामिल हैं। इसके अलावा, शिक्षा पर उनके सौ से अधिक निबंध और व्याख्यान प्रकाशित हुए, जिनका अनेक भाषाओं में अनुवाद किया गया।

टैगोर का जीवन दर्शन मानवता, करुणा, आत्मसम्मान और समन्वय पर आधारित था। उनका विश्वास था कि कोई भी नवनिर्माण ऐसा नहीं होना चाहिए, जिससे व्यक्ति या समाज के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे या जीवन के आध्यात्मिक और सांसारिक पक्षों में दूरी पैदा हो। उन्होंने 1905 में 'स्वदेश समाज' निबंध लिखा, जिसमें कृषि, शिल्प और ग्रामोद्योग के पुनर्विकास पर बल दिया गया। इन्हीं विचारों को मूर्त रूप देने के लिए उन्होंने श्रीनिकेतन की स्थापना की, जहां आत्मसहायता और सहयोग के आधार पर सामुदायिक विकास का प्रयोग किया गया।

1924 में गरीब और अनाथ बच्चों के लिए 'शिक्षा सत्र' की स्थापना की गई। 1921 में शान्तिनिकेतन का विस्तार विश्वभारती विश्वविद्यालय के रूप में हुआ। यहां राष्ट्रीयता, धर्म, जाति और भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं था। रवीन्द्रनाथ टैगोर विभिन्न संस्कृतियों के बीच सहयोग और समन्वय में विश्वास रखते थे। उनका उद्देश्य मानव को संकीर्ण सीमाओं से निकालकर 'वसुधैव कुटुम्बकम' की भावना से जोड़ना था।

अमेरिका का एक स्कूल जहां स्टील की वॉटर बॉटल ले जाने पर रोक!

वाशिंगटन। अमेरिका के केंटकी स्थित हार्डिन काउंटी स्कूल प्रशासन ने बच्चों को स्टील वॉटर बॉटल न लाने का आदेश सुनाया है। जिला प्रशासन के अनुसार, छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये अहम फैसला लिया है। नए शैक्षणिक सत्र से छात्रों को स्कूल और स्कूल बसों में धातु (स्टील या एल्यूमीनियम) और कांच की पानी की बोतलें लाने की अनुमति नहीं होगी। अब केवल प्लास्टिक के पानी की बोतलें ही परिसर में ले जाई जा सकेंगी। स्कूल प्रशासन का कहना है कि यह फैसला अचानक नहीं लिया गया। पिछले कुछ वर्षों में ऐसी कई घटनाएं सामने आईं, जिनमें छात्रों ने भारी स्टील की पानी की बोतलों का इस्तेमाल दूसरे छात्रों पर हमला करने के लिए किया। कई मामलों में बच्चों के सिर, चेहरे और शरीर पर गंभीर चोटें आईं। कुछ छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जबकि कुछ को सिर में गंभीर चोट (कंकशन) का सामना करना पड़ा। अधिकारियों के अनुसार, जब स्टील की बोतल पूरी तरह पानी से भरी होती है, तो उसका वजन इतना अधिक हो जाता है कि वह किसी कठोर वस्तु की तरह गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। इन्हीं घटनाओं को देखते हुए स्कूल डिस्ट्रिक्ट ने सुरक्षा विशेषज्ञों और प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा के बाद यह निर्णय लिया कि संभावित खतरे को पहले ही रोकना बेहतर होगा। प्रशासन का मानना है कि यदि स्कूल परिसर में ऐसी भारी वस्तुएं ही नहीं होंगी, तो हिंसक घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। यह नया नियम 6 अगस्त से शुरू होने वाले शैक्षणिक सत्र के साथ लागू होगा। हालांकि शुरुआती दिनों में छात्रों और अभिभावकों को नियम समझाने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। यदि कोई छात्र गलती से धातु की बोतल लेकर आता है, तो शुरुआत में उसे केवल चेतावनी देकर प्लास्टिक की बोतल इस्तेमाल करने को कहा जाएगा। स्कूल प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध केवल नियमित स्कूल समय और स्कूल बसों के लिए लागू होगा। स्कूल के बाद होने वाली खेल प्रतियोगिताओं, अभ्यास सत्रों और अन्य सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों में खिलाड़ी धातु की पानी की बोतलें इस्तेमाल कर सकेंगे, क्योंकि उन परिस्थितियों में उनकी आवश्यकता अधिक होती है और निगरानी भी अलग ढंग से की जाती है। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, इस फैसले पर अभिभावकों की राय बंटी हुई है। कई अभिभावकों का कहना है कि कुछ छात्रों की अनुशासनहीनता के कारण सभी बच्चों पर प्रतिबंध लगाना उचित नहीं है। उनका तर्क है कि स्टील की बोतलें पर्यावरण के लिए बेहतर होती हैं और लंबे समय तक चलती हैं, जबकि प्लास्टिक की बोतलों के इस्तेमाल से प्लास्टिक कचरा बढ़ेगा।

फैटी लिवर, डेंगू और डायबिटीज में कैसे करें गिलोय का सेवन, जानिए क्या हैं Giloy के आयुर्वेदिक फायदे

गिलोय (टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया) एक बेल वाला पौधा होता है जो आमतौर पर जंगलों और झाड़ियों में पाया जाता है। गिलोय का इस्तेमाल लंबे समय से आयुर्वेदिक दवाओं में किया जाता रहा है। कोरोना में गिलोय के फायदे जानने के बाद आम लोगों ने भी इसे अपने घरों में लगाना शुरू कर दिया। गिलोय आसानी से उगने और लंबा होने वाला पौधा है। आप घर में भी इसकी बेल लगा सकते हैं। आइये जानते हैं गिलोय का इस्तेमाल किन बीमारियों को ठीक करने में किया जाता है।

गिलोय के पत्तों की पहचान कैसे करें?

गिलोय के पत्ते पान और मनी प्लांट के पत्तों से बड़े होते हैं। गिलोय की पहचान करना आसान है। इसकी पत्तियां पान के पत्तों जैसी होती हैं और इनका रंग गहरा हरा होता है। आप गिलोय को अपने घरों में सजावट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गिलोय को आयुर्वेद में गुडूची और अमृता जैसे नामों से भी जाना जाता है। आयुर्वेद के अनुसार, गिलोय की बेल जिस पेड़ पर चढ़ती है, उसके गुण भी उसमें आ जाते हैं। इसलिए नीम के पेड़ पर चढ़ने वाली गिलोय की बेल को दवा के लिहाज से सबसे अच्छा माना जाता है। इसे नीम गिलोय के नाम से जाना जाता है।

आयुर्वेद के अनुसार जाने गिलोय के औषधीय गुण

आयुर्वेदिक डॉक्टर चंचल शर्मा (आशा आयुर्वेदा विशेषज्ञ) आयुर्वेद में गिलोय की पत्तियों, जड़ और तना सभी को सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। लेकिन बीमारियों के इलाज में सबसे ज़्यादा इसके तने का इस्तेमाल किया जाता है। गिलोय में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। गिलोय में सूजन कम करने वाले एंटी-इंफ्लेमेटरी पाए जाते हैं और ये कैंसर-रोधी गुणों से भरपूर हैं। गिलोय का इस्तेमाल बुखार, पीलिया, गठिया, डायबिटीज, कब्ज, एसिडिटी, अपच और यूरिन से जुड़ी समस्याओं में राहत देने के लिए किया जाता है। बहुत कम औषधीय पौधे ऐसे हैं जो शरीर के तीनों दोषों वात, पित्त और कफ को संतुलित कर सकते हैं। गिलोय उनमें से एक है। गिलोय में टॉक्सिन्स को बाहर निकालने वाले गुण पाए जाते हैं जो इन हानिकारक टॉक्सिन्स से होने वाली बीमारियों को ठीक करने में असरदार भूमिका निभाते हैं।

गिलोय का सेवन करने का सही तरीका

आमतौर पर गिलोय का सेवन तीन तरीकों से किया जा सकता है।

गिलोय सत्व

गिलोय का रस

गिलोय चूर्ण

गिलोय के फायदे

अपच- गिलोय का काढ़ा पेट की कई बीमारियों को दूर रखने में मदद करता है। इसलिए कब्ज और अपच से राहत पाने के लिए रोज गिलोय का सेवन करें। इसके लिए रात में सोने से पहले आधे से एक चम्मच गिलोय पाउडर को गुनगुने पानी के साथ लें।

डायबिटीज- जानकारों के अनुसार, गिलोय हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के तौर पर काम करता है और टाइप-2 डायबिटीज को कंट्रोल करने में असरदार भूमिका निभाता है। गिलोय का जूस बढ़े हुए ब्लड शुगर लेवल को कम करता है, इंसुलिन के बनने को बढ़ाता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है। इसके लिए आप एक कप पानी में दो से तीन चम्मच गिलोय का जूस मिलाकर सुबह खाली पेट पी लें। आप आधा चम्मच गिलोय पाउडर पानी के साथ दिन में दो बार ले सकते हैं। लेकिन इसे खाना खाने के एक से डेढ़ घंटे बाद लेना चाहिए।

डेंगू- गिलोय के बुखार कम करने वाले गुण तेज़ी से बुखार घटाने में मदद करते हैं। यह इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है, जिससे बीमारी से तेज़ी से ठीक होने में मदद मिलती है। इसके लिए 1 कप पानी में दो से तीन चम्मच गिलोय का रस मिलाएं और इसे दिन में दो बार पिएं। आपको इसे खाने से करीब एक से डेढ़ घंटे पहले लेना चाहिए।

एनीमिया- शरीर में खून की कमी से कई तरह की बीमारियों का कारण बनती हैं। खासतौर से महिलाओं में एनीमिया की बड़ी समस्या होती है। महिलाओं को इसके लिए गिलोय का जूस बहुत फायदेमंद साबित होता है। गिलोय का जूस पीने से खून की कमी दूर होती है और इम्यून सिस्टम मज़बूत होता है। इसके लिए दो से तीन चम्मच गिलोय का जूस शहद या पानी के साथ मिलाकर, दिन में दो बार खाने से पहले लें।

लिवर के लिए फायदेमंद- गिलोय सत्व का सेवन लिवर के लिए टॉनिक का काम करता है। यह खून को साफ करता है और एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम के लेवल को बढ़ाता है। इससे लिवर पर काम का बोझ कम होता है और वह स्वस्थ रहता है। गिलोय का नियमित सेवन लिवर से जुड़ी गंभीर बीमारियों से बचाने में मदद करता है। एक से दो चुटकी गिलोय सत्व को शहद के साथ मिलाकर दिन में दो बार लें।

डॉक्टर चंचल शर्मा ने सलाह दी कि प्रेग्नेंट और ब्रेस्टफीडिंग कराने वाली महिलाओं को गिलोय न लेने की सलाह दी जाती है। हालांकि प्रेग्नेंसी के दौरान गिलोय से होने वाले नुकसान का कोई सबूत नहीं है, फिर भी डॉक्टर से सलाह लिए बिना इसका सेवन नहीं करना चाहिए।

लाहौर का वो मंच, जब केएल सहगल ने की मदद... फिर गूंज उठी सिद्धेश्वरी देवी की आवाज

मशहूर गायिका सिद्धेश्वरी देवी की आवाज में दर्द, प्यार और भावनाओं की ऐसी गहराई होती थी कि सुनने वाला खुद को उस संगीत से जुड़ा हुआ महसूस करता था। उन्हें 'ठुमरी की रानी' कहा जाता था। उनकी कला का बड़े-बड़े कलाकारों ने सम्मान किया। उनके जीवन से जुड़ा एक चर्चित किस्सा भी है, जब मशहूर गायक केएल सहगल ने खुद मंच पर आकर लोगों से सिद्धेश्वरी देवी को सुनने की अपील की थी। सिद्धेश्वरी देवी का जन्म 8 अगस्त 1908 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। उनका परिवार संगीत से जुड़ा था। उनकी दादी मैना देवी प्रसिद्ध गायिका थीं। बचपन में ही माता-पिता का निधन हो जाने के बाद उनका पालन-पोषण उनकी मौसी राजेश्वरी देवी ने किया। वह भी संगीत की अच्छी जानकार थीं। कहा जाता है कि सिद्धेश्वरी देवी का संगीत की दुनिया में आना भी एक खास घटना से जुड़ा था। शुरुआत में उनकी मौसी की बेटी संगीत सीखती थीं और सिद्धेश्वरी घर के छोटे-मोटे काम करती थीं। एक दिन जब उनकी बहन एक कठिन धुन नहीं गा पाई तो गुरु पंडित सियाजी महाराज नाराज हो गए। उस समय सिद्धेश्वरी ने वही धुन आसानी से गाकर सबको हैरान कर दिया। उनकी प्रतिभा देखकर पंडित सियाजी महाराज ने उन्हें संगीत की शिक्षा देने का फैसला किया। उन्होंने सबसे पहले प्रसिद्ध सारंगी वादक पंडित सियाजी महाराज से संगीत सीखा। इसके बाद उन्होंने उस्ताद राजब अली खान और उस्ताद इनायत खान जैसे बड़े कलाकारों से भी प्रशिक्षण लिया। हालांकि, वह पंडित बड़े रामदास को अपना मुख्य गुरु मानती थीं। उनकी गायकी में बनारस घराने की मिठास और भावनाओं की गहराई साफ दिखाई देती थी। सिद्धेश्वरी देवी की पहचान सबसे ज्यादा ठुमरी गायिका के रूप में बनी। ठुमरी में शब्दों के साथ भावनाओं को बहुत महत्व दिया जाता है। प्रेम, विरह, भक्ति और जीवन की छोटी-बड़ी भावनाओं को वह अपनी आवाज के जरिए लोगों तक पहुंचाती थीं। इसके अलावा, वह ख्याल, दादरा, कजरी, चैती, होरी और भजन भी गाती थीं। उनके करियर से जुड़ा एक बेहद चर्चित किस्सा साल 1930 का है। जब सिद्धेश्वरी देवी लाहौर में प्रस्तुति देने पहुंची थीं, तब वहां लोग मुख्य रूप से मशहूर गायक केएल सहगल को सुनने आए थे।

रवि किशन के मीम्स पर वीडियो बनाकर ट्रेंड में शामिल हुए शेखर सुमन, लिखा-'मनी फॉलो माई ब्रदर'

विश्व केसरी ■

मुंबई। अभिनेता और भाजपा सांसद रवि किशन इन दिनों सोशल मीडिया पर अपने द्वारा दिए गए पुराने बयानों, इंटरव्यू और एक्सप्रेशन्स को लेकर काफी मीम सेंसेशन बने हुए हैं। ऐसा ही उनका ऑडियो 'मनी फॉलो माई ब्रदर' काफी वायरल हो रहा है, जिस पर अभिनेता शेखर सुमन वीडियो बनाकर ट्रेंड में शामिल हो गए। अभिनेता ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वे रवि किशन के पुराने इंटरव्यू के ऑडियो 'मनी फॉलो माई ब्रदर-नाम या दाम नाम' पर लिपसिंक कर रहे हैं। रवि किशन के इस वायरल ऑडियो पर शेखर सुमन मजेदार अंदाज और शानदार एक्सप्रेशन के साथ लिपसिंक करते नजर आ रहे हैं। उनके एक्सप्रेशन देखकर ऐसा एहसास होता है कि वे ही इसे बोल रहे हैं।

अभिनेता ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ''मनी फॉलो माई ब्रदर'। 'मनी फॉलोसस'। नया एपिसोड शाम 6.18 बजे आएगा। शेखर सुमन की इस पोस्ट को फैंस द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है। कई यूजर्स रवि किशन के इमोजी बनाकर प्रतिक्रिया दे रह हैं। साथ ही, शेखर कैप्शन पढ़कर फैंल कयास लगा रहे हैं कि उनके चर्चित टॉक शो 'शेखर टुनाइट' के आगामी एपिसोड में रवि किशन हो सकते हैं।

बता दें कि रवि किशन का 'मनी फॉलो माई ब्रदर' बयान सोशल मीडिया (इंस्टाग्राम रील्स और मीम्स) पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे पहचान (नाम) बनाम पैसे (दाम) की बात करते हुए कहते हैं कि पैसा पहचान के पीछे-पीछे दौड़कर आता है। रवि किशन के इस वीडियो को इंस्टाग्राम और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर युवा इस कोट का उपयोग करके मजेदार, प्रेरणादायक और व्यंग्यात्मक रील्स बना रहे हैं। इस ट्रेंड के साथ-साथ रवि किशन के पुराने वायरल वीडियो जैसे 'जल्दी द लेट' और उनके अनोखे अंदाज भी फिर से चर्चा में आ गए हैं। साथ ही, उनके गाने के अंदाज और वीडियोज भी मीम्स का हिस्सा बनने से पीछे नहीं रह रहे हैं। शेखर सुमन का नया और चर्चित टॉक शो 'शेखर टुनाइट' मई 2026 में लॉन्च हुआ था, जो उनके लोकप्रिय 90 के दशक के कल्ट शो 'मूवर्स एंड शेकर्स' का डिजिटल अवतार है। यह शो उनके आधिकारिक शेखर सुमन यूट्यूब पर प्रसारित होता है, जिसमें राजनीतिक कटाक्ष, हास्य और मशहूर हस्तियों के साथ खुली बातचीत शामिल है।

सोनू निगम ने पहली बार हिंदी-हरियाणवी गाना 'चुन्नी' गाया, बताया- 'यह रोमांस और मस्ती से भरपूर है'

तीन दशक से भी ज्यादा समय से अपनी आवाज का जादू बिखेर रहे मशहूर सिंगर सोनू निगम ने पहली बार हिंदी-हरियाणवी संगीत की दुनिया में कदम रखा है। उनका नया गाना 'चुन्नी' रिलीज हो गया है। इसमें रोमांस, मस्ती और हरियाणवी संस्कृति की खूबसूरत झलक है। इस नए गीत को लेकर सोनू निगम ने कहा, ''संगीत केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि अलग-अलग संस्कृतियों और भावनाओं को जोड़ने का सबसे खूबसूरत जरिया भी है। 'चुन्नी' एक ऐसा गीत है, जिसमें मधुर धुन, रोमांटिक बोल और जोशीले संगीत का बेहतरीन मेल देखने को मिलता है। इस गाने की सबसे बड़ी खासियत इसकी एनर्जी है, जो सुनने वालों को अपने साथ जोड़ लेती है। मुझे इस गीत के बीट्स और इसकी चंचलता बेहद पसंद आई।''उन्होंने कहा, ''यह केवल शुरुआत है और आने वाले समय में श्रोताओं को इस तरह के कई नए और दिलचस्प संगीत सुनने को मिलेंगे। कलाकारों को समय-समय पर प्रयोग करते रहना चाहिए। इससे संगीत की दुनिया समृद्ध होती है और नए श्रोताओं तक पहुंच बनाने का अवसर मिलता है।''चुन्नी' को सोनू निगम के अपने म्यूजिक लेबल 'आई बिलीव म्यूजिक' के तहत वार्नर म्यूजिक इंडिया और ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के सहयोग से रिलीज किया गया है। इस गाने में आधुनिक संगीत के साथ हरियाणवी लोक संगीत भी है। इस मौके पर डिजिटल मनोरंजन और प्रौद्योगिकी कंपनी जेटसिंथेसिस के चेयरमैन राजन नवानी ने कहा, '''चुन्नी' केवल एक गीत नहीं, बल्कि भारत की समृद्ध क्षेत्रीय संगीत परंपरा और सांस्कृतिक विरासत का उत्सव है।

द अलायंस विनर मिनी माथुर बोलीं, जीतने के लिए डाउन एंड डर्टी होने की जरूरत नहीं

विश्व केसरी ■

मुंबई। मशहूर टीवी होस्ट और अभिनेत्री मिनी माथुर इन दिनों वेब रियलिटी शो 'द अलायंस' की विजेता के तौर पर सुर्खियों बटोर रही हैं। अभिनेत्री ने आईएएनएस के साथ बातचीत में रियलिटी शो में, स्मार्ट गेमप्ले और डर्टी गेमप्ले के बीच के अंतर पर बात की।

अभिनेत्री का मानना है कि ऐसे शोज में कुछ हद तक मैनिपुलेशन होता है। उन्होंने कहा कि कई बार खिलाड़ी अपनी रणनीति के तहत दूसरे का गेम अंडरप्ले करवाने की कोशिश करते हैं। अगर इससे किसी की अपनी रणनीति को फायदा मिलता है, तो यह गेम का हिस्सा माना जा सकता है, हालांकि वह पर्सनल अटैक में विश्वास नहीं करती हैं।

उन्होंने कहा कि किसी के जेंडर का अपमान करना गलत है। सिर्फ माहौल खराब करने के लिए चिल्लाना भी सही नहीं है। रणनीति के साथ खेलना और किसी को नीचा दिखाकर आगे बढ़ना, दोनों अलग बातें हैं। इन दोनों के बीच बहुत बारीक फर्क होता है। उम्मीद है मेरी जीत दूसरे रियलिटी शो को यह मैसेज देगी कि जीतने के लिए आपको डाउन एंड डर्टी होने की जरूरत नहीं है। आप गेम के नियमों के अंदर सीधे, तेज, स्ट्रैटजिक और मैनिपुलेटिव भी हो सकते हैं। आप पचास से ज्यादा उम्र की महिला भी हो सकती हैं और फिर भी अपनी आधी उम्र के कंटेस्टेंट को हरा सकती हैं।

मिनी माथुर ने कुशाल टंडन के व्यवहार के बारे में भी बात की। उनका मानना है कि कुशाल वैसे ही हैं जैसे कैमरे में दिखते हैं। शायद यही बात उनके फैंस को पसंद आती है। उन्होंने कहा, 'मुझे कभी नहीं लगा कि वे कैमरों के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। असल जिंदगी में भी वे ऐसे ही बात करते हैं। हालांकि कई मौकों पर मैंने उनसे बोला था कि उन्हें अपना अग्रेसन कम करना चाहिए, लेकिन उन्हें लगता था कि उनकी ऑडियंस उन्हें वैसे ही पसंद करती है जैसे वे हैं।'

अभिनेत्री नेकहा कि कुशाल बहुत ही सच्चे व्यक्ति हैं क्योंकि शो में वे जिन लोगों के साथ शुरू में खड़े थे, आखिरी तक उन्होंने उनका साथ दिया था। फिर सोहेल भाई हों, रेबा हों या मैं, वे पूरे सफर में सच्चे रहे। मिनी माथुर ने कहा, 'उन्होंने पूरे शो में मेरी इज्जत की और इसी वजह से मेरे पास कुशाल टंडन के बारे में कहने के लिए कुछ भी नेगेटिव नहीं है।

आईएएनएस ने जब अभिनेत्री से पूछा कि क्या वे आगे कोई रियलिटी शो करेंगी तो अभिनेत्री ने मना कर दिया और बताया कि उनके कई सारे प्रोजेक्ट लाइन पर लगे हुए हैं, जिनमें वे व्यस्त रहेंगी।

सीरीज रिलीज होने के बाद मेरे पास राकेश रौशन का पहला कॉल आया था : वेदिका पिंटो

विश्व केसरी ■

मुंबई । अभिनेत्री वेदिका पिंटो ने रोमांटिक-ड्रामा वेब सीरीज 'मुसाफिर कैफे' में सुधा किरदार निभाया है, जिसे दर्शकों की तरफ से लगातार तारीफ देखने को मिल रही है। अभिनेत्री ने आईएएनएस के साथ बातचीत में बताया कि सीरीज रिलीज होने के बाद सबसे पहले उनके पास किन-किन हस्तियों का कॉल आया था।

अभिनेत्री ने आईएएनएस को बताया सीरीज रिलीज होने के बाद उनके पास राकेश रौशन का कॉल आया था। उन्होंने कहा, 'सीरीज रिलीज के बाद मेरे पास राकेश रौशन का कॉल आया था। वह मेरे लिए बहुत बड़ा पल था क्योंकि मैं बचपन से ही उनकी फैन रही हूं। ऐसे में रिलीज के पहले ही दिन उनका कॉल आना मेरे लिए बहुत मायने रखता है।

अभिनेत्री ने बताया कि सुधा के किरदार ने उन्हें इस कदर आकर्षित किया, कि वे इस रोल के लिए मना ही नहीं कर पाईं। वेदिका पिंटो ने कहा, 'इसे चुनने की सबसे बड़ी वजह इसकी कहानी थी। इससे भी जरूरी बात यह है कि मुझे सुधा का किरदार और उसका कॉन्फिडेंस बहुत पसंद आया था। उसमें ऐसी कई सारी खूबियां हैं, जो अपने जीवन में लाना चाहती हूं। इसी बात ने मुझे इस रोल लिए आकर्षित किया। 'जब आईएएनएस ने अभिनेत्री से पूछा, 'आपको अभी तक किस रोल के लिए दर्शकों का प्यार मिला?

अभिनेत्री वेदिका पिंटो ने कहा, 'मुसाफिर कैफे ने मुझे दर्शकों का काफी ज्यादा प्यार और वैधता दिलाई है। क्योंकि यह एक रोमांटिक कहानी है, तो मुझे लगता है कि लोग रोमांटिक किरदारों से नैचुरली कनेक्ट करते हैं और रिस्पॉन्स भी जबरदस्त रहा है।

अभिनेत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि ओटीटी की वजह से पहले के मुकाबले नए लोगों को मौके मिल रहे हैं। उन्होंने कहा, 'ओटीटी की वजह से मौकों की संख्या निश्चित रूप से बढ़ी है, पहले, हर साल कुछ ही फिल्में बनती थीं। आज, कई ओटीटी प्लेटफॉर्म हैं, जो फिल्में और सीरीज बना रहे हैं, इसलिए जाहिर है कि एक्टर्स की ज्यादा डिमांड है। रोमांटिक-ड्रामा वेब सीरीज 'मुसाफिर कैफे' दिव्य प्रकाश दुबे के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है। इस सीरीज में विक्रांत मैसी, वेदिका पिंटो और महिमा मकवाना मुख्य भूमिकाओं में हैं। यह सीरीज नेटफ्लिक्स पर 24 जुलाई से स्ट्रीम हो रही है।

इंस्टाग्राम और यूट्यूब केवल कमाई का जरिया नहीं, कलाकारों के लिए नई पहचान बनाने का भी मंच : जयंती भाटिया

विश्व केसरी ■

झमुंबई, 7 अगस्त (आईएएनएस)। डिजिटल दौर में इंस्टाग्राम, यूट्यूब और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म आज कलाकारों के लिए टैलेंट दिखाने, लोगों से जुड़ने और पैसे कमाने का महत्वपूर्ण जरिया बन चुके हैं। इस पर टीवी अभिनेत्री जयंती भाटिया का कहना है कि सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव रहना और रोज नया और दिलचस्प कंटेंट तैयार करना आसान काम नहीं है। इसके लिए समय, मेहनत और क्रिएटिव सोच की जरूरत होती है। यहां सफलता पाने के लिए लगातार मेहनत करनी पड़ती है। कंटेंट क्रिएशन अब एक फुल-टाइम प्रोफेशन बन चुका है।

आईएएनएस से बात करते हुए जयंती भाटिया ने सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा, ''आज के समय में कई कलाकार इंस्टाग्राम और यूट्यूब के जरिए निजी जिंदगी, शूटिंग के दौरान के अनुभव, ट्रैवल, खान-पान, फैशन और रोजमर्रा के कामों को लेकर वीडियो शेयर करते हैं। इससे दर्शकों को कलाकार के असली व्यक्तित्व को करीब से जानने का मौका मिलता है। पर्दे पर निभाया गया किरदार और असल जिंदगी का इंसान दोनों अलग होते हैं। सोशल मीडिया इन दोनों के बीच की दूरी को कम करता है और दर्शकों के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाने में मदद करता है।

जयंती ने कहा, 'मेरा यूट्यूब चैनल 'चटपुरी चैती' भी है, जहां मैं अभिनय से अलग कुछ नया करने की कोशिश करती हूं। इस मंच पर काम करना मेरे लिए एक अलग और सुखद अनुभव रहा है। मैं अभी भी सोशल मीडिया की बारीकियों को सीख रही हूं, लेकिन आने वाले समय में इंस्टाग्राम पर छोटे-छोटे व्लॉग बनाना चाहती हूं। मैं दिनभर की गतिविधियों, शूटिंग के अनुभवों और अभिनय से जुड़ी ऐसी बातें लोगों तक पहुंचाना चाहती हूं, जिनसे खासकर नए कलाकारों को कुछ सीखने का मौका मिले। मेरा मानना है कि मनोरंजन जगत में आने वाले युवाओं को अभिनय ही नहीं, बल्कि इंडस्ट्री के काम करने के तरीके भी समझना चाहिए।

अभिनेत्री ने कहा, ''मैं अक्सर सोचती हूं कि नए कलाकारों के साथ इस पेशे से जुड़ी नैतिकता, अनुशासन और व्यवहार से संबंधित जरूरी बातें साझा करूं। अभिनय की दुनिया बाहर से जितनी आकर्षक दिखाई देती है, अंदर से उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी होती है। अपने लंबे करियर में मैंने कई उतार-चढ़ाव देखे हैं और कई कठिन परिस्थितियों का सामना किया है। ऐसे में अगर मेरा अनुभव किसी नए कलाकार के काम आ सके तो इससे बेहतर बात और क्या हो सकती है। इंडस्ट्री में सफल होने के लिए केवल अच्छा कलाकार होना काफी नहीं है, बल्कि समय की पाबंदी, प्रोफेशनल व्यवहार और दूसरों के प्रति सम्मान भी उतना ही जरूरी है।'' जयंती भाटिया ने उन कंटेंट क्रिएटर्स और कलाकारों की भी खुलकर तारीफ की, जिन्होंने इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा, ''इन लोगों ने समय रहते डिजिटल मीडिया की ताकत को समझा और उसका सही उपयोग किया। सोशल मीडिया आज केवल लोकप्रियता हासिल करने का माध्यम नहीं रह गया है, बल्कि यह कलाकारों के लिए अतिरिक्त आय का भी मजबूत स्रोत बन चुका है। इसके साथ ही जब किसी कलाकार के पास नया प्रोजेक्ट नहीं होता, तब भी कंटेंट क्रिएशन उसे सक्रिय, रचनात्मक और अपने दर्शकों से जुड़ा रखता है। यह लगातार सीखने और खुद को बेहतर बनाने का भी एक अच्छा जरिया है।''

ट्रंप ने अमेरिकी जन्मसिद्ध नागरिकता और बर्थ टूरिज्म पर लगाया प्रतिबंध

विश्व केसरी

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्मसिद्ध नागरिकता के दायरे को सीमित करने के लिए दो कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। यह कदम सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रशासन के पिछले आदेश को खारिज किए जाने के बाद उठाया गया है।

ट्रंप ने व्हाइट हाउस ओवल ऑफिस में नए ऑर्डर पर हस्ताक्षर करते हुए कहा, 'जन्म के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हमारा बहुत बुरा फैसला आया, यह बहुत करीबी था। इसलिए हम बदलाव कर रहे हैं।'

व्हाइट हाउस के अनुसार, एक आदेश 'बर्थ टूरिज्म' को टारगेट करता है। व्हाइट हाउस के अनुसार, बर्थ टूरिज्म का अर्थ है, किसी भी विदेशी का नॉन-इमिग्रेंट वीजा पर संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करना, जिसका उद्देश्य अमेरिकी धरती पर बच्चे को जन्म देना हो, या किसी भी विदेशी द्वारा ऐसे प्रवेश को सुविधाजनक बनाने का कोई भी प्रयास। न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, दूसरा आदेश जन्म के आधार पर नागरिकता के लिए अयोग्य लोगों की परिभाषा का विस्तार करता है। इसमें विदेशी सरकार के कर्मचारियों के बच्चे, किसी घोषित विदेशी आतंकवादी संगठन के सदस्यों के बच्चे, साथ ही ऐसे लोगों के बच्चे शामिल हैं जिन्होंने नागरिकता प्राप्त करने के लिए धोखाधड़ी की हो।

अमेरिकी संविधान का 14वां संशोधन 1868 में लागू किया गया था। 14वें संशोधन के अनुसार, 'संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्मे या वहां की नागरिकता पाने वाले सभी व्यक्ति, और जो इसके कानूनों के अधीन हैं, वे अमेरिका और उस राज्य के नागरिक होंगे जहां वे रहते हैं।'

20 जनवरी, 2025 को अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत पर राष्ट्रपति ट्रंप ने जन्मसिद्ध नागरिकता को लेकर एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे। आदेश में कहा गया कि अमेरिका में अवैध रूप से रहने वाले या अस्थायी वीजा पर मौजूद लोगों के यहां जन्मे बच्चे अमेरिकी कानूनों के दायरे में नहीं आते। इसलिए वे 14वें संशोधन या इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट के तहत नागरिकता के लिए योग्य नहीं हैं। कई माता-पिता ने शिकायत दर्ज कराई, कुछ ने अपनी तरफ से और कुछ ने अपने बच्चों की तरफ से। कई निचली अदालतों ने शिकायत करने वालों के पक्ष में फैसला सुनाया, और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कभी लागू नहीं हुआ।

30 जून को, सुप्रीम कोर्ट ने, 6-3 वोट से, ट्रंप के उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को खारिज कर दिया, जिसमें बिना डॉक्यूमेंट वाले इमिग्रेंट्स या अस्थायी निवासियों के बच्चों को बर्थराइट नागरिकता देने से मना किया गया था और बर्थराइट सिटीजनशिप को बरकरार रखा।

होर्मुज स्ट्रेट के पास ईरान की सैन्य कार्रवाई, केश्म द्वीप पर धमाकों की आवाज सुनी गई : रिपोर्ट

विश्व केसरी

तेहरान। ईरान की अर्ध-सरकारी तस्नीम न्यूज एजेंसी की ओर से साझा जानकारी के अनुसार, गुरुवार रात ईरान के होर्मोजगान प्रांत के दक्षिणी केश्म द्वीप पर दो धमाके सुने गए। एजेंसी ने बताया कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के प्रवेश द्वार पर 'शत्रुतापूर्ण लक्ष्यों' से ईरानी सशस्त्र बलों की भिड़ंत के कारण यह धमाके हुए।

तस्नीम ने सूत्रों के हवाले से बताया कि धमाकों की आवाज स्थानीय समय के हिसाब से करीब 21:40 बजे सुनी गई और कहा कि ईरानी नौसेना को इस संघर्ष में मिली कामयाबियों की घोषणा आने वाले घंटों में की जाएगी।

इसमें होर्मोजगान के पॉलिटिकल, सिक्योरिटी और सोशल मामलों के डिप्टी गवर्नर अहमद नफीसी के हवाले से यह भी कहा गया कि केशम आइलैंड और प्रोविंशियल कैपिटल बंदर अब्बास पर किसी हमले या घटना की खबर नहीं है। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी धमाकों के कारण का पता लगाने के लिए जरूरी जांच कर रहे हैं। सऊदी के अल हदथ न्यूज चैनल और अल अरबिया न्यूज चैनल ने गुरुवार को उच्च पदस्थ सूत्रों के हवाले से बताया कि ईरान और ओमान के बीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को 60 दिनों के लिए फिर से खोलने के समझौते की रूपरेखा पर सहमति बनी। न्यूज एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, सूत्रों ने कहा कि इस समझौते को अभी भी ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से मंजूरी मिलनी बाकी है और कुछ ही दिनों में इसकी घोषणा हो सकती है। इसका मकसद पानी के रास्ते में नेविगेशन फिर से शुरू करना है। स्ट्रेट में आने वाले जहाज ईरान के पास वाले रास्ते का इस्तेमाल करेंगे, जबकि बाहर निकलने वाले जहाज ओमान के पास वाले रास्ते का इस्तेमाल करेंगे। सूत्रों ने कहा कि कोई ट्रांजिट फीस या सर्विस चार्ज नहीं लगाया जाएगा और इलाके की पार्टियां माइन हटाने और टेक्निकल प्रोसेस में हिस्सा ले सकती हैं। सूत्रों ने बताया कि समझौते को मंजूरी मिलने के बाद, अमेरिका और ईरान अपने पीस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (एमओयू) पर वापस लौटेंगे और स्ट्रेट के जरिए कमर्शियल शिपिंग को फिर से खोलने और सुरक्षित नेविगेशन से जुड़े पैराग्राफ 5 को एक्टिवेट करेंगे।

संक्षिप्त खबर

अमेरिका में भारत की स्वतंत्रता का जश्न, मैसाचुसेट्स ने 15 अगस्त को 'इंडिया-डे' घोषित किया

विश्व केसरी

वॉशिंगटन। मैसाचुसेट्स की गवर्नर मौरा हीली ने 15 अगस्त को 'इंडिया-डे' घोषित किया है। यह घोषणा भारत के स्वतंत्रता दिवस और राज्य की अर्थव्यवस्था, संस्कृति तथा सार्वजनिक जीवन में भारतीय-अमेरिकियों के महत्वपूर्ण योगदान के सम्मान में की गई है।

हीली ने एक अगस्त को इस घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसमें 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता की 79वीं वर्षगांठ के सम्मान में 15 अगस्त को इंडिया डे के रूप में मान्यता दी गई। 'अमेरिकन बाजार' की रिपोर्ट के अनुसार, मैसाचुसेट्स की लेफ्टिनेंट गवर्नर किम्बर्ली ड्रिस्कॉल और कॉमनवेल्थ ऑफ मैसाचुसेट्स के सचिव विलियम फ्रांसिस गैल्विन ने भी इस घोषणा का समर्थन किया और राज्य के लोगों से 15 अगस्त को इंडिया डे के रूप में मनाने और मान्यता देने का आग्रह किया। घोषणा-पत्र में दुनिया भर में बसे भारतीय मूल के लोगों की उपस्थिति का भी उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया है कि भारत के बाहर भारतीय मूल के 3.6 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं, जिनमें से 50 लाख से ज्यादा अमेरिका में बसे हुए हैं। मैसाचुसेट्स ने यह भी स्वीकार किया कि राज्य में भारतीय समुदाय के लोगों ने उद्यमिता, सार्वजनिक सेवा, शिक्षा, नवाचार, स्वास्थ्य सेवा और वैज्ञानिक अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

भारतीय राजदूत ने जापान के रक्षा मंत्री कोईजुमी से की बात, रक्षा सहयोग की मजबूती पर दिया जोर

विश्व केसरी

टोक्यो। भारत और जापान ने शुक्रवार को दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने को लेकर चर्चा की। यह बातचीत जापान में भारत की राजदूत नगमा मलिक और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के बीच बैठक के दौरान हुई। जापान में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, 'राजदूत मलिक ने रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी से एक औपचारिक फोन कॉल पर बात की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने के मौकों पर विचारों का आदान-प्रदान किया।' कोइजुमी ने कहा कि भारत और जापान के बीच रक्षा सहयोग दोनों देशों और इस इलाके और दुनिया की शांति और स्थिरता के लिए जरूरी है। जापान के रक्षा मंत्रालय ने एक्स पर लिखा, '7 अगस्त को रक्षा मंत्री कोइजुमी को जापान में भारतीय राजदूत मलिक का कॉल आया। जापान और भारत के बीच रक्षा सहयोग, जो हिंद-प्रशांत पर आधारित है, न केवल दोनों देशों के लिए बल्कि इस इलाके और दुनिया की शांति और स्थिरता के लिए भी जरूरी है। रक्षा मंत्री और सेल्फ-डिफेंस फोर्सेज जापान और भारत के बीच रक्षा सहयोग को और गहरा करेंगे।' कोइजुमी ने राजदूत मलिक के आवास पर 16 जुलाई को एक स्वागत समारोह में भाग लिया, जिसमें दोनों पक्षों ने दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने का वचन दिया।

अमेरिका ने सोशल मीडिया वीजा की व्यापक जांच का किया बचाव, देश की सुरक्षा का दिया हवाला

विश्व केसरी

वाशिंगटन। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने विदेशी वीजा आवेदकों की व्यापक ऑनलाइन जांच का बचाव किया है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि ट्रंप सरकार सोशल मीडिया के निरीक्षण को भी वीजा कैटेगरी तक बढ़ा रहा है, जिसमें विदेशी पत्रकारों और कुछ कनाडाई और मेक्सिको के पेशेवर शामिल हैं। डेली सिग्नल ने बताया कि राज्य विभाग के एक इंटरनल मेमोरेंडम के मुताबिक आवेदकों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स सार्वजनिक करने होंगे या कॉन्सुलर ऑफिसर्स की जांच के लिए खोलने होंगे।

रिपोर्ट के अनुसार, इस बढ़ी हुई जरूरत में यूनाइटेड स्टेट्स-मेक्सिको-कनाडा एग्रीमेंट के तहत बिजनेस के लिए अमेरिका में आने वाले विदेशी मीडिया प्रतिनिधि और योग्य कनाडा और मेक्सिको के नागरिक शामिल होंगे। उन पर आश्रित भी कवर होंगे। अमेरिकी राज्य विभाग ने रिपोर्ट किए गए मेमोरेंडम की पुष्टि या खारिज नहीं किया। राज्य विभाग के एक

प्रवक्ता ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस को बताया, 'हालांकि हम कहे जा रहे इंटरनल डॉक्यूमेंट्स पर टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन ट्रंप प्रशासन अपनी वीजा प्रक्रिया के जरिए राष्ट्रीय सुरक्षा और जनसुरक्षा के सर्वोच्च मानकों को बनाए रखकर हमारे देश और हमारे नागरिकों की सुरक्षा कर रहा है।' प्रवक्ता ने आगे कहा, 'जैसा कि विदेश सचिव मार्को रुबियो ने कहा, 'वीजा एक अधिकार नहीं, बल्कि एक विशेषाधिकार है।'

विभाग ने कहा कि अमेरिका में प्रवेश चाहने वाले हर विदेशी नागरिक की पूरी जांच की जाती है। प्रवक्ता ने कहा, 'अमेरिकी राज्य विभाग में प्रवेश चाहने वाले हर विदेशी नागरिक की ज्यादा से ज्यादा जांच कर रहा है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे अमेरिका में प्रवेश की शर्तों सहित अमेरिकी कानून का सम्मान करेंगे और अमेरिकी सुरक्षा, पब्लिक सेफ्टी या राष्ट्रीय हितों के लिए खतरा पैदा नहीं करेंगे।' डेली सिग्नल ने बताया कि डिप्लोमैटिक और आधिकारिक वीजा, अस्थायी श्रमिक और ट्रेनी वीजा और एक्सचेंज विजिटर वीजा चाहने वाले आवेदकों के लिए सोशल मीडिया जांच पहले से ही जरूरी थी। कॉन्सुलर अधिकारी ऑनलाइन मौजूद जानकारी का इस्तेमाल यह पता लगाने के लिए करते हैं कि कोई आवेदक वीजा के लिए योग्य होता है या नहीं और क्या उसे कोई सुरक्षा की चिंता है। राज्य विभाग के प्रवक्ता ने कहा, 'अधिकारी सोच-समझकर फैसले लेने के लिए कई तरह के तरीके इस्तेमाल करते हैं, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा सुरक्षित रहे, धोखाधड़ी रुके और आवेदक की पूरी समीक्षा हो।'

मेक्सिको ने अमेरिका को एवोकाडो निर्यात फिर से शुरू करने के लिए सुरक्षा योजना का किया ऐलान

विश्व केसरी

मेक्सिको सिटी। मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम ने कहा कि उनकी सरकार अपराध से प्रभावित मिचोआकन राज्य में सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक योजना पर काम कर रही है। इसका मकसद अमेरिका को एवोकाडो का एक्सपोर्ट फिर से शुरू करना है, जिसे सेफ्टी की वजह से फिर से रोक दिया गया था।

न्यूज एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, गुरुवार को नेशनल पैलेस में अपनी डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस में शीनबाम ने कहा कि इस रणनीति का मकसद मिचोआकन के कुछ इलाकों में सुरक्षा को और सुनिश्चित करना है, जहां नेशनल गार्ड की मौजूदगी कम थी। साथ ही अमेरिकी अधिकारियों के साथ बातचीत भी जारी रखी जाएगी।

एक्सपोर्ट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, 'हमें उम्मीद है कि यह बहुत जल्द फिर से शुरू हो जाएगा और इसीलिए हम बातचीत कर रहे हैं और साथ ही कुछ इलाकों में सुरक्षा को मजबूत कर रहे हैं जहां गार्ड की उतनी मौजूदगी नहीं थी।' राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम ने कहा कि अमेरिका द्वारा इस इलाके के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी करने के बाद उन्होंने मिचोआकन में एवोकाडो उगाने वालों और एक्सपोर्टर्स से मुलाकात की, जो अमेरिकी मार्केट में एवोकाडो का लीडिंग प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है। उसी समय, मेक्सिको के कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अमेरिकी दूतावास के साथ जल्द से जल्द बैठक आयोजित करने की मांग की है। मंत्रालय ने प्रस्ताव दिया कि निरीक्षण कार्य फिर से शुरू किया जाए, जिसमें मेक्सिको की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सेवा के पर्यवेक्षक उपस्थित रहें। शीनबाम ने कहा कि वह इस मुद्दे को हल करने के लिए काम कर रही हैं, ताकि हम एक्सपोर्ट को वापस पटरी पर ला सकें।

डब्ल्यूएमसीसी की 36वीं बैठक : भारत और चीन ने सीमा मुद्दों पर की बातचीत

विश्व केसरी

नई दिल्ली। भारत और चीन ने सीमा निर्धारण, सीमा प्रबंधन, तंत्र निर्माण और सीमा पार सहयोग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। भारत-चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्य तंत्र (डब्ल्यूएमसीसी) की 36वीं बैठक का आयोजन 6 अगस्त को राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में किया गया।

इस बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव (पश्चिम एशिया) सुजीत घोष ने किया और चीनी प्रतिनिधिमंडल को विदेश मंत्रालय के बाउंड्री और ओशनिक अफेयर्स डिपार्टमेंट की डायरेक्टर जनरल होउ यांकी ने किया।

दोनों पक्षों ने खुलकर बातचीत की और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (एलएसी) पर हालात की समीक्षा की। इसके अलावा इस बात पर जोर दिया गया कि सीमावर्ती इलाकों में शांति बनाए रखना दोनों देशों के संबंधों के पूरे विकास के लिए जरूरी है।

दोनों पक्ष मौजूदा डिप्लोमेटिक और मिलिट्री चैनलों का इस्तेमाल जारी रखने पर सहमत हुए। इसमें डब्ल्यूएमसीसी, स्थानीय कमांडर स्तर की बैठक और दूसरे तय तरीके शामिल हैं, ताकि बाकी मुद्दों को सुलझाया जा सके और एलएसी पर गलतफहमी और गलत अंदाजे से बचा जा सके।

24वीं एसआर टॉक्स के नतीजों के बाद, दोनों पक्षों ने बाउंड्री डिलिमिटेशन, सीमा प्रबंधन, मैकेनिज्म-बिल्डिंग और ट्रांस-बॉर्डर कोऑपरेशन से जुड़े मुद्दों पर डिटेल में बातचीत की। भारतीय पक्ष ने ट्रांस-बॉर्डर नदियों पर एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म की अगली मीटिंग जल्द बुलाने की जरूरत दोहराई और अपस्ट्रीम प्रोजेक्ट्स पर टेक्निकल डिटेल्स साझा करने की अहमियत पर जोर दिया। इससे पहले 4 अगस्त को विदेश मंत्रालय ने कहा था कि भारत और चीन ने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करना और सिविल एविएशन कनेक्टिविटी फिर से शुरू करना शामिल है।

अमेरिका-ईरान में जुबानी जंग तेज, सऊदी अरब ने जताई हूती के हमले की आशंका

विश्व केसरी

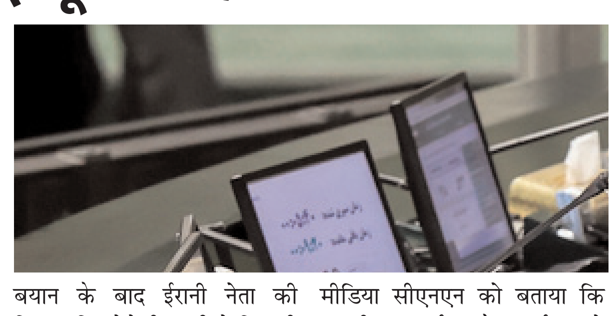

तेहरान। ईरान के मुख्य वार्ताकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर 'थिएटर डिप्लोमेसी' करने का आरोप लगाया है। दूसरी तरफ, अमेरिका दावा कर रहा है कि ईरान के साथ बातचीत अंतिम चरण में पहुंच गई है। हालांकि, ईरान इस बात से इनकार करता रहा है।

ईरान के संसदीय अध्यक्ष और शीर्ष नेगोशिएटर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में ट्रंप पर मजाक उड़ाते हुए लिखा, 'बड़ा हमला होने वाला है। रुको, कोई बात नहीं, वे बातचीत करना चाहते हैं। यह थिएटर डिप्लोमेसी का खेल है।'

हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि वह मिडिल ईस्ट के कई देशों और तेहरान की अपील के बाद ईरा पर सुनियोजित हमले को रोकने के लिए राजी हो गए हैं। ट्रंप के इस बयान के बाद ईरानी नेता की थिएटर डिप्लोमेसी वाली ये टिप्पणी सामने आई है।

इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये दावा भी किया था कि तेहरान के साथ डील की रूपरेखा पहले ही तय हो चुकी है। हालांकि, ईरानी अधिकारियों ने इस दावे को खारिज कर दिया था और कहा कि कोई बातचीत नहीं चल रही है।

इस बीच, यह संघर्ष पूरे इलाके में फैल रहा है, जिससे खाड़ी के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और मुख्य शिपिंग चोकपॉइंट्स पर नया खतरा मंडरा रहा है। इसके अलावा, एक सऊदी अधिकारी ने अमेरिकी मीडिया सीएनएन को बताया कि सऊदी अरब, ईरान के समर्थन वाले हूतियों के साथ काम कर रहे इराकी मिलिशिया समूहों के कई कोऑर्डिनेटेड हमलों के लिए तैयार है। सऊदी अरब और इलाके की सरकारों की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स से पता चला है कि इन समूहों ने ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) के गाइडेंस में बहुत जल्द देश पर हमला करने की योजना बनाया है। यह चेतावनी हूतियों के अदन की खाड़ी में दो सऊदी तेल टैंकरों पर हमलों की जिम्मेदारी लेने के एक दिन बाद आई है।

बिजली और गैस की कमी के बीच बांग्लादेश ने भारत से की अधिक डीजल सप्लाई की अपील

विश्व केसरी

ढाका। बांग्लादेश ने देश में जारी बिजली और गैस संकट से निपटने के लिए भारत से सीमा पार पाइपलाइन के जरिए डीजल आपूर्ति बढ़ाने का अनुरोध किया है।

स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, बांग्लादेश के पावर, एनर्जी और मिनरल रिसोर्स मंत्री इकबाल हसन महमूद ने ढाका में सेक्रेटेरिएट में भारतीय उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी के साथ मीटिंग के बाद रिपोर्टर्स को संबोधित करते हुए इस बात की जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि ऊर्जा सहयोग उन खास मुद्दों में से एक था जिन पर चर्चा हुई। बांग्लादेशी अखबार द बिजनेस स्टैंडर्ड ने महमूद के हवाले

से कहा, 'हम पाइपलाइन के जरिए भारत से डीजल आयात करते हैं और हमने उनसे और सप्लाई करने की अपील की है।'

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पड़ोसी देशों के तौर पर बांग्लादेश और भारत के बीच आपसी हितों के कई मामले हैं। बांग्लादेशी मंत्री ने कहा कि भारतीय राजदूत से मिलना विदेशी डिप्लोमैट्स के साथ उनके रेगुलर एंगेजमेंट का हिस्सा था।

उन्होंने कहा, 'मैं अलग-अलग देशों के राजदूत से लगातार मिलता रहता हूं। भारतीय उच्चायुक्त के साथ मीटिंग भी एक रूटीन मीटिंग थी, क्योंकि भारत हमारा पड़ोसी देश है, इसलिए हमारे कई आपसी हितों के क्षेत्र हैं और उन मुद्दों पर बात हुई।'

ड्रग्स-रोधी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एनसीबी ने की भारत-अमेरिका काउंटर नारकोटिक्स वर्किंग ग्रुप की बैठक

विश्व केसरी

नई दिल्ली। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने भारत-अमेरिका काउंटर नारकोटिक्स वर्किंग ग्रुप (सीएनडब्ल्यूजी) के 'प्रथम पिलर' वर्किंग ग्रुप की बैठक की। इस बैठक में भारत और अमेरिका की कई एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल हुए।

एनसीबी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जानकारी दी कि हाइब्रिड मोड में गुरुवार को बैठक आयोजित की गई थी। भारतीय पक्ष से एनसीबी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स (सीबीएन), डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (डीआरआई), सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (सीडीएससीओ), विदेश मंत्रालय (एईए), राजस्व विभाग और

रसायन व पेट्रो-रसायन विभाग के प्रतिनिधि शामिल थे। वहीं, अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल में ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन (डीईए), एलईजीएटी, ऑफिस ऑफ नेशनल ड्रग कंट्रोल पॉलिसी (ओएनडीसीपी) और अमेरिकी विदेश विभाग के अधिकारी शामिल थे।

एनसीबी के अनुसार, चर्चा का मुख्य फोकस परिचालन सहयोग को मजबूत करने, प्रीकर्सर केमिकल्स के गलत इस्तेमाल को रोकने, नीतिगत समन्वय को बेहतर बनाने और क्षमता निर्माण को आगे बढ़ाने पर था।

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, 'भारत ने प्रीकर्सर रसायनों के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए अपने मजबूत प्रीकर्सर नियंत्रण ढांचे तथा नियामक व प्रवर्तन तंत्र को और मजबूत करने के लिए चल रही पहलों पर बात की।'

इसी बीच, केंद्र सरकार ने इस सप्ताह लोकसभा को सूचित किया कि एनसीबी ने 27 देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों और 19 देशों के साथ समझौता ज्ञापनों के माध्यम से ड्रग कंट्रोल में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत किया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक सवाल के जवाब में कहा कि भारत म्यांमार, नेपाल, थाईलैंड, श्रीलंका, इंडोनेशिया, सिंगापुर और अमेरिका जैसे देशों के साथ ड्रग से जुड़े मामलों पर नियमित रूप से महानिदेशक (डीजी) स्तर पर द्विपक्षीय बातचीत करता है।

दिल्ली-एनसीआर में झमाझम बारिश जलभराव से जनजीवन प्रभावित

विश्व केसरी

नोएडा। दिल्ली समेत पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने शुक्रवार, 7 अगस्त के लिए तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।

बीती देर रात से ही दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद सहित एनसीआर के कई इलाकों में लगातार बारिश का दौर जारी है। सुबह के समय हुई बारिश से लोगों को उमस और गर्मी से बड़ी राहत मिली है, लेकिन कई स्थानों पर जलभराव और टूटी सड़कों में बने गड्ढों के कारण यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

लगातार दो दिनों से हो रही बारिश का असर तापमान पर भी साफ दिखाई दे रहा है। अधिकतम तापमान में करीब 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे मौसम सुहावना हो गया है। हालांकि बारिश के चलते कई प्रमुख मार्गों पर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिलीं और ऑफिस जाने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, 7 अगस्त को अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। विभाग ने दिनभर आमतौर पर बादल छाए रहने और भारी बारिश की संभावना जताई है। विशेष रूप से सुबह और पूर्वाह्न के दौरान मध्यम से भारी वर्षा होने की चेतावनी जारी की गई है, जिसके मद्देनजर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

मौसम विभाग के आगामी पूर्वानुमान के अनुसार, 8 अगस्त को अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। दिनभर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। इस दिन के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। 9 अगस्त को अधिकतम तापमान 34 डिग्री तथा न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने हल्की बारिश या बूंदाबांदी के साथ सामान्य रूप से बादल छाए रहने की संभावना जताई है।

10 अगस्त को अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इस दिन भी हल्की बारिश या बूंदाबांदी का पूर्वानुमान है और कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की गई है। 11 अगस्त को अधिकतम तापमान 33 डिग्री तथा न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। दिनभर बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश हो सकती है।

कर्नाटक सीएम से मुलाकात के बाद नाराज दिखे विधान परिषद के सभापति होरट्टी

विश्व केसरी

बेंगलुरु। कर्नाटक विधान परिषद के सभापति पद को लेकर राजनीतिक ड्रामा शुक्रवार को भी जारी रहा। इस बीच, कांग्रेस सरकार परिषद के सभापति बसवराज होरट्टी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही है।

होरट्टी ने शुक्रवार को सदाशिवनगर स्थित आवास पर मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार से मुलाकात की। हालांकि होरट्टी ने पहले घोषणा की थी कि वह 14 अगस्त को अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, लेकिन अब पता चला है कि उन्होंने पद छोड़ने से पहले और समय मांगा है।

बातचीत के बाद होरट्टी मुख्यमंत्री आवास से साफ तौर पर नाराज दिखते हुए निकले।

मुख्यमंत्री के साथ बैठक के बाद सवालों का जवाब देते हुए होराट्टी ने कहा कि वह अपने पहले के रुख पर कायम हैं। बेंगलुरु में मुख्यमंत्री आवास के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए होराट्टी ने कहा, 'मैंने जो कुछ दिन पहले कहा था, मैं उस पर कायम हूं। अगर वे अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं, तो ला सकते हैं। वे कानून के मुताबिक आगे बढ़ सकते हैं।'

खबरों के अनुसार, होरट्टी के अपने इस्तीफे पर साफ तौर पर कोई वादा न करने के कारण कांग्रेस ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी शुरू कर दी है।

सूत्रों के मुताबिक, सत्ताधारी पार्टी को इस बात की चिंता है कि होरट्टी ने चेयरमैन के तौर पर अहम फैसले लेने से पहले भाजपा नेताओं से सलाह-मशविरा करके पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया है।

खबरों के मुताबिक, कांग्रेस एमएलसी इवान डिसूजा अविश्वास प्रस्ताव के लिए नोटिस तैयार कर रहे हैं, जिसे विधान परिषद में पेश किए जाने की उम्मीद है। कांग्रेस पार्टी ने नए मंत्रियों की सूची जारी करते हुए वरिष्ठ नेता सलीम अहमद को इस पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया है।

संक्षिप्त खबर

मद्रास हाई कोर्ट ने हॉर्स-ट्रेडिंग मामले में एक और आरोपी को दी जमानत

विश्व केसरी

चेन्नई। मद्रास हाईकोर्ट ने हॉर्स ट्रेडिंग मामले में एक और आरोपी कृष्णन को जमानत दे दी है। इस मामले में जमानत पर रिहा होने वाले आरोपियों की कुल संख्या 14 हो गई है। ट्रिपलिकेन पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिन पर आरोप था कि उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए उथंगराई निर्वाचन क्षेत्र के थवेका विधायक इलैयाराजा को प्रभावित करने की कोशिश की थी। इस मामले में पूर्व डीएमके मंत्री सेंथिल बालाजी और उनके भाई अशोक कुमार को पहले ही अग्रिम जमानत मिल चुकी है। इस बीच, मद्रास हाईकोर्ट ने ट्रिपलिकेन पुलिस की जांच पर रोक लगा दी है। रोक के दौरान गिरफ्तार आरोपियों में से एक कृष्णन ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। जस्टिस जी.के. इलंथिरायण ने याचिका को मंजूरी दी और कृष्णन को जमानत दे दी। इस आदेश के साथ हॉर्स ट्रेडिंग मामले में गिरफ्तार सभी 14 लोग अब जमानत पर रिहा हो गए हैं। जज ने कार्तिकेयराजा द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई भी 1 सितंबर तक के लिए टाल दी और निर्देश दिया कि तब तक याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई न की जाए। इसके अलावा कोर्ट ने सेतुराज और राजसेकर पर लगाई गई जमानत की शर्तों में ढील दी, जिन्हें पहले इस मामले में जमानत पर रिहा किया गया था।

मोहन भागवत का युवाओं से संवाद राष्ट्र निर्माण की दिशा में अहम कदम : सतीश महाना

विश्व केसरी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने आरआरएस प्रमुख मोहन भागवत की युवाओं से बातचीत और देश की संस्कृति को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत ने अपना पूरा जीवन समाज और राष्ट्र को समर्पित किया है और वे हर मुद्दे की हकीकत को समझते हैं। सतीश महाना ने आईएएनएस से कहा, 'सरसंघचालक मोहन भागवत ने अपना पूरा जीवन समाज और राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। वे हर मुद्दे की वास्तविकता को समझते हैं। मुझे याद है जब हम बच्चे थे, मेरे पिता आरएसएस से जुड़े थे, तो हम बाल स्वयंसेवक के रूप में शाखा में जाते थे। वहीं हमने मूल्य और अनुशासन सीखा।' उन्होंने कहा, 'शाखाएं सिर्फ खेल का स्थान नहीं हैं। ये मूल्य देने का माध्यम हैं। ये लोगों को इस राष्ट्र के स्वाभिमान को पहचानने में मदद करती हैं और देश के प्रति समर्पण भाव से काम करने के लिए प्रेरित करती हैं।' सतीश महाना ने भागवत की जेन-जी से बातचीत का जिक्र करते हुए कहा, 'जब नौजवान आता है तो नई ऊर्जा के साथ आता है, उनमें एक नया जज्बा होता है। ऐसे में मोहन भागवत उनके साथ बैठे। उन्होंने उनसे बहुत सारे विषयों पर बातचीत की।' उन्होंने कहा, 'हमारा आज का नौजवान बहुत योग्य है। बहुत इनोवेटिव है। आजादी के 100 साल बाद 2047 में भारत कैसा होगा। इस नाते मोहन भागवत ने नौजवानों से बातचीत की।

राष्ट्रीय हथकरघा दिवस : सीएम भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में हैंडलूम उत्पादों की खरीदारी की

विश्व केसरी

गांधीनगर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से मनाए जा रहे राष्ट्रीय हथकरघा दिवस (नेशनल हैंडलूम डे) के अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शुक्रवार को गांधीनगर स्थित गरवी गुर्जरी स्टोर जाकर हथकरघा उत्पादों की खरीदारी की।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री की इस अपील पर गांधीनगर में राज्य सरकार के उपक्रम गरवी गुर्जरी से हैंडलूम उत्पादों की खरीदारी की। मुख्यमंत्री ने गरवी गुर्जरी के कर्मचारियों के साथ संवाद किया और बिक्री के लिए रखे गए विभिन्न हैंडलूम उत्पादों की जानकारी हासिल की।

इस अवसर पर मुख्य सचिव एमके दास तथा गुजरात राज्य हथकरघा और हस्तकला निगम गरवी गुर्जरी की प्रबंध निदेशक और सचिव आर्द्रा अग्रवाल भी मौजूद रहे। इससे पहले सीएम भूपेंद्र पटेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, ''हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, अद्भुत कला-कौशल और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ 'राष्ट्रीय हथकरघा दिवस' पर हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिए गए वोकल फोर लोकल के मंत्र को अपनाएं और स्वदेशी हथकरघा उत्पादों को खरीदने का संकल्प लें। आइए, हथकरघा क्षेत्र के कारीगरों और बुनकरों की आर्थिक समृद्धि के साथ-साथ 'आत्मनिर्भर भारत' के निर्माण में भी योगदान दें।' प्रधानमंत्री ने इस वर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के मौके पर देशवासियों से हैंडलूम उत्पाद खरीदकर ग्रामीण गरीबों की आय बढ़ाने में सहभागी होने के साथ ही अपनी समृद्ध हथकरघा बुनाई की विरासत को प्रोत्साहन देने की अपील की है। प्रधानमंत्री का लक्ष्य हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक और कलात्मकता के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार हैंडलूम उत्पादों को 'वोकल फॉर लोकल' मंत्र के जरिए दुनियाभर का बाजार उपलब्ध कराना है।

झारखंड में 14 दिन से सड़कों पर छात्र, अब जाकर राहुल गांधी ने जताई चिंता : नीरज कुमार

विश्व केसरी

पटना। झारखंड में जेपीएससी पेपर लीक के खिलाफ चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन को कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा समर्थन दिए जाने पर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने सवाल उठाए।

उन्होंने कहा, 'मैं बार-बार यह सवाल पूछ रहा था कि राहुल गांधी चुप क्यों हैं? झारखंड के इस मुद्दे पर तेजस्वी यादव चुप क्यों हैं? अगर छात्र वहां विरोध कर रहे हैं, तो वे उनसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? जब यह मुद्दा चर्चा में आया, तब राहुल गांधी ने चिंता जताई। ऐसे मुद्दों पर हमेशा चिंता करनी चाहिए और लगातार सोचना चाहिए। तभी स्थिति बेहतर होगी।'

14 दिन से छात्र सड़कों पर हैं लेकिन सरकार की तरफ से अब तक कोई बातचीत नहीं हुई है। इसको लेकर नीरज कुमार ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, 'लोकतंत्र में संवाद को सबसे बड़ी पूंजी माना गया है। देश का संविधान ही नहीं, महात्मा बुद्ध और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी संवाद को ही जीवन का केंद्र बिंदु मानते थे। छात्र की समस्या हो या सरकारी कर्मी की समस्या हो या किसानों की समस्या हो, न आंदोलन करने वाला हठधर्मी होना चाहिए, न सरकार को हठधर्मी होना चाहिए। दोनों पक्ष को लचीला होकर देश की आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति के आधार पर नीतियों को तय करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पेपर लीक छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। ऐसे में सरकार को तुरंत छात्रों से बात करके सुदृढ़ परीक्षा प्रणाली बनानी चाहिए।' आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के आरक्षण संबंधी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए नीरज कुमार ने कहा कि आरक्षण अपने आप में जरूरी है, लेकिन इसका मूल्यांकन भी होना चाहिए। उन्होंने कहा, 'आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जिसने आजादी के दशकों बाद भी सभी सामाजिक समस्याओं का समाधान नहीं किया है।

हस्तशिल्प विश्वविद्यालय की दिशा में काम जारी, बुनकरों-शिल्पकारों को मिलेगी नई पहचान : राज्यपाल आनंदीबेन पटेल

विश्व केसरी

लखनऊ। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि प्रदेश में हस्तशिल्प विश्वविद्यालय की स्थापना की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इससे बुनकरों, शिल्पकारों और उनके बच्चों को शिक्षा, कौशल विकास तथा रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।

उन्होंने कहा कि पारंपरिक शिल्प को वैश्विक पहचान दिलाने और कारीगरों की आजीविका सुदृढ़ करने के लिए सरकार और विभिन्न संस्थाएं मिलकर काम कर रही हैं। राजभवन स्थित जनभवन में आयोजित राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के दौरान राज्यपाल ने नाबार्ड के सहयोग से बागपत, वाराणसी, भदोही, मिर्जापुर, बाराबंकी, आजमगढ़, कानपुर, लखनऊ, फर्रुखाबाद, लखीमपुर खीरी, बिजनौर, हापुड़ और उन्नाव समेत प्रदेश के 13 जिलों के बुनकरों एवं शिल्पकारों की हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प प्रदर्शनी का अवलोकन किया।

उन्होंने हस्तनिर्मित वस्त्रों और उत्पादों की गुणवत्ता, कलात्मकता तथा पारंपरिक शिल्पकला की सराहना करते हुए प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। राज्यपाल ने बुनकरों और शिल्पकारों से संवाद कर उनके उत्पादों के विपणन, बिक्री और आजीविका से जुड़े मुद्दों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि कारीगरों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए 'क्राफ्ट्स रूट्स' संस्था निरंतर कार्य कर रही है। प्रदेश के विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोहों में 17 हस्तशिल्पियों को डी.लिट. की मानद उपाधि प्रदान की जा चुकी है। इससे स्थानीय शिल्प को नई पहचान मिली है और कारीगरों का सम्मान भी बढ़ा है। आनंदीबेन पटेल ने बताया कि पूर्वांचल में 'ग्रीन आर्मी' से जुड़ी करीब 2,500 महिलाएं पर्यावरण संरक्षण और आजीविका संवर्धन का उल्लेखनीय कार्य कर रही हैं।

महिलाओं के हाथों तैयार हो रहा तिरंगा, 'हर घर तिरंगा' अभियान को मिल रही नई रफ्तार

विश्व केसरी

कानपुर। 'हर घर तिरंगा' अभियान को इस बार कानपुर देहात की महिलाएं अपने हाथों से रंग दे रही हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े 96 स्वयं सहायता समूहों की 360 महिलाएं दिन-रात मेहनत कर करीब तीन लाख तिरंगे तैयार कर रही हैं।

यह पहल सिर्फ अभियान को मजबूती नहीं दे रही बल्कि गांव की गरीब, विधवा, दिव्यांग और कम पढ़ी-लिखी महिलाओं के लिए रोजगार और आत्मनिर्भरता का जरिया भी बन गई है। कानपुर देहात में 'हर घर तिरंगा' अभियान पूरे उत्साह के साथ चल रहा है। जिले की 360 महिलाएं झंडा बनाने में जुटी हैं। हर तिरंगा 30 इंच लंबा और 20 इंच चौड़ा बनाया जा रहा है। सरकार ने इसकी निर्धारित कीमत 20 रुपए रखी है। तैयार होने वाले ये तिरंगे जिले के स्कूलों, सरकारी कार्यालयों और सभी सरकारी भवनों पर लगाए जाएंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अधिकारियों के मुताबिक जिले को करीब तीन लाख तिरंगे बनाने का लक्ष्य मिला था, जिसे महिलाएं तय समय में पूरा करने में लगी हैं।

उमंग स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष प्रतिमा सिंह ने आईएएनएस से कहा कि विभाग का मकसद ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को रोजगार देना और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करना है, ताकि आत्मनिर्भर भारत के साथ आत्मनिर्भर महिलाएं भी तैयार हो सकें। कभी जो महिलाएं घर की चारदीवारी तक सीमित थीं, आज वे अपने हुनर से पहचान बना रही हैं। स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर वे हर महीने अच्छी आय कमा रही हैं और परिवार की जिम्मेदारियां भी निभा रही हैं।

मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने 'राष्ट्रीय हथकरघा दिवस' पर बुनकरों की रचनात्मकता की सराहना की

विश्व केसरी

हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी और राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने शुक्रवार को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर राज्य के बुनकरों को बधाई दी।

गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि तेलंगाना के बुनकरों की लगन, कौशल और रचनात्मकता को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। एक संदेश में गवर्नर ने हथकरघा को भारत की सांस्कृतिक विरासत का गौरवपूर्ण प्रतीक बताया और तेलंगाना के बुनकरों की तारीफ करते हुए उन्हें कुशल कारीगर कहा, जिनकी लगन, हुनर और रचनात्मकता को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। उन्होंने कहा कि पोचमपल्ली इकत, गडवाल, नारायणपेट, सिरसिल्ला और कोठाकोटा जैसी मशहूर हथकरघा परंपराएं तेलंगाना की समृद्ध कपड़ा विरासत को दर्शाती हैं।

गवर्नर ने कहा, 'हमारे बुनकर हमारी संस्कृति के संरक्षक हैं। उनकी कारीगरी ने हमारी विरासत को संजोकर रखा है और तेलंगाना की हथकरघा परंपरा को स्थायी पहचान दिलाई है।' उन्होंने लोगों से यह भी अपील की कि वे हाथ से बुने हुए उत्पादों को चुनकर और बुनकर समुदाय की अथक मेहनत का सम्मान करके हथकरघा क्षेत्र को प्रोत्साहित और समर्थित करें। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हथकरघा बुनकरों और कामगारों को बधाई देते हुए कहा कि हथकरघा एक महान विरासत है, जो दुनिया के सामने भारतीय संस्कृति और परंपराओं की भव्यता को प्रदर्शित करती है। मुख्यमंत्री रेड्डी ने कहा कि उनकी सरकार हथकरघा बुनकरों और कारीगरों की मेहनत, कला और रचनात्मकता का सम्मान करने, उनकी आजीविका को मजबूत करने और हथकरघा क्षेत्र को और विकसित करने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है।

जम्मू में रेजिडेंसी रोड-हाई स्ट्रीट प्रोजेक्ट का उद्घाटन, व्यापार और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

विश्व केसरी

जम्मू। जम्मू शहर को आधुनिक और पर्यटक अनुकूल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज जम्मू में अपग्रेड किए गए रेजीडेंसी रोड-हाई स्ट्रीट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इस प्रोजेक्ट के तहत सड़कों को चौड़ा और बेहतर किया गया है। आधुनिक स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं, पैदल यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं दी गई हैं और शहरी बुनियादी ढांचे को पूरी तरह से सुधारा गया है।

उद्घाटन कार्यक्रम में मौजूद भाजपा विधायक युद्धवीर सेठी ने आईएएनएस से बात करते हुए इस प्रोजेक्ट की सराहना की। उन्होंने कहा, 'मैं जम्मू पुराने शहर के निवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज सीएम उमर अब्दुल्ला द्वारा यहां उद्घाटन किया गया। जो पिछले दो वर्षों से रेजीडेंसी रोड से बाजार तक का काम चल रहा था, आज उसका उद्घाटन किया गया है। अब सीटी जोन से पुरानी मंडी तक का काम चल रहा है।' युद्धवीर सेठी ने आगे कहा, 'हम जम्मू को इतना सुंदर बनाना चाहते हैं कि व्यापारियों के दिल से डर निकल जाए। पहले लोगों को लगता था पता नहीं टूरिस्ट आएंगे या नहीं। हम इसी मुहिम पर काम कर रहे हैं कि जम्मू शहर को अपग्रेट करके यहां व्यापार के नए साधन बनाए जाएं।'

उन्होंने जम्मू को मंदिरों का शहर बताते हुए कहा कि यहां धार्मिक पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। यह मंदिरों का शहर है, हमारा जम्मू इसी से जाना जाता है। मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए भी करोड़ों रुपये आ चुके हैं। जल्द से जल्द मंदिरों के काम भी यहां शुरू करवाएंगे। इससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय व्यापारियों को भी फायदा होगा। काम भी यहां शुरू करवाएंगे।

व्हाट्सएप मैलवेयर हमले से 10,000 से अधिक भारतीयों को बचाया गया : सरकार

विश्व केसरी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को बताया कि भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) की समन्वित कार्रवाई के जरिए व्हाट्सऐप अकाउंट हैक करने वाले एक बड़े मैलवेयर अभियान से 10,000 से अधिक भारतीयों को सुरक्षित बचाया गया है। गृह मंत्रालय (एमएचए) ने कहा कि सहयोग पोर्टल के माध्यम से कमांड एंड कंट्रोल (सी2) सर्वरों को जियो-ब्लॉक करने सहित कई कदम उठाए गए, जिससे इस साइबर हमले के प्रभाव को रोका जा सका।

गृह मंत्रालय के अनुसार, राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) पर हाल के दिनों में व्हाट्सऐप अकाउंट टेकओवर से जुड़ी शिकायतों में तेज वृद्धि दर्ज की गई है। ये हमले ऐसे मैलवेयर के जरिए किए जा रहे हैं, जिन्हें अकाउंट स्टेटमेंट या किसी सरकारी नियामक संस्था के आधिकारिक दस्तावेज के रूप में छिपाकर भेजा जाता है।

मंत्रालय ने कहा, 'इन समन्वित प्रयासों के माध्यम से अब तक 10,000 से अधिक भारतीयों को इस साइबर अभियान से सुरक्षित किया गया है। सहयोग पोर्टल के जरिए मैलवेयर से जुड़े सर्वरों को लगातार ब्लॉक किया जा रहा है।'

गृह मंत्रालय के मुताबिक, इस तरह की घटनाएं दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान समेत कई राज्यों में सामने आई हैं। आई4सी ने इससे पहले 22 जून को भी एक एडवाइजरी जारी कर लोगों को ऐसे साइबर हमलों के प्रति सतर्क किया था, जिनमें सरकारी या नियामक अधिकारियों का रूप धारण कर व्हाट्सऐप अकाउंट पर कब्जा करने की कोशिश की जाती है।

मंत्रालय ने बताया कि साइबर अपराधी आमतौर पर व्हाट्सऐप, एसएमएस या ई-मेल के माध्यम से 'स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट.जिप', 'आरबीआई.जिप' या 'एमसीए.जिप' जैसे नामों वाली संपीड़ित (.जिप) फाइलें भेजते हैं। कई मामलों में फाइलों के नाम के आगे तारीख भी लिखी होती है, ताकि वे अधिक विश्वसनीय दिखाई दें। ये संदेश इस तरह तैयार किए जाते हैं कि वे किसी बैंक खाते के विवरण, वित्तीय दस्तावेज या किसी नियामक संस्था की तत्काल सूचना जैसे प्रतीत हों। इससे लोग बिना सोचे-समझे फाइल खोल लेते हैं।

मंत्रालय ने बताया, 'जब कोई व्यक्ति अपने विंडोज डेस्कटॉप या लैपटॉप पर इन जिप (जेडआईपी) फाइलों को एक्सट्रैक्ट कर खोलता है, तो उसके सिस्टम में एक ट्रोजन मैलवेयर इंस्टॉल हो जाता है जो डिवाइस को हैक कर लेता है और पीड़ित के सक्रिय व्हाट्सऐप वेब सेशन को हाईजैक कर लेता है।'

मंत्रालय ने यह भी बताया कि कई मामलों में साइबर अपराधी आयकर विभाग के नाम से फर्जी ई-मेल भी भेज रहे हैं, ताकि लोगों को भ्रमित किया जा सके।

ई-कोर्ट्स परियोजना से न्याय व्यवस्था में बड़ा बदलाव, 2014 के बाद मामलों की फाइलिंग और निपटान तीन गुना बढ़ा

विश्व केसरी

नई दिल्ली। भारत में ई-कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना ने कागज आधारित न्यायिक व्यवस्था को डिजिटल और ट्रैक करने योग्य न्याय वितरण प्रणाली में बदल दिया है। इसकी मदद से 2014 के बाद से मामलों की फाइलिंग और निपटान दोनों में लगभग तीन गुना वृद्धि हुई है। साथ ही अदालतें हर वर्ष दर्ज होने वाले मामलों की तुलना में अधिक मामलों का निपटारा कर रही हैं।

सरकार द्वारा शुक्रवार को जारी फैक्टशीट के अनुसार, कोर्ट के रिकॉर्ड के 753 करोड़ से ज्यादा पन्नों को डिजिटाइज किया गया है, जबकि हजारों ई-सेवा केंद्र न्यायिक सेवाओं तक पहुंच बढ़ाकर डिजिटल अंतर को कम करने में मदद कर रहे हैं। ये सभी सुधार मिलकर न्याय व्यवस्था को तेज, ज्यादा पारदर्शी और सभी के लिए ज्यादा सुलभ बना रहे हैं।

भारत की न्यायपालिका, जो एक अरब से ज्यादा लोगों की सेवा करती है। लंबे समय से कागजी रिकॉर्ड और पारंपरिक बुनियादी ढांचे पर निर्भर रही है। कई नागरिकों को अपने मामलों और दस्तावेजों के लिए अदालतों और अन्य दफ्तरों के चक्कर लगाने में बहुत ज्यादा यात्रा और अन्य खर्च उठाने पड़ते थे। इस पुराने सिस्टम की वजह से लोगों को न्याय मिलने में देरी होती थी। यह प्रक्रिया मुश्किल और महंगी थी। अपने तीसरे चरण में ई-कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके न्यायिक व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया है।

पहले चरण (2011-2015) ने 14,000 से ज्यादा अदालतों को कंप्यूटराइज करके और टेक्नोलॉजी-आधारित न्यायिक सेवाओं के लिए जरूरी बुनियादी नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर इस मिशन की नींव रखी।

दूसरे चरण (2015-2023) में नागरिकों पर केंद्रित कई सेवाओं के साथ इसे और आगे बढ़ाया गया। इसमें नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड, ई-फाइलिंग और ई-सेवा केंद्र (डिजिटल कोर्ट सेवाएं देने वाला एक फिजिकल हेल्प डेस्क) शुरू किए गए। फैक्टशीट के अनुसार, इस फेज में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को पांच गुना से ज्यादा बढ़ाया गया, जिससे अदालती कार्यवाही तक वर्चुअल पहुंच में काफी सुधार हुआ। यह प्रोजेक्ट अब अपने तीसरे चरण (2023-2027) में है।

वित्त मंत्री ने यूपीआई शुल्क संबंधी दावों को किया खारिज, जयराम रमेश पर अफवाह

विश्व केसरी

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश द्वारा कराधान एवं अन्य विधियां (संशोधन) विधेयक, 2026 की आलोचना पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें यूपीआई लेनदेन से संबंधित प्रस्तावित परिवर्तनों के बारे में 'अफवाह' फैलाने से बचना चाहिए।

रमेश के आरोपों का जवाब देते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने स्पष्ट किया कि व्यापारी छूट दर (एमडीआर) केवल व्यापारियों पर लागू होती है, न कि अंतिम उपयोगकर्ताओं या ग्राहकों पर।

मंत्री ने कहा कि इस कदम से बैंकों और फिनटेक कंपनियों को बुनियादी ढांचे, नवाचार और सुरक्षा में अधिक निवेश करने में मदद मिलेगी, जिससे अंततः सभी यूपीआई उपयोगकर्ताओं को इन निवेशों का लाभ मिलेगा।

उन्होंने जयराम रमेश को संबोधित करते हुए कहा कि अफवाह फैलाने से पहले कृपया इस पर विचार करें कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) केवल व्यापारियों पर लागू होता है, न कि अंतिम उपयोगकर्ताओं/ग्राहकों पर। इससे बैंकों और फिनटेक कंपनियों को बुनियादी ढांचे, नवाचार और सुरक्षा में अधिक निवेश करने में मदद मिलेगी। यूपीआई के सभी उपयोगकर्ता इस निवेश का लाभ उठाएंगे।

वित्त मंत्री सीतारमण ने संसद के बाहर इस मुद्दे को उठाने के लिए कांग्रेस की आलोचना भी की। मंत्री ने कहा कि यदि पार्टी ने लोकसभा और राज्यसभा में विधेयक पेश होने के समय रचनात्मक रूप से भाग लिया होता, तो इस मामले पर सदन में चर्चा की जा सकती थी।

वित्त मंत्री सीतारमण ने आगे कहा कि यदि आपकी पार्टी विधेयक पेश होने के समय संसद में रचनात्मक रूप से भाग लेती, तो इन सभी मुद्दों पर सदन में चर्चा हो सकती थी। इससे पहले, जयराम रमेश ने आरोप लगाया था कि प्रस्तावित संशोधन उस वैधानिक गारंटी को हटा देता है जिसके तहत यूपीआई लेनदेन शुल्क मुक्त रहे हैं, जिससे भविष्य में डिजिटल भुगतानों पर एमडीआर (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) लगाने का रास्ता खुल जाता है।

कांग्रेस नेता ने सरकार के इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि यूपीआई को आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाने के लिए एमडीआर लगाना आवश्यक है।

उन्होंने तर्क दिया कि भारतीय रिजर्व बैंक के पास व्यापारियों या उपभोक्ताओं पर कोई अतिरिक्त बोझ डाले बिना देश के डिजिटल भुगतान बुनियादी ढांचे को समर्थन देने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन हैं। उन्होंने 2025-26 में केंद्र को आरबीआई द्वारा हस्तांतरित 2.86 लाख करोड़ रुपए के अधिशेष का हवाला दिया।

बच्चों की सेहत के लिए जरूरी हैं फल और सब्जियां, उम्र के हिसाब से दें सही मात्रा

विश्व केसरी

नई दिल्ली। बच्चों की अच्छी सेहत और सही विकास के लिए फल और सब्जियां बहुत जरूरी हैं। छोटी उम्र में बच्चे जो खाना सीखते हैं, उसका असर उनकी आगे की खाने की आदतों पर भी पड़ता है। इसलिए शुरुआत से ही बच्चों को अलग-अलग तरह की सब्जियां और फल खिलाने की कोशिश करनी चाहिए।

बच्चों के लिए फल और सब्जियां तैयार करते समय उन्हें छोटे और आसानी से खाने लायक टुकड़ों में काटना अच्छा रहता है। इन्हें छोटे-छोटे कंटेनर में पहले से तैयार करके रखा जा सकता है, ताकि बच्चे को भूख लगने पर तुरंत हेल्दी स्नैक दिया जा सके। बच्चे को कितनी मात्रा में फल और सब्जियां चाहिए, यह उसकी उम्र और शारीरिक गतिविधि पर निर्भर करता है। सामान्य तौर पर 12 से 23 महीने के बच्चों को रोजाना करीब एक सर्विंग (करीब 75-100 ग्राम) फल और लगभग सवा सर्विंग (तीन चौथाई कप) सब्जियों की जरूरत हो सकती है। वहीं 2 से 4 साल की उम्र में करीब एक से डेढ़ सर्विंग (एक से डेढ़ कप कटे हुए) फल और लगभग सवा से पौने दो सर्विंग सब्जियां दी जा सकती हैं।

बच्चों की प्लेट को जितना रंग-बिरंगा बनाया जाए, उतना ही उन्हें अलग-अलग खाद्य पदार्थ आजमाने में रुचि हो सकती है। इसे आप रेनबो प्लेट की तरह बना सकते हैं। बच्चों की प्लेट में गाजर, मटर, पालक, शकरकंद और चुकंदर जैसी सब्जियां शामिल की जा सकती हैं। फलों में केला, स्ट्रॉबेरी, नाशपाती, संतरा, खरबूजा और एवोकाडो जैसे विकल्प दिए जा सकते हैं, हालांकि सिर्फ फल और सब्जियां ही पर्याप्त नहीं हैं। बच्चों की डाइट में प्रोटीन, डेयरी और साबुत अनाज जैसे दूसरे पोषक खाद्य पदार्थ भी शामिल होने चाहिए। जब बच्चा करीब 6 महीने का हो जाए, तब आमतौर पर मां के दूध या शिशु फॉर्मूला के साथ दूसरे खाद्य पदार्थों की शुरुआत की जा सकती है।

मानसून में भूलकर भी न खाएं ये चीजें, छोटी सी गलती से बिगड़ सकती है सेहत

विश्व केसरी

नई दिल्ली। बारिश का मौसम आते ही गर्मी से राहत मिलती है, लेकिन इस मौसम में सेहत को लेकर थोड़ी सावधानी रखना भी जरूरी होता है। बारिश के दिनों में हवा में नमी ज्यादा होती है, जिसके कारण बैक्टीरिया और कीटाणु तेजी से बढ़ने लगते हैं। यही वजह है कि इस समय पेट दर्द, उल्टी, दस्त, गैस और खाने से होने वाली बीमारियों के मामले बढ़ जाते हैं।

मानसून में हमारा पाचन तंत्र भी थोड़ा कमजोर होता है, इसलिए इस मौसम में ऐसा खाना खाना चाहिए जो साफ, ताजा और आसानी से पच सके। कुछ ऐसी चीजें हैं, जिनसे बारिश के मौसम में बचना चाहिए।

हरी पत्तेदार सब्जियां- पालक, मेथी, बथुआ और दूसरी हरी सब्जियां शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं। इनमें आयरन, फाइबर और कई जरूरी विटामिन पाए जाते हैं, जो शरीर को ताकत देते हैं और खून बनाने में मदद करते हैं। लेकिन बारिश के मौसम में इन सब्जियों में मिट्टी, छोटे कीड़े और गंदगी ज्यादा चिपक सकती है। नमी के कारण इनमें कीटाणु भी बढ़ सकते हैं। इसलिए अगर हरी सब्जियां खानी हैं तो उन्हें अच्छी तरह धोकर और पूरी तरह पकाकर ही खाएं। अधपकी या ठीक से साफ न की गई सब्जियां पेट की परेशानी बढ़ा सकती हैं।

खुले में रखे फल और स्ट्रीट फूड- बारिश में सड़क किनारे मिलने वाले कटे हुए फल, चाट, गोलगप्पे और दूसरी खुली चीजों को खाने से बचना चाहिए। खुले में रखे खाने पर मक्खियां बैठती हैं और धूल-मिट्टी भी जमा होती है। ऐसे खाने में कीटाणु पहुंचने का खतरा रहता है, जिससे पेट खराब, उल्टी या दस्त जैसी समस्या हो सकती है। फलों को घर लाकर अच्छी तरह धोकर खाएं।

बहुत ज्यादा ठंडी चीजें- बारिश के मौसम में आइसक्रीम, बर्फ वाले पेय और बहुत ठंडी चीजें खाने का मन करता है। हालांकि, ज्यादा ठंडी चीजें कुछ लोगों में गले की परेशानी, खांसी या पेट की समस्या बढ़ा सकती हैं।

तली हुई चीजें- बारिश में पकौड़े, समोसे और कचौड़ी खाने का मजा अलग होता है। लेकिन इनमें तेल की मात्रा ज्यादा होती है। ज्यादा तेल वाला खाना पचने में समय लेता है और गैस, एसिडिटी या पेट भारी होने की समस्या पैदा कर सकता है। इसलिए मानसून में तली हुई चीजें कभी-कभी और कम मात्रा में खाना बेहतर होता है।

बासी खाना- बारिश के मौसम में खाना जल्दी खराब होता है। कई लोग बचे हुए खाने को दोबारा गर्म करके खा लेते हैं, लेकिन ऐसा खाना हमेशा सुरक्षित नहीं होता। लंबे समय तक रखा हुआ खाना खाने से पेट में संक्रमण हो सकता है। कोशिश करें कि हर बार ताजा बना हुआ खाना ही खाएं।

दूध और मिठाई- दूध, मिठाई और क्रीम वाली चीजें जल्दी खराब हो सकती हैं। बारिश में नमी ज्यादा होने के कारण इनमें कीटाणु बढ़ने का खतरा रहता है। खुले में रखी मिठाई या लंबे समय से रखे डेयरी उत्पाद खाने से बचें। हमेशा ताजे और अच्छी तरह रखे हुए सामान का ही इस्तेमाल करें।

हनुमानासन : पैरों, कूल्हों और जांघों की जकड़न करता है दूर

विश्व केसरी

नई दिल्ली। दफ्तर में लगातार डेस्क पर बैठे रहने से कमर में दर्द और पैरों की मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं। योग के अनेक आसनों में से एक हनुमानासन प्रभावी माना जाता है। इस आसन के नियमित अभ्यास से शरीर का निचला भाग मजबूत और लचीला बनता है।

यह आसन हठयोग का अत्यंत प्रभावी और उन्नत श्रेणी का आसन हैं। ऐसी मान्यता है कि इस आसन का नाम भगवान हनुमान के उस विशाल छलांग से लिया गया, जो उन्होंने सीता माता की खोज में लंका जाने के लिए लगाई थी।

आयुष मंत्रालय के अनुसार, हनुमानासन (स्प्लिट्स पोज) शरीर के लचीलेपन और संतुलन को बढ़ाने वाला एक उन्नत आसन है। यह आसन शरीर की लचक बढ़ाने में मदद करता है और खासकर पेल्विक मसल्स को ताकत देता है। यह आसन पैरों, कूल्हों और जांघों की जकड़न को खोलता है और पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार करता है। नियमित अभ्यास से न सिर्फ शारीरिक शक्ति बढ़ती है, बल्कि मन में एकाग्रता और धैर्य भी आता है। आइए जानते हैं हनुमानासन करने की सही विधि, फायदे और सावधानियां।

इस आसन को करने से शरीर में रक्त प्रवाह का संचार होता है, जिन लोगों के शरीर में रक्त प्रवाह सही से नहीं होता, वे इसका रोजाना अभ्यास कर सकते हैं। साथ ही, यह पेट की मांसपेशियों को टाइट बनाता है, अतिरिक्त चर्बी को घटाता है, नितंबों और जांघों की चर्बी को कम करने में यह आसन बहुत फायदेमंद है।

हनुमानासन को करने के लिए सबसे पहले जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाएं। दाएं पैर को आगे की ओर बढ़ाएं और सीधा रखें, हाथों का सहारा लेकर धीरे-धीरे दाएं पैर को आगे और बाएं पैर को पीछे खिसकाएं। अब शरीर के वजन को हाथों से संभालते हुए कूल्हों को नीचे जमीन की तरफ लाएं। दोनों पैर जमीन पर पूरी तरह सीधे और एक सीध में होने चाहिए। संतुलन बनने पर हथेलियों को छाती के आगे जोड़ लें। सबसे पहले जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाएं। रीढ़ सीधी रखें। दाएं पैर को आगे की ओर सीधा बढ़ाएं। हाथों को जमीन पर टिकाकर सहारा लें। धीरे-धीरे दाएं पैर को आगे और बाएं पैर को पीछे खिसकाएं। शरीर का वजन हाथों पर रखें। अब कूल्हों को धीरे-धीरे नीचे जमीन की तरफ ले जाएं। दोनों पैर जमीन पर पूरी तरह सीधे और एक सीध में हों।

माइग्रेन के दर्द को बढ़ा सकती हैं ये 5 गलतियां, छोटी-छोटी आदतों में बदलाव से मिलेगी राहत

विश्व केसरी

नई दिल्ली। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सिरदर्द एक आम समस्या बन गई है, लेकिन हर सिरदर्द सामान्य नहीं होता। कुछ लोगों को बार-बार होने वाला तेज दर्द, रोशनी और आवाज से परेशानी, जी मिचलाना या कमजोरी जैसी समस्याएं महसूस होती हैं, जिसे माइग्रेन कहा जाता है। यह सिर्फ सिर में दर्द की स्थिति नहीं है, बल्कि यह शरीर के तंत्रिका तंत्र से जुड़ी एक जटिल समस्या है।

विशेषज्ञों के अनुसार, माइग्रेन का दर्द कई बार हमारी रोजमर्रा की आदतों से भी प्रभावित होता है। गलत खान-पान, नींद की कमी, तनाव, शरीर में पानी की कमी और जीवनशैली की कुछ गलत आदतें इसके लक्षणों को बढ़ा सकती हैं। यही वजह है कि माइग्रेन से पीड़ित लोगों को अपनी दिनचर्या में कुछ सावधानियां बरतने की सलाह दी जाती है। आइए जानते हैं ऐसी कौन-सी गलतियां हैं, जो माइग्रेन के दौरान परेशानी को और बढ़ा सकती हैं।

शरीर में पानी की कमी - माइग्रेन के समय शरीर में पानी की कमी होना दर्द को बढ़ाने वाले कारणों में शामिल हो सकता है। जब शरीर को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलता, तो शरीर के सामान्य कामकाज पर असर पड़ सकता है और थकान, चक्कर या सिर में भारीपन जैसी समस्याएं महसूस हो सकती हैं। पानी शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने और कोशिकाओं को सही तरीके से काम करने में मदद करता है। इसलिए दिनभर थोड़ी-थोड़ी मात्रा में पानी पीते रहना जरूरी है। पानी के अलावा नारियल पानी, सूप या पानी से भरपूर फल भी शरीर में तरल पदार्थों की कमी पूरी करने में मदद करते हैं।

नींद के साथ लापरवाही करना- माइग्रेन और नींद का संबंध काफी गहरा माना जाता है। कम सोना या रोज अलग-अलग समय पर सोना शरीर की प्राकृतिक घड़ी को प्रभावित कर सकता है, जिससे कुछ लोगों में माइग्रेन का खतरा बढ़ सकता है।

चेसः आर प्रज्ञानानंद ने जीता सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्ज का खिताब

एजेंसी ■

सेंट लुइस। भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानानंद ने एक राउंड बाकी रहते हुए ही ग्रैंड चेस टूर सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्ज का खिताब अपने नाम किया।

प्रज्ञानानंद और उज्बेकिस्तान के जावोखिर सिंदारोव के बीच आखिरी मुकाबले का अंत ड्रॉ पर होने के साथ ही भारतीय ग्रैंडमास्टर का खिताब पक्का हो गया। 20 साल के भारतीय खिलाड़ी ने कुल 35 में से 23 प्वाइंट हासिल करके चैंपियनशिप को अपने नाम किया। शानदार टूर्नामेंट के बाद सिंदारोव ने 22 प्वाइंट के साथ दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि वेस्ली सो 20.5 प्वाइंट के साथ तीसरे स्थान पर रहे।

लेवोन अरोनियन 19 प्वाइंट के साथ चौथे स्थान पर रहे, और फैबियानो कारुआना, लीनियर डोमिंग्वेज और जॉर्डन वैन फॉरेस्ट 17 प्वाइंट के साथ संयुक्त रूप से पांचवें स्थान पर रहे। प्रज्ञानानंद को बिना किसी प्लेऑफ के सीधे जीत हासिल करने पर 50,000 अमेरिकी डॉलर और 13 ग्रैंड चेस टूर प्वाइंट मिले। इस नतीजे से प्रज्ञानानंद सिंकफील्ड कप से पहले ग्रैंड चेस टूर स्टैंडिंग में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। हालांकि फैबियानो अभी भी ओवरऑल ग्रैंड चेस टूर स्टैंडिंग में सबसे आगे हैं।

प्रज्ञानानंद ने पांच दिन के इस इवेंट में शुरू से आखिर तक बढ़त बनाए रखी। सिंदारोव ने आखिरी दौर में कड़ी चुनौती पेश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए और 1.5 प्वाइंट के अंतर से उपविजेता रहे। जून में, प्रज्ञानानंद प्रतिष्ठित नॉर्वे चेस खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रच चुके हैं।

सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्ज टूर्नामेंट में 31 जुलाई से 7 अगस्त तक सेंट लुइस चेस क्लब में दस बेहतरीन ग्रैंडमास्टर शामिल हुए। पांच दिनों के खेल में, खिलाड़ियों ने 9 रैपिड राउंड और 18 ब्लिट्ज राउंड खेले। इस दौरान कुल मिलाकर 135 गेम हुए, जिनमें सिंकफील्ड कप और जीसीटी ग्रैंड फाइनल से पहले महत्वपूर्ण टूर प्वाइंट दांव पर थे।

इस टूर्नामेंट में दो तेज गति वाले फॉर्मेट शामिल रहे। 9-राउंड का सिंगल राउंड-रॉबिन रैपिड टूर्नामेंट (जो 25 मिनट के टाइम कंट्रोल और पहली चाल से ही 10-सेकंड के इंक्रीमेंट के साथ खेला जाता है) और 18-राउंड का डबल राउंड-रॉबिन ब्लिट्ज टूर्नामेंट (जो 5 मिनट के टाइम कंट्रोल और पहली चाल से ही 2-सेकंड के इंक्रीमेंट के साथ खेला जाता है)। रैपिड में जीत पर 2 पॉइंट और ड्रॉ पर 1 प्वाइंट मिलता है, जबकि ब्लिट्ज में जीत पर 1 प्वाइंट और ड्रॉ पर 0.5 प्वाइंट मिलता है।

एएचएफ जूनियर एशिया कप 2026 के लिए भारतीय पुरुष टीम का ऐलान, अनमोल एक्का बने कप्तान

विश्व केसरी ■

नई दिल्ली। हॉकी इंडिया ने शुक्रवार को एएचएफ जूनियर एशिया कप 2026 के लिए भारतीय पुरुष टीम का ऐलान कर दिया है। चीन के मोकी में 30 अगस्त से 13 सितंबर तक होने वाले इस टूर्नामेंट के लिए 18 खिलाड़ियों का चुनाव किया गया है, जबकि दो वैकल्पिक प्लेयर्स को भी टीम में रखा गया है। टीम की कमान अनमोल एक्का के हाथों में सौंपी गई है।

डिफेंडर अनमोल एक्का की कप्तानी वाली यह टीम अभी बेंगलुरु में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (साई) सेंटर में नए कोच फ्रेडरिक सोयेज की देखरेख में ट्रेनिंग कर रही है। टूर्नामेंट की तैयारी के हिस्से के तौर पर टीम ने हाल ही में बेल्जियम का एक शानदार एक्सपोजर दौरा पूरा किया, जहां टीम की भिड़ंत मजबूत इंटरनेशनल टीमों से हुई थी। इस दौरे से खिलाड़ियों को मैच का कीमती अनुभव और अहम सीख मिली, जिससे टीम अपनी प्रगति का आकलन कर सकी, अपने कॉम्बिनेशन को बेहतर बना सकी और एएचएफ जूनियर एशिया कप से पहले अपनी तैयारियों को और मजबूत कर सकी।

टीम बेंगलुरु में साई सेंटर पर मलेशियाई अंडर 21 टीम के साथ फ्रेंडली मैच खेलकर और भी ज्यादा प्रतिस्पर्धी अनुभव हासिल कर रही है। टीम के चयन पर बात करते हुए कोच सोयेज ने कहा, 'हम जूनियर एशिया कप के लिए चुनी गई टीम के संतुलन और गहराई से खुश हैं। खिलाड़ियों ने पिछले कुछ महीनों में कड़ी मेहनत की है और प्रतिबद्धता, अनुशासन और सुधार की जबरदस्त इच्छाशक्ति दिखाई है। चयन लगातार अच्छे प्रदर्शन, रवैये और दबाव में हमारे गेम प्लान को लागू करने की क्षमता के आधार पर किया गया है। एएचएफ जूनियर एशिया कप एशिया की प्रमुख जूनियर हॉकी प्रतियोगिताओं में से एक है, जो महाद्वीप की शीर्ष उभरती टीमों को एक बेहद प्रतिस्पर्धी माहौल में एक साथ लाती है। यह टूर्नामेंट भारत की युवा टीम को एशिया की सर्वश्रेष्ठ टीमों के खिलाफ खुद को परखने और अपनी मजबूत छाप छोड़ने का मौका देगा।

अंडर 20 एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिपः मोहम्मद अशफाक ने नेशनल रिकॉर्ड तोड़कर बनाई फाइनल में जगह

विश्व केसरी ■

यूजीन। भारत के मोहम्मद अशफाक ने वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 में पुरुषों की 400 मीटर दौड़ के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए अंडर-20 का नेशनल रिकॉर्ड भी ध्वस्त किया।

19 साल के अशफाक ने हीट 5 में 45.81 सेकंड का समय लेकर दूसरा स्थान हासिल किया और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। उन्होंने अप्रैल में बेंगलुरु में हुई अंडर 20 फेडरेशन कप में बनाए अपने ही 46.05 सेकंड के रिकॉर्ड को तोड़ा। सेमीफाइनल हीट 3 में, अशफाक ने 46.00 सेकंड का समय लेकर तीसरा स्थान हासिल किया और फाइनल में जगह बनाई।

अशफाक के साथी खिलाड़ी पीयूष राज हीट 6 में 47.78 सेकंड के समय के साथ पांचवें स्थान पर रहे और फाइनल राउंड में जगह बनाने से चूक गए। पुरुषों की हाई जंप में, बसंत ने 2.14 मीटर की जंप के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया और क्वालिफिकेशन ग्रुप ए में पांचवें स्थान पर रहे। के. अम्ब्रीश 2.05 मीटर की अपनी सर्वश्रेष्ठ जंप के साथ क्वालिफिकेशन ग्रुप बी में 12वें स्थान पर रहे और क्वालिफाई नहीं कर पाए। गौरतलब है कि किसी भी ग्रुप का कोई भी एथलीट 2.21 मीटर का ऑटोमैटिक क्वालिफिकेशन मार्क पार नहीं कर पाया। महिलाओं की शॉट पुट स्पर्धा में, अंशु फाइनल में जगह बनाने से चूक गईं। उन्होंने 15.24 मीटर की सर्वश्रेष्ठ थ्रो की, जो फाइनल क्वालिफिकेशन कटऑफ से 21 सेंटीमीटर कम थी। इस तरह वह ग्रुप ए में 9वें और क्वालिफिकेशन राउंड में कुल मिलाकर 14वें स्थान पर रहीं। भारत की तनु चौधरी को महिलाओं की 400 मीटर हर्डल्स हीट में निराशा हाथ लगी। वह 1:00.03 के समय के साथ पांचवें स्थान पर रहीं और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाईं। पुरुषों की 400 मीटर हर्डल्स में, अमित कुमार हीट में 54.01 सेकंड के समय के साथ सबसे पीछे रहे। पुरुषों की ट्रिपल जंप क्वालिफिकेशन में, धनुष राज और पी. रॉयशन फाइनल में जगह नहीं बना पाए। उन्होंने क्रमशः 14.71 मीटर और 15.20 मीटर की सर्वश्रेष्ठ दूरी तय की।

भारत की अंडर-20 मेंस टीम ने सिंगापुर को फ्रेंडली मैच में 1-0 से हराया

विश्व केसरी ■

नई दिल्ली। भारत की अंडर-20 पुरुष टीम ने गुरुवार को सिंगापुर के खिलाफ फ्रेंडली मैच में 1-0 से जीत हासिल की। बेंगलुरु के सेंटर फॉर स्पोर्ट्स एक्सीलेंस में सुमित शर्मा ब्रह्मचारीमयूम (5वें मिनट) ने विजयी गोल किया।

कोल्ट्स' (भारतीय टीम) एएफसी अंडर-20 एशियन कप चीन 2027 क्वालीफायर की तैयारी कर रहे हैं, जो 31 अगस्त से 6 सितंबर तक उज्बेकिस्तान में आयोजित होंगे।

इससे पहले, सोमवार को बेंगलुरु के सेंटर फॉर स्पोर्ट्स एक्सीलेंस में खेले गए दो फ्रेंडली मुकाबलों में से पहले मैच में भारत की अंडर-20 पुरुष टीम ने सिंगापुर को 3-0 से मात दी। इस मैच में ऋषि सिंह निंगथौखोंगजाम (45+2 मिनट) और सिंगामयूम शमी (63वें मिनट) ने शुरुआती दो गोल किए, जिसके बाद विपक्षी टीम ने एक 'ओन गोल' (83वें मिनट) किया।

भारत की अंडर-20 पुरुष टीम के हेड कोच महेश गवली ने सिंगापुर के खिलाफ दो फ्रेंडली मैचों के लिए 30 खिलाड़ियों की टीम में से अपनी शुरुआती प्लेइंग इलेवन चुनी है। कैंप शुरू होने से पहले ट्रायल में देश भर से कुल 102 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, जिनमें से इन 30 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। मूल्यांकन प्रक्रिया के बाद, गवली ने अंडर-20 पुरुष राष्ट्रीय टीम के साथ ट्रेनिंग के लिए 26 खिलाड़ियों को चुना।

एएफसी अंडर-20 एशियन कप क्वालिफायर के लिए 'ब्लू कोल्ट्स' की शुरुआती टीम को अंतिम रूप देने और उसकी घोषणा करने से पहले और मूल्यांकन किए जाएंगे। इस सीरीज से पहले, भारत और सिंगापुर आधिकारिक अंडर-20 पुरुष प्रतियोगिताओं में दो बार आमने-सामने आ चुके हैं। भारत ने एएफसी यूथ चैंपियनशिप में दोनों मैच जीते थे — 1966 में 4-1 से जीत और 1974 में खिताब जीतने वाले अभियान के दौरान क्वार्टर-फाइनल में पेनाल्टी शूटआउट में जीत।

दोनों टीमों ने 2017 में गोवा में दो अंडर-19 इंटरनेशनल फ्रेंडली मैच भी खेले थे, जिसमें भारत ने पहला मैच 7-2 से जीता था, जबकि सिंगापुर ने दूसरा मैच 1-0 से जीता था।

2027 क्वालिफायर में, हेड कोच महेश गवली की अगुवाई वाली 'ब्लू कोल्ट्स' टीम ताशकंद में सीरिया (31 अगस्त), उज्बेकिस्तान (3 सितंबर) और बांग्लादेश (6 सितंबर) का सामना करेगी।

सात साल किया पहले मेडल का इंतजार; शेन वॉट्सन की किताब ने बदला माइंडसेट, एशियन गेम्स में चमकने के लिए तैयार साहिल जाधव

विश्व केसरी ■

कोलकाता । 19 साल की उम्र में आर्चरी के खेल में रखा कदम। सात साल किया पहले मेडल का इंतजार। शेन वॉट्सन की किताब 'द विनर्स माइंडसेट' ने बदली मानसिकता। साहस और संघर्ष से भरी यह कहानी है भारत के साहिल जाधव की है, जो एशियन गेम्स 2026 में भारत की 12 सदस्यीय आर्चर टीम का हिस्सा होंगे।

साहिल ने आर्चरी के खेल में आने का फैसला 19 साल की उम्र में किया। हालांकि, शुरुआत में साहिल के हाथ लगातार निराशा लगी और उन्हें अपने नेशनल खिताब के लिए 7 साल का इंतजार करना पड़ा। हालांकि, संघर्ष से भरे वर्षों में साहिल के परिवार ने उनका भरपूरा साथ निभाया और बुरे वक्त में उनकी ढाल बनकर खड़े रहे। साई मीडिया के साथ बात करते हुए साहिल ने कहा, 'मैंने 19 साल की उम्र में काफी देर से आर्चरी शुरू की। हालांकि, मेरे परिवार ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। असल में, मेरे परिवार ने मुझसे ज्यादा त्याग किए हैं। मुश्किल भरे उन वर्षों में वे मेरे साथ खड़े रहे और हर तरह से मेरी मदद की। नेशनल लेवल पर अपना पहला मेडल जीतने में मुझे सात साल लग गए। यह सब्र और हिम्मत की परीक्षा थी क्योंकि हर साल मैं बहुत कम अंतर से चूक जाता था। साहिल जाधव की वर्षों की कड़ी मेहनत और लगन साल 2024 में रंग लाई। उन्होंने सीनियर नेशनल में अपने करियर का पहला मेडल गोल्ड के रूप में जीता। इसके बाद 2025 में हुए वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में व्यक्तिगत कैटेगरी में साहिल चैंपियन बने और उन्होंने टीम इवेंट में भी सिल्वर मेडल जीतकर इंटरनेशनल स्तर पर सफलता हासिल की। महाराष्ट्र के सातारा के रहने वाले साहिल इस साल शानदार फॉर्म में हैं। उन्होंने इस साल की शुरुआत में चीन के शंघाई में हुए आर्चरी वर्ल्ड कप 2026 के स्टेज 2 में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर अपने करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल की। उन्होंने कहा, 'जब मैं पोडियम पर खड़ा था, तो मुझे अपने माता-पिता, उनके त्याग और पिछले कुछ वर्षों में मैंने जो संघर्ष किया था, उन सबके बारे में ख्याल आया। साहिल ने बताया कि कैसे ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर की किताब द विनर्स माइंडसेट को पढ़ने के बाद उनकी मानसिकता में बदलाव आया। उन्होंने बताया, ' 'मैंने लगभग एक महीने पहले शेन वॉटसन की किताब 'द विनर्स माइंडसेट' पढ़ना शुरू किया था।

भारत-श्रीलंका टेस्ट मुकाबलों में सर्वाधिक विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज, लिस्ट में चार भारतीय शामिल

विश्व केसरी ■

नई दिल्ली। भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत 15 अगस्त से होनी है। शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ अपने दमदार रिकॉर्ड को इस सीरीज में भी बरकरार रखने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। आइए आपको उन पांच गेंदबाजों के नाम बताते हैं, जिन्होंने भारत-श्रीलंका के बीच हुए टेस्ट मुकाबलों में सबसे ज्यादा विकेट निकाले हैं।

मुथैया मुरलीधरन: टेस्ट क्रिकेट में 800 विकेट लेने वाले इकलौते गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए टेस्ट मुकाबलों में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। मुरलीधरन ने भारत के खिलाफ खेले 22 टेस्ट में कुल 105 विकेट निकाले हैं। इस दौरान वह 7 बार एक पारी में 5 विकेट लेने का कारनामा भी कर चुके हैं।

अनिल कुंबले: भारत की तरफ से श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड अनिल कुंबले के नाम दर्ज है। कुंबले ने श्रीलंका के खिलाफ खेले 18 टेस्ट मैचों में कुल 74 विकेट चटकाए। उन्होंने 4 बार एक पारी में 5 विकेट निकाले हैं। कुंबले का गेंदबाजी औसत 31.20 का रहा है।

आर अश्विन: भारत और श्रीलंका के बीच हुए टेस्ट मुकाबलों में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में आर अश्विन तीसरे नंबर पर काबिज हैं। अश्विन ने 11 टेस्ट मुकाबलों में श्रीलंका के खिलाफ 62 विकेट चटकाए। वह 3 बार एक पारी में 5 विकेट निकाल चुके हैं और श्रीलंका के खिलाफ 46 रन देकर 6 विकेट उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है।

हरभजन सिंह: श्रीलंका के खिलाफ 16 टेस्ट मैचों में 53 विकेट लेकर हरभजन सिंह इस लिस्ट में चौथे नंबर पर मौजूद हैं। हरभजन का इस दौरान गेंदबाजी औसत 39.77 का रहा और उन्होंने 2 बार एक ही पारी में श्रीलंका के पांच बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। हरभजन ने श्रीलंका के खिलाफ 62 रन देकर 7 विकेट चटकाए हैं, जो उनका बेस्ट प्रदर्शन भी है। कपिल देव: भारत को पहला विश्व कप दिलाने वाले कप्तान कपिल देव को अपने करियर के दौरान श्रीलंका के खिलाफ गेंदबाजी करना खूब रास आया।

मीराबाई चानूः बचपन में उठाए लकड़ियों के गट्ठर, ट्रक ड्राइवरों से लेनी पड़ी लिफ्ट, कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड की हैट्रिक लगातार रचा इतिहास

विश्व केसरी■

नई दिल्ली। कहते हैं कि जिंदगी का दूसरा नाम ही संघर्ष है। भारत के महिला वेटफिल्टर मीराबाई चानू शायद इस बात को बखूबी जानती और मानती भी हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में तीन गोल्ड मेडल जीतने वालीं दुनिया की इकलौती वेटलिफ्टर मीराबाई के लिए जिंदगी कभी आसान नहीं रही, हालांकि उन्होंने हर कदम और हर मोड़ पर संघर्ष का दामन थामे रखा और हर विपरीत परिस्थिति से निकलकर विश्वभर में अपने खेल के दम पर अलग पहचान बनाई।

मीराबाई चानू का जन्म 8 अगस्त, 1994 को मणिपुर के इंफाल के पास स्थित नोंगपोक काकचिंग में हुआ। मीराबाई एक साधारण परिवार से आती थीं, तो आर्थिक तंगी और शुरुआती जीवन संघर्ष से भरा रहा, हालांकि भारतीय महिला वेटलिफ्टर के अंदर बचपन से ही असाधारण शारीरिक क्षमता थी। वह लकड़ियों के भारी गट्ठर उठाया करती थीं। वह इन गट्ठर को उठाकर पहाड़ियों पर भी चढ़ा करती थीं। मीराबाई के परिवार का किसी भी खेल से दूर-दूर तक कोई नाता नहीं था, हालांकि बेटी की क्षमता को देखते हुए माता-पिता ने हमेशा मीराबाई को सपोर्ट किया।

मीराबाई की दिलचस्पी पहले तीरंदाजी में थी, लेकिन इंफाल के भारतीय खेल प्राधिकरण केंद्र में वेटलिफ्टिंग की ट्रेनिंग को देखकर इस खेल के प्रति मीराबाई की दिलचस्पी बढ़ी। उन्होंने जल्द ही इस खेल में अपना करियर बनाने की ठान ली। घरेलू प्रतियोगिताओं में मीराबाई की प्रतिभा का हर कोई कायल हो गया। मीराबाई ने साल 2008 में मणिपुर स्पोर्ट्स अकादमी में अपनी ट्रेनिंग शुरू की। घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उन्हें अकादमी तक पहुंचने के लिए रास्ते में बालू और पत्थर लेकर जाने वाले ट्रक ड्राइवरों से लिफ्ट मांगनी पड़ती थी।

नेशनल गेम्स में शानदार प्रदर्शन करने के बाद मीराबाई चानू ने साल 2014 में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में अपना डेब्यू किया। मीराबाई का डेब्यू शानदार रहा और उन्होंने 48 किलोग्राम वर्ग में सिल्वर मेडल अपने नाम किया, हालांकि यह उनके शानदार करियर की महज शुरुआत मात्र थी। साल 2017 में विश्व वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में मीराबाई गोल्ड मेडल जीतने में सफल रहीं। वह दो दशकों में यह गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय वेटलिफ्टर बनीं।

इसके बाद साल 2018 में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में मीराबाई का दमदार प्रदर्शन देखने को मिला और उन्होंने गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया। वहीं, 2021 में टोक्यो ओलंपिक में भी भारतीय महिला वेटलिफ्टर का जलवा देखने को मिला और उन्होंने 49 किलोग्राम वर्ग में सिल्वर मेडल जीता। वह ओलंपिक में सिल्वर जीतने वालीं पहली भारतीय वेटलिफ्टर बनीं। 2022 में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में मीराबाई चानू अपना दबदबा कायम रखने में सफल रहीं और उन्होंने लगातार दूसरे कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। हालांकि पेरिस ओलंपिक में जरूर मीरीबाई चानू के हाथ निराशा लगी और वह मेडल जीतने से चूक गईं। मगर कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में मीराबाई ने शानदार वापसी की और वह कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में लगातार तीन गोल्ड मेडल जीतने वाली दुनिया की पहली वेटलिफ्टर बनीं।

स्वात्वधिकारी राइवल्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक सुजीत कुमार द्वारा साई प्रींटिंग प्रेस, डी-85, सेक्टर 6 नोएडा,गौतम बुध्द नगर पिन कोड -201301 उ.प्र. से मुद्रित और मकान संख्या एन-58 जगतराम पार्क के सामने, लक्ष्मी नगर पूर्व दिल्ली-110053 से प्रकाशित
समाचार संपादक : चन्द्रमणी साव (पीआरबी एक्ट के अनुसार समाचार पत्र चयन एवं संपादन के लिए उत्तरदायी। नोट किसी भी विवाद के निपटारे के लिए न्यायक्षेत्र दिल्ली होगा) मोबाइल 9340573892 ई-मेल: vishwakesari2026@gmail.com,आर.एन.आई.नं. DLHIN/2015/61415